# हरियाणा विधान सभा

# की

# कार्यवाही

## 4 मार्च, 1987

खण्ड 1, अंक 6

अधिकृत विवरण

# विषय सूची

## बुधवार, 4 मार्च, 1987

पृष्ठ संख्या


| | |
|---|---|
| शोक प्रस्ताव | (6) 1 |
| तारांकित प्रश्न एवं उत्तर | (6) 3 |
| सदन की मेज पर रखे गये कागज पत्र | (6) 25 |
| वर्ष 1987–88 के बजट पर सामान्य. चची (पुनरारम्भ ) | (6)25 |
| बैठक का समय बढ़ाना | (6) 70 |
| वर्ष– 1987–88 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ.) | (6)70 |
| बैठक का समय बढाना | (6) 74 |
| वर्ष 1987– 88 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ ) | (6) 74 |

# हरियाणा विधान सभा

## बुधबार 4 मार्च, 1987

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर– 1, चण्डीगढ में प्रातः 9.30 बजे हुई । अध्यक्ष (सरदार तारा सिंह ) ने अध्यक्षता की ।

## शोक प्रस्ताव

**Mr. Speaker :** Honourable Members, now a Minister will make obituary references.

**सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला ) :** अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े खेद के साथ सदन को सूचित करना पड़ता हउ कि हमारे आनरेबल मैम्बर, श्री अमीर चन्द मक्कड की पूजनीय माता, श्रीमती जिन्दोबाई, का 28 फरवरी, 1987 को लगभग छह वर्ष की उम्र मे देहान्त हो गया है । वे बड़ी धार्मिक वृत्ति की थी । सामाजिक कार्यो में भी उनकी बड़ी रुचि थी । हमारे माननीय सदस्य श्री अमीर चन्द मक्कड जी ने सैशन के शुरू में ही लीव आफ ऐबसैस की परमिशन मांगी थी कि मेरी माता जी बीमार हैं । अकस्मात ही उनकी माता का देहान्त हो गया । मेरी भगवान से प्रार्थना है कि वे उनकी आत्मा को शान्ति दे और शोक संतप्त परिवार को इस घाटे को सहने की हिम्मत दें ।

**श्री लछमन सिंह (कालका ) :** स्पीकर साहब, चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला ने जो शोक प्रस्ताव हाउस में रखा है उसमें मैं भी अपने आपको शामिल करता है और परमात्मा से दुआ करता हूं कि श्री अमीर चन्द मक्कड को माता की आत्मा को शान्ति दे और उनके परिवार को इतनी शक्ति दे कि वे इस दुःख को बरदास्त कर सके । मैं भगवान से यह भी दुआ करता हूं कि वे उन्हें अपने' चरणों मैं जगह दें ।

**जन स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री ए० सी ० चौधरी ):** स्पीकर साहब, श्री मक्कड जी की माता के निधन पर इस हाउस में जो शोक प्रस्ताव रखा गया है, मैं मी उन भावनाओ के साथ अपने आप को जोड़ता हूं । मेरा उनके परिवार से बहुत ही करीब का सम्बन्ध रहा है । मक्कड साहब की माता 86 वर्ष की थी लेकिन नितनेम से पूजा पाठ करना उनकी जिन्दगी का मकसद रहा और मक्कड साहब ने भी एक आदर्श बेटे की तरह अपनी मां की सेवा की जिसके ऊपर हर बेटे को नाज हो सकता है । इस –दुनिया में मां से बढ़ कर कोई नेमत नहीं है और न ही मां दुबारा इस जीवन में मिल सेंकती है । जैसे कहा गया है कि गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता । इसलिए मां का दर्जा सब से बड़ा माना गया है । उनकी माता के निधन से मक्कड परिवार को बड़ी भारी क्षति हुई है, जिनकी पूर्ति नही हो सकती लेकिन हम लोक सद्भावना पेश करने के सिवाए और क्या कर सकते हैं । हम तो केवल शोक प्रस्ताव ही पेश कर सकते हैं और उस परिवार के साथ हमदर्दी दिखा सकते

हैं लेकिन साथ साथ यह भी हमारे लिए लाजमी है कि उस परिवार से सहानुभूति प्रकट करें । और परमात्मा से प्रार्थना करें कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और जो उनके पीछे परिवार रह गया है उसे इस दु:ख को सहन करने की शक्ति दे ।

**सेठ राम दास धमीजा (अम्बाला छावनी ) :** स्पीकर साहब, श्री अमीर चन्द मक्कड की माता जी के विषय में चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला ने जो शोक प्रस्ताव रखा है मैं भी उसके साथ अपने आपको शामिल करता हूं । आपको पता ही है कि माता का दर्जा सब से उत्तम होता है जिसका कोई भी अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता । जिस आदमी ने माता की सेवा की हो उसे ही पता होता है । मुझे इस बारे में पता है कि माता का कितना बड़ा दर्जा होता है । श्री अमीर चन्द मक्कड की माता की उम्र बड़ी जरूर थी लेकिन इस उम्र में उनका पूजा पाठ करना ही बड़ा महान कार्य है । वे 86 वर्ष की थी लेकिन उन्होंने जो उन्की सेवा की उसके लिए परमात्मा उन्हें लाभ दे । मैं भी इस दुख में अपने आपको शरीक करता हूं और जो उन्होंने शोक प्रस्ताव रखा है, उसकी ताईद करता हूं । भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को अपने चरणों में जगह दे और शोक संतप्त परिवार को इस दुख को सहन करने की हिम्मत दे ।

**परिवहन मंत्री (श्री अमर सिंह ) :** स्पीकर साहब, श्री सुरजेवाला जी ने जो शोक प्रस्ताव हाउस में रखा है, मैं भी उसमें अपने आपको शरीक करता हूं और उस प्रस्ताव की ताईद करने के

लिये खड़ा हुआ हूं । मक्कड साहब की माता जी धार्मिक वृत्ति की थीं और मां का दर्जा संतों ने परमेश्वर के बराबर का दिया है यानि परमेश्वर का ही रूप है । सन्तों ने यह भी कहा है कि जब भी समाज में मनुष्य किसी कठिनाई में आता है तो परमेश्वर का आवाहन कूरने की बजाये मां को याद करता है । मां और परमेश्वर को एक ही माना गया है । इसलिए मां का प्यार छिन जाना बहुत ही दुखदायी है । यह बात दूसरी है कि उनकी आयु 86 साल की थी लेकिन अब भी वे दोनों टाईम मन्दिर में जाया करती थी और पूजा पाठ किया करती थी । सेहत से वे ठीक थी लेकिन अचानक बीमार हो जाने के कारण वे मारे बीच से चली गई । आप जानते हैं कि इस संसार के चक्र से कोई बच कर नही जा सका । संतों ने कहा है कि जो आया है वह जायेगा, जो पैदा हुआ है वह मरेगा भी । वे अपने पीछे साधन सम्पन्न परिवार को छोड्कर गई हैं । मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वे उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और मक्कड परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे ।

**श्री अध्यक्ष :** आनरेवल मैम्बर्ज जो शोक प्रस्ताव चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला साहब ने रखा है, उसमें मैं अपने आपको शरीक करता हूं । सैशन से एक दिन पहले मुझे मक्कड साहब का लैटर आया था । उस खत से मक्कड साहब के मन की चिन्ता जाहिर हो रही थी और मैंने भी यह महसूस किया था कि उनकी चिन्ता मां के प्रति ठीक है। उनकी मां की उम्र 86 साल की थी

लेकिन घर में बुजुर्गो की गाइडैन्स हमेशा हमेशा के लिये चाहिए होती है । मक्कड साहब की अपनी माता के प्रति बड़ी अच्छी भावना थी । वे चाहते थे कि मैं अपनी मां की जितनी ज्यादा से ज्यादा सेवा कर सकूं करूं । इसीलिये उन्होंने हाउस से गैर–हाजिर रहने की रिक्वैस्ट की थी । मैं हाउस की फीलिंग और सिम्पथी मक्कड साहब की फैमिली तक पहुंचाऊंगा ।

अब मैं मैम्बर साहेबान से रिक्वैस्ट करूंगा कि वे खड़े होकर दो मिनट के लिए मौन धारण करें ।

(इस समय सदन ने दिवंगत महानुभावों के सम्मान में खड़े हो कर दो मिनट का मौन धारण किया । )

## तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

**श्री अध्यक्ष :** मैम्बर साहेबान अब सवाल होंगे ।

**Linking of Ambala Cantt. with Civil Air-service**

***1234. Seth Ram Dass Dhamija : Will** the Minister of State for Forests be pleased to state whether the question of linking Ambala Cantt. by Civil Air-service has been taken up by the Government with the Government of India; if so, the decision, if any, taken thereon ?

**Minister of State for Forests and Wild Life Preservation (Dr.** Om Parkash Sharma) : Yes. The matter is under consideration of the Vayudoot management.

**सेठ राम दास धमीजा :** स्पीकर, साहब, मन्त्री महोदय ने बड़ा अच्छा जवाब दिया । अगर वहां पुरू हवाई अड्डा बन जाता है तो हम ''घाटे में नही रहेंगे । हिमाचल, हरियाणा, पंजाब और यू० टी ० भी साथ ही लगते हैं । वहां पर सवारियों की कोई कमी नही रहेगी । डाक्टर ओमप्रकाश जी ने बड़ा अच्छा कदम उठाया है । मैं इम के लिये सरकार का धन्यवादी हूं ।

**Construction of I.T.I. Educational and Vocational Guidance Centre at Rakhi Shahpur**

***1248. Chaudhri Inder Singh Nain :** Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) whether then_ is any proposal under consideration of the Government to construct Educational and Vocational LTA. centre at Rakhi Shahpur of district Hisar; and

(b) if so, the time by which the aforesaid proposal is likely,to materialize togetherwith the estimated cost thereof ?

**उद्योग मंत्री (श्री श्री किशन दास ) :**

(ए ) हां । राखी शाहपुर में व्यावसायिक शिक्षा संस्थान के भवन का निर्माण किया जाना है ।

(बी ) निर्माण कार्य वित्त वर्ष 198 7— 88 में आरम्भ होने की संभावना है । भवन निर्माण पर 9 लाख रुपये खर्चा आने का अनुमान है ।

**चौधरी इन्द्र सिंह नैन :** स्पीकर साहब। मन्त्री जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया है । जो ट्रेनीज हूँ, वे स्कूल की बिल्डिंग में बैठतै हैं । मैंने शिक्षा विभाग से कहकर कुछ कमरे उनको दिलाये थे । मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि चूंकि वहां पर कमरे न होने की वजह से ट्रेनीज को काफी दिक्कत है इमलिये काम को जल्दी शुरू करवाने की कृपा करें ।

**श्री श्री किशन दास :** स्पीकर साहब, जमीन पंचायत ने दे दी है मगर अभी तक इन्तकाल नही चढ़ा है । इन्तकाल होते ही नक्शा बनवा कर जल्दी ही काम शुरू करवा दिया जायेगा ।

**श्री भले राम :** स्पीकर साहब, कुछ आई० टी ० आईज० ऐसी हैं जहां पर सभी ट्रेड्ज नही हैं । दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में लोगों को उनके लिये जाना पड़ता है । हमारे गोहाना में आई० टी ० आई० में बिजली मिस्त्री की, लोहार की और ट्रैक्टर रिपेयर की ट्रेड्ज नही है । मैं यह जानना चाहता हूं कि इस तरह की आई० टी ० आईज० में जहां पर बिल्डिग की कमी नही है, क्या वहां पर जुलाई से जब से यह सैशन शुरू होगा, इन ट्रेड्ज को देने की कृ पा करेंगे?

**श्री श्री किशन दास :** सर, वोकेशनल इंस्टीच्यूट्स अलग हैं और आई ० टी ० आईज ० अलग हैं । यह तो वोकेशनल सैन्टर की बिल्डिग का मामला है । इसके लिये अलग से नोटिस दे दें, बता देंगे ।

**श्री महेन्द्र प्रताप सिह :** स्पीकर साहब, मेरा सवाल हिसार का नहीं है मेरा तो फरीदाबाद का जनरल सा सवाल है, अगर आपकी इजाजत हो तो पूछ लूं ।

**श्री अध्यक्ष :** पूछ लें ।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : स्पीकर साहब, फरीदाबाद जिले में एक पाली गांव है । बहुत बड़ा गांव है । वहां के कुछ बच्चों की कुतुब मीनार के हादसे में मृत्यु हो गयी थी । सरकार ने वहां पर उन बच्चौं की स्मृति में एक स्मारक के रूप में आई ० टी ० आई ० चलायी थी । वहां पर बिल्डिग का अभाव है । दो साल सें वहां पर क्लासिज चालू हैं । अगर वहां पर जमीन वगैरा मुहैया करवा दें तो क्या सरकार वहां पर प्राथमिकता के आधार पर बिल्डिग बनवाने की कृपा करेंगी?

**श्री श्री किशन दास :** यह 'केस भिजवा दें, उसको देख लेंगे ।

**Surplus land with the Irrigation Department**

***1261. Shri Bhalle Ram :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether any surplus land is available with the Irrigation Department in the State ;

(b) if so, the total acreage of such land; and

(c) whether there is any proposal under consideration of the Government to allot such surplus land, if any available, to the Harijans in the State at the Government price ?

**Irrigation & Power Minister** (Chaudhri Shamsher Singh Surjewala) :

(a) Yes, Sir.

(b) 4010 Acres.

(c) Not yet.

**श्री भले राम :** स्पीकर साहब, मन्त्री जी ने यह बताया है कि नहर विभाग के पास 4010 एकड़ जमीन पड़ी हुई है । मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि सर्कलवाईज कितनी कितनी जमीन पड़ी हुई है, इसमें से कितनी बोली पर दे रखी है और कितनी लीज पर दे रखी है ।

**चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला :** अध्यक्ष महोदय, यह जो जमीन नहर विभाग के पास होती है यह इस शेप में नहीं होती जिस तरह से आम जमीन एक आदमी के पास होती है । यह जमीन दो तीन कारणों से अवेलेबल होती है । एक कारण तो यह होता हे कि जब कोई माईनर एबनडन हो जाये तो वह जमीन एक

स्ट्रिप के रुप में 4 फुट या 6 फुट चौड़ी होगी और उसकी लम्बाई कई मील होगी, वह विभाग के पास अवेलेवल होगी । दूसरा कारण आपको पता है क्योंकि आप भी किसान हैं । जब भट्ठे लगाते हैं या जब किसी नहर को पक्का करते हैं तो वह भट्ठे की जमीन नहरों के साथ साथ होगी तीसरे कई बार हम चौनल की कंस्ट्रक्शन के लिये भी जमीन ऐक्वायर करते हैं । नौर्मली तो अगर उसकी जरूरत न पड़े तो हम वापिस कर देते हैं, मगर हो सकता है कहीं पर यह वापिस न हुई हो । इस प्रकार की जमीन होती है । इस जमीन का 50 प्रतिशत भाग हरिजनों को हम ऐनुअल लीज पर देते हैं और 50 प्रतिशत दूसरे लोगों को देते हैं । इसमें से 40 प्रतिशत जमीन तो लीज पर देने के लिये अवेलेबल है बाकी जमीन पर हम फारैस्ट वगैरा लगा चुके हैं । यह इस जमीन की पोजिशन है ।

**श्री भले राम :** स्पीकर साहब, मन्त्री जी ने यह बताया है कि 50 प्रतिशत जमीन हम हरिजनों को लीज पर देते हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह जमीन लीज पर दे रखी है या नहीं? अगर हां, तो सर्कलवाईज बताने की कृपा करेंगे ।

**चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला :** 50 प्रतिशत जमीन हरिजनों को बिल्कुल दे रखी है । अगर यह कहीं पर जमीन अवेलेबल बतायेंगे तो हम वहां पर भी देने की कोशिश करेंगे । वैसे हमने फालतू ही जमीन हरिजनों को देने की कोशिश की है । इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है ।

**चौधरी अजमत खां :** स्पीकर साहब, मन्त्री जी ने बताया है कि भट्ठे वाली जमीन और दूसरी किस्म की जमीन, जैसे कहीं पर माईनर बन्द हो जाती है, ये लीज पर देते हैं । मेरे इलाके की कुछ जमीन भट्ठे के लिये ली गयी लेकिन आज तक जमींदारों को उसका मुआवजा नहीं दिया गया । अब वह जमीन फिशरीज डिपार्टमैंट को दे दी है । किसानों को उस जमीन का– मुआवजा भी न मिले और यह जमीन को दूसरे डिपार्टमैंट को ट्रांसफर भी कर दें, ऐसा तो नहीं होना चाहिये क्या उस जमीन को लोगों का मुआवजा दिलाने की कृपा करेंगे?

**चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला :** स्पीकर साहब, अजमत खां जी मेरे नोटिस में आज ही लाये हैं । हम जरुर मुआवजा दिलाने की कोशिश करेंगे ।

**श्री अध्यक्ष :** वह जमीन वापिस भी तो हो सकती है । जिस परपज के लिये ली गयी थी, वह तो पूरा नहीं हुआ । यह आप कृपया देख लें ।

**चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला :** अगर ऐसी कोई बात होगी तो हम पता कर लेंगे ।

**श्री भले राम :** स्पीकर साहब, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो लीज पर जमीन दी गयी है, वह कितनी है, कितने साल की लीज पर दी गयी है और' इसका रेट क्या है?

**चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला :** इसका रेट कोई नहीं है । एक सारन के लिये दी है । 50 प्रतिशत हरिजनों के लिये दे रखी है । हरिजनों में से कोई भी हरिजन बोली दे सकता है । 50 प्रतिशत दूसरे लोगों को देते हैं । रेट का तौ कोई सवाल ही नहीं है जो औक्शन है वह इस बात पर डिपैन्ड करती है कि जमीन कहां पर लोकेटिड है, कल्टीवेबल है या नही, न तो भट्ठे की जमीन काश्त. हो सकती है और न ही दूसरी जमीन जो एक लम्बे स्ट्रिप के रूप में होती है । वह काश्त हौ सकती है । हम 50 प्रतिशत जमीन हरिजनों को देते हैं । उसमें दूसरे आदमी बोली नहीं दे सकते ।

**चौधरी कुन्दन लाल :** मन्त्री जी ने यह बताया है कि 50 प्रतिशत जमीन हरिजनों को दी जाती है । मैं उनसे यह जानना चाहूंगा कि क्या बैकवर्ड क्लासिज या किसी अपंग वगैरा को भी ऐसी जमीन दी गयी है या नहीं? अगर दी गयी है तो कितनी दी गयी हे?

**चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला :** स्पीकर साहब, मुख्य मन्त्री महोदय ने पिछले दिनों बैकवर्ड क्लासिज के लिये पानीपत में एक कांफ्रैंस के बाद यह फैसला किया है कि पंचायत की जमीन का 10 प्रतिशत इनके लिये रिजर्व किया जाये । इरीगेशन महकमे की जमीन के बारे में तो कोई फैसला नहीं हुआ एं । इनकी यह बात ठीक है । इस फैसले की इस तरफ ऐक्सटैंशन कूरने में कोई दिक्कत नहीं हो सकती । मैं मुख्य मन्त्री जी से पूछ लूंगा । जैसा

वह कहेंगे, कर लेंगे । बाकी अपंगों के लिये जमीन देने में कोई रिजर्वेशन नहीं है । वह शायद इसलिये है कि उनके अन्दर खेती करने की क्षमता नहीं होती । उनके लिये नौकरियों में रिजर्वेशन जरूर है ।

**Cutting of wood**

***1268. @Chaudhri Roshan Lal Arya :** Will the Minister of State for Forests be pleased to state—

(a) the criteria, if any, adopted by the Government for allowing cutting of wood by the farmers from their own fields in those areas of the State where section 4 of the Forest Act is in force ; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to make relaxation in the said criteria, if any adopted, and if so, the details thereof ?

**वन तथा वन्य जन्तु परिरक्षण राज्य मंत्री (डा० ओम प्रकाश शर्मा ) :**

(क ) अधिसूचित क्षेत्र में, हकदार अपने घरेलू या कृषि प्रयोग के लिए बिना अनुमति के वृक्ष काट तथा छांट सकता है परन्तु उसे बिक्री के लिए वृक्ष काटने बारे उस क्षेत्र के संबंधित वन मण्डल अधि– कारी से अनुज्ञा पत् (परमिट ) लेना पड़ता है । संबंधित क्षेत्र से 10 वर्षीय कटाई वृक्ष योजना के अन्तर्गत वृक्ष काटने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

(ख ) जी हां । उपरोक्त मापदण्ड में सफैदा और पोपलर वृक्षों को काटने बारे कुछ ढील देने हेतु प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

**श्री भले राम :** स्पीकर साहब, कई बार लोग बिना गार्ड की इन्फर्मेशन के वृक्ष काट लेते हैं । गार्ड बिना यह देखे कि किसने पेड़ू काटा है, जिसको मर्जी आए नोटिस भेज देता है । इसको कोई चौलेन्ज भी नहीं कर सकता क्योंकि उसको इतनी पावर्ज हैं कि अगर कॉइ दूसरा भी काट ले तो किसी और को नोटिस भेज सकता है । क्या इस बात का कोई इलाज है कि सही आदमी को ही पकड़ा जाये ।

**डा० ओम प्रकाश शर्मा :** अगर कोई फौरेस्ट गार्ड गैर–कानूनी बात करता है तो मैं आनरेबल मैम्बर से यह कहूंगा कि वह सरकार के नोटिस में लाये । उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही अवश्य की जायेगी ।

**चौधरी साहब सिंह सैनी :** स्पीकर साहब, जो किसान खुद जमीन का मालिक है, उसको भी अपनी जमीन में से पेड़ू काटने के लिये परमिशन सरकार से या फौरेस्ट डिपार्टमैंट से लेनी पड़ती है । मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या उनको यह सहूलियत नहीं दी जा सकती कि वह बिना परमिशन के अपनी जमीन से पेड़ू काट सकें ।

**श्री अध्यक्ष :** सरकार का ला बना हुआ है ।

**चौधरी साहब सिंह सैनी :** जब जमीन का मालिक वह खुद है और पेड भी वह खुद लगाता है, क्या तब भी उसको परमिशन लेनी पड़ेगी?

**श्री अध्यक्ष :** ला क्लीयर है और उसके हिसाब से सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी ।

**श्री भले राम :** स्पीकर साहब, पिछली बार लोकदल वालों ने सरकार के तथा दूसरे लोगों के पेड़ू काट डाले थे । क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि डिपार्टमैंट ने कितने लोगों के खिलाफ कार्यवाही की और कितने लोगों को नोटिस दिए हैं?

**डा ० ओम प्रकाश शर्मा :** स्पीकर साहब, अगर कही रायट्स हो जाएं, कहीं ऐसे हालात हो जाएं जो कन्ट्रोल से बाहर हों और ऐसी स्थिति में किसी को आइ– डैन्टिफाई न किया जा सके कि किसने कत्ल किया है या नुकसान पहुंचाया है या वृक्ष काट दिया है तो किसी के खिलाफ ऐक्शन लेना कठिन होता है । अगर आन– रेबल मैम्बर साहब किसी को आइडैटीफाई करके आरोप लगाएं और हमारे नोटिस में लाएं तो जरूर कार्यवाही की जाएगी ।

**सिचाई तया बिजली मंत्री (चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला ) :** स्पीकर साहब, डा ० साहब जो कुछ कह रहे थे उसको मैं सप्लीमैंट करना चाहता हूं । स्पीकर साहब बहुत से केसिज में जहां यह पता लग गया कि किसने पेड़ काटे पे उनके

खिलाफ एफ०आई०आर० दर्ज की गई हैं और चालान पेश किए गए हैं । कलप्रिट्स के खिलाफ सरकार ने कार्यवाही की है और सख्त नोटिस लिया है ।

**चौधरी लीला कृष्ण :** स्पीकर साहब, मेरे हल्के में ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गई है । यह पहला मौका है कि मुख्य मन्त्री जी ने ऐसा सख्त कदम उठाया है ।

**श्री कंबल सिंह :** अभी मन्त्री जो ने बताया है कि पोपलर्ज और यूकालिप्टस के पेड़ू काटने के लिए रिलैक्सेशन दी जाएगी । क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किस टाइप की रिलैक्सेशन वे दे रहे हैं?

**Mr. Speaker :** Do you want to test his knowledge ?
(हंसी )

**चौधरी लाल सिंह :** स्पीकर साहब, किसान अपने खेत में से गेहू काट सकता है, मक्का काट सकता है, ईख काट सकता है और दूसरी फसलें काट सकता है लेकिन अपने खेत में से पेड़ नहीं काट पकता और अगर लकड़ी काटी जा सकतीं ऐं तो केवल जंगलात के कर्मचारियों से मिलकर काटी जा सकती है । क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इसका क्या कारण है?

**डा ० ओम प्रकाश शर्मा :** चौधरी लाल सिंह के नोटिस में अगर कोई ऐसी बात है कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है और जंगलात के कर्मचारी से मिल– कर पेड़ू काटते हैं तो

लिखित रूप में दें, हम उमकी इंक्वायरी करवाएंगे । स्पीकर साहब, मैं लाल सिंह जी को यकीन दिलाता हूं कि आपका जो एरिया है उसमें से काफी एरिया सैक्शन चार के अन्दर आता है और सरकार ने वहां पेड काटने पर प्रतिबन्ध लगाया है । आप हमारे नोटिस में केसिज लाएं! हम ऐक्शन लेगे ।

**श्री अध्यक्ष :** आनरेबल मैम्बर्ज, कांइडली रैलेवैन्ट क्वेशचंज पूछें, मजाक न बनाएं ।

**श्री निहाल सिंह :** स्पीकर साहब, बहुत सी पंचायतों को अपने यहां डिवैल्पमैंट करने में दिक्कत आ रही. है क्योंकि उनके पास फाइनैसं की कमी है और फाइनैसं. की कभी को पूरा करने के लिए वे पंचायत पेडू बेचन ( चाहती ट्रे ले किल फौरेस्ट डिपार्टनैंट उनको दरख्त बे चने की इजाजत नहीं दे रहा है । क्या मन्त्री महोदय अपने विभाग को यह आदेश देने की कृपा करेंगे कि जो पंचायत दरख्त बे चना चाहे उनक विभाग उन पंचायतों के रास्ते में रुक न डाले जिससे कि पंचायत अपने यहां डिवैल्पमैंट के काम कर सकें?

**डा ० ओम प्रकाश शर्मा :** इस तरह की इजा जत हम बिल्कुल नहीं देंगे क्योंकि हमने पर्यावरण संतुलन काय न रखना है । स्पीकर साहब । अगर पेड अंधाधुंध कटने शुरू हो जाएं और लगाये न जायें तो इससे संतुलन बिगड़ जाएगा । सरकार की नीति है कि संतुलन कायम रखा जाए ।

**चौधरी साहब सिंह सैनी** : स्पीकर साहब, सड़क के किनारे जिस जमी न पर पेडू लगे हुए हैं उसमें कुछ जमीन तो किसान की होती है और कुछ जमीन पी ० डब्ल्यू ०डी ० की होती है । फोरेस्ट डिपार्टमैंट वाले उन पेड़ों पर नम्बर लगा देते हें । किसान कहता है कि हमारी जमीन में पेडू आता है और पी ०डब्ल्यू०डी० वाले कहते हैं कि यह पेड सरकारी जमीन में है । पैमाइश करने कोई नहीं आता है और इस तरह से कि सान को परेशानी होती है ।

**Mr. Speaker :** Saini Sahab, again this is a question of fact.

**चौधरी साहब सिंह सैनी** : स्पीकर साहब, जंगलात के डिपार्टमैंट के आदमी किसानों को परेशान करते हैं 1

**श्री अध्यक्ष** : जो पेड इनकी हदूद में हैं उनको ये नहीं काटने देंगे ।

**चौधरी साहब सिंह सैनी** : स्पीकर साहब, निशानदेही के लिए मौके पर कोई नहीं आता और किसान परेशान हुआ फिरता है। क्या मन्त्री जी यह आश्वासन देंगे और कोई ऐसा प्रावधान करेगें कि इस मामले में किसान को कोई तकलीफ न हो?

**डा ० ओम प्रकाश शर्मा:** स्पीकर साहब, आनरेबल मैम्बर अगर कोई स्पैसिफिक केस मेरे नोटिस में लाएंगे तो हम उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ।

**चौधरी अजमत खां :** स्पीकर साहब, गांव के अन्दर ऐप्रोच रोडज हैं सरकार ने उस जमीन का किसान को अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया है ।

**Mr. Speaker :** Azmat Khan Ji, this is a separate question.

**चौधरी अजमत खां :** उस जमीन पर पेड़ू लगे हुए हैं और वे पेड़ू न तो जंगलात वालों ने लगाएं हैं और न किसान ने लगाएं हैं और वहां सैक्शन चार भी लागू नहीं है । व्यार किसान वहां पर पेड़ू काटता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाती है और जुर्माना होता है । स्पीकर साहब, किसान अपने काम के लिए वह पेड़ू काटता है जिस पर किसी का भी हक नहीं है । क्या मन्त्री जी ऐसा कोई आश्वासन देंगे कि उन किसानों के साथ कोई ज्यादती नहीं की जाएगी?

**डा ० ओम प्रकाश शर्मा :** स्पीकर साहब, अगर हमारे महकमे का कोई आदमी कोई गैर कानूनी हरकत करता. है तो हम उसके खिलाफ ऐक्शन लेंगे ।

**चौधरी लीला कृष्ण :** स्पीकर साहब, अक्सर किसी का डंगर छूटकर भाग जाता है और दरख्त को नुकसान पहुंचा देता है । क्या मन्त्री महोदय अश्योरैंस देंगे कि अगर किसी का डंगर किसी दरख्त को नुक्सान पहुंचाता है तो उसके मालिक के खिलाफ कोई ऐक्शन नहीं लिया जाएगा?

**श्री अध्यक्ष :** कई ऐसे मालिक होते हें जो जान बूझकर डंगर छोड़ देते हैं । यह कोई क्वैश्चन नहीं है ।

**चौधरी कुन्दन लाल :** स्पीकर साहब, जंगलात के कर्मचारी नाजायज तौर से किसानों से हरी बरसीम और छोले मुक्त लेना चाहते हैं और अगर कोई किसान उनको चारा या छोले नहीं देता है तो वे उन किसानों के खिलाफ झूठे केसिज बनाते हैं और उनको तंग करते हैं । क्या मन्त्री महोदय ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ ऐक्शन लेने की कृपा करेंगे?

**डा ० ओम प्रकाश शर्मा :** स्पीकर साहब, आनरेबल मैम्बर का सवाल मुझे समझ नहीं आया कि छोले और जंगलात का क्या ताल्लुक है?

**चौधरी कुन्दन लाल :** अध्यक्ष महोदय, आजकल जो हरा चारा पैदा होता है वे कर्मचारी अपने पशुओं के लिए किसानों से मुक्त लेना चाहते हैं और अगर उनको कोई किसान नहीं देता तो वे उन किसानों का चालान कर देते हैं । (शोर एवं व्यवधान ) ।

**डा ० ओम प्रकाश शर्मा :** स्पीकर साहब, चारे पर कोई पाबन्दी नहीं है । वह चारा ले सकता है । जहां तक सवाल छोलों का है वह छोले नहीं ले सकता । (हंसी एवं शोर तथा व्यवधान ) । सीकर साहब, कोई भी कर्मचारी रिश्वत के रूप मे कुछ नही ले सकता चाहे वह चारा हो या छोले हों । इस बारे में आनरेबल मैम्बर लिखित रूप में मुझे दे दें, मैं अवश्य कार्यवाही करूंगा ।

10.00 बजे

**सेठ राम दास धमीजा :** क्या मन्त्री महोदय यह बताएंगे कि इंडस्ट्रियल प्लाट्स में अगर कोई फलदार या दूसरे किस्म के दरख्त लगाये जाते हैं तो उस एरिया में फारेस्ट विभाग का क्या रोल होता है?

**डा ० ओम प्रकाश शर्मा :** सीकर साहब, जिस एरिया को सरकार की ओर. से इंडस्ट्रियल एरिया घोषित कर दिया गया हो उसका तो फौरेस्ट विभाग से कोई ताल्लुक नही होता ।

**Execution of water supply and sewerage works**

***1272. Shri Brij Mohan :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that water supply and sewerage works in various cities in the State are being executed by the concerned Municipal Committees as well as by the Public Health Department; and

(b) if so, whether there is any propsal under consideration of the Government to entrust such works to one single agency ?

**Minister of State for Local Government** (Shri Lachhman Dass Arora) :

(a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

**श्री बृज मोहन :** स्पीकर साहब, हमने यह महसूस किया है कि म्यूनिसिपल कमेटीज और पब्लिक हैल्थ वालो का आपस में कोई प्रीपर कोआर्डिनेशन नहीं है और दोनो में से कोई भी अपनी रिस्पोन्सीबिलिटी शेयर करने के लिये तैयार नही है । इसलिये मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हुं कि इन हालात में जब कि दोनों में से कोई भी एजैन्सी वाटर सप्लाई के बारे में और सीवरेज सिस्टम के बारे में अपनी रिस्पौन्सीबिलिटी शेयर करने के लिये तैयार नहीं है तो क्या यह काम किसी एक ही एजैन्सी को सौंप दिये जाने पर सरकार विचार करेगी ताकि शहरों में लोगों को इसके कारण किसी किस्म की दिक्कत का सामना न करना पड़े? आपसी कोआर्डिनेशन न होने के कारण शहरों में लोगों को काफी दिक्कत पेश आ रही है और गन्दगी फैल रही है ।

**श्री लछमन दास अरोडा :** स्पीकर साहब, म्यूनिसिपल कमेटीज और पब्लिक हैल्थ वालों में आपसी कोई मतभेद नही है । कोआर्डिनेशन वगैरह बिल्कुल ठीक है । केवल बात यह है कि म्यूनिसिपल कमेटीज के पास जे ०ई० लैवल के इंजीनियर्ज हैं और बडे कामों में बड़े इंजीनियर्ज की आवश्यकता होती है इसलिये ऐसे बड़े कामों को पब्लिक हैल्थ वालों को सौंपा जाता है । ऐसे बडे कामों को म्यूनिसिपल कमेटीज टेक ओवर नहीं कर सकतीं । जहां तक सीवरेज और वाटर सप्लाई के कामों को एक ही एजैन्सी को सौंपने का सवाल है । इस बारे में 1982 में कौंसिल आफ मिनिस्टर्ज में फैसला हुआ था और जिसको राष्ट्रपति महोदय की

ऐप्रूवल भी दी गयी थी लेकिन यह बोर्ड वाला काम किन्हीं कुछ फारमैलिटीज कमग्लीट न होने की वजह से सिरे नहीं चढ़ सका और यह फील किया गया कि यह स्कीम कोई खास लाभदायक नहीं होगी । अब यह मामला फिर दोबारा कैबिनेट के पास भेजने के लिये तैयार है ।

**चौधरी इन्द्र सिंह नैन :** स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूं कि किसी कस्वे में सीवरेज स्कीम चालू करते वक्त किन किन बातों को ध्यान में रखा जाता है? आया पापुलेशन या अदर फैक्टर्ज का इसके लिये कोई क्राइटेरिया फिक्स किया गया है कि इतनी पापुलेशन के बाद सीवरेज सिस्टम को चालू कर दिया जाएगा?

**श्री लछमन दास अरोडा :** स्पीकर साहब, इस वक्त हरियाणा के तकरीबन 81 टाऊन्ज हैं और सब में इस समय सीवरेज सिस्टम प्रोग्रैस पर चल रहा है और जहां जहां लोगों की तरफ से इसकी डिमांड आती है, वहां वहां हम इसको चालू कर देते हैं । जहां तक पापुलेशन के क्राइटेरिया का सवाल है इसके लिये हरियाणा के अन्दर ए, बी व सी कैटेगरीज की म्यूनिसिपल कमेटीज घोषित की हुई हैं । कैटे– गरीब के हिसाब से भी हम सीवरेज सिस्टम बिछाने का काम करते हैं और जहां जहां गलियों में सड़कों पर लोग इसके लिये जरूरत महसूस करते हैं, वे हमें अप्लाई करते हैं और हम वहां पर इंस्पैक्शन करके सीवरेज सिस्टम

चालू करवा देते हैं ताकि लोगों की सेहत पर किसी प्रकार का बुरा असर न पड़े और न ही गन्दगी फैले ।

**श्री बनारसी दास :** वाल्मीकि स्पीकर साहब, जब श्री ऐ०सी० चौधरी साहब के पास यह चार्ज था उस वक्त झज्जर में सीवरेज सिस्टम में बड़ा सुधार आ नग था और लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं थी लेकिन अब फिर वही हाल हो गया है । तो क्या अब यह काम म्यूनिसिपल कमेटीज से लेकर केवल पब्लिक हैल्थ वालों को दे दिया जाएगा ताकि इस में कुछ सुधार आ सके?

**श्री लछमन दास अरोड़ा :** स्पीकर साहब, ऐसी बात नहीं है जरूरत के मुताबिक सब जगह काम हो रहा है ।

**चौधरी लील कृष्ण :** स्पीकर साहब, म्यूनिसिपल कमेटीज के पास कोई साधन नहीं हैं और न ही उनके पास इफर नियर्ज ही हैं जिस वा से सीवरेज व वाटर सप्लाई के कामों में काफी दिक्कतें आ रही है और लोगों '' को इस बारे में बहुत सो शिकायते भी हैं । कथन यह काम केवल पब्लिक हैल्थ वालों को ही सौप दिया जाएगा ? हमने देखा भी है कि म्यूनिसिपल कमेटीज और पब्लिक हैल्थ वालों का आपसी तालमेल भी नहीं है जिस का असर लोगों पर पड़ता है और बस्तियों में गन्दगी फैलती है । इसलिये क्या सरकार मेरे इस सुझाव पर गौर करेंगी?

**श्री लछमन दास अरोडा :** स्पीकर साहब, इस सवाल का जवाब मैंने पहले ही सिंगला साहब के सवाल के जवाब में दे दिय हए कि म्यूनिसिपल कमेटीज के पास इंजीनियर्ज तो हैं लेकिन जे ०ई ० लैवल के इंजीनियर्ज हैं और बड़े कामो में बड़े इजी–नियर्ज की आवश्यकता रहती है । इसलिये बड़े कामो को पब्लिक हैल्थ वालों के पास ही दे दिया जाता है । दोनों एजैन्सीज का काम तकरी बन आपसी कोआर्डीनेशन से ही हो रहा है और होता भी है ।

**श्री लछमन सिंह :** स्पीँकर साहब, सभी जानते हैं कि हरियाणा के अन्दर आज के युग में सीवरेज की सख्त आवश्यकता है और इसके लिये पैसे की भी आवश्यकता है लेकिन म्यूनिसिपल कमेटीज के पास पैसा नहीं है । पानी की भी यहां पर कमी है जिस के कारण से फ्लश सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है । क्या मन्त्री महोदय इस बात का आश्वासन देंगे कि सीवरेज सिस्टम से पहले पानी का पूरी तरह से प्रबन्ध करवा देंगे ताकि पानी का सिस्टम शहरों में बेहतर हो । क्या ऐसा काम सरकार के द्वारा या किसी और एजैन्सी के द्वारा करवाने का प्रयत्न किया जाएगा? दूसरी बात यह है कि पापुलेशन की कंडीशन को मद्देनजर न रखते हुए क्या सीवरेज सिस्टम को भी चालू करने का आश्वासन मन्त्री महोदय देंगे जिसकी कि आज हरियाणा के अन्दर सख्त जरूरत है ताकि हरियाणा वासियों के रहन सहन को बेहतर बनाया जा सके?

**श्री लछमन दास अरोडा :** अध्यक्ष महोदय, जहां तक वाटर सप्लाई का सवाल है इस काम को सरक की ओर से प्राय रिटीरिज । इस वक्त हरियाणा के अन्दर 81 कस्बे हैं, जहां पर काम प्रोग्रैस में है और जहां जहां सरक इस बात की आवश्यकता महसूस करती है, वहां पर इस का प्रबन्ध कपार जा रहा है । पानी ' की उपलब्धि करवाने के बाद सीवरेज सिस्टम को पूरी तरह से और सतर्कता के साथ बिछाया जाएगा ताकि हरियाणा के अन्दर लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो । बहुत जल्द ही यह सारा काम सम्पूर्ण हो जाएगा ।

**चौधरी लाल सिंह :** स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि नारायणगढ में पहले सीवरेज का काम चल रहा था अब उसको बीच में क्यों रोक दया गया है?

**श्री लछमन दास अरोडा :** स्पीकर साहब, चौधरी लाल सिंह जी मुझे मिल कर बतला दें कि यह काम कहां पर रोका गया है तो हम इसको चालू करवा देगे ।

**श्री बृज मोहन :** स्पीकर साहब, जैसा कि मैंने पहले अपने सवाल में कहा कि म्यूनिसिपल कमेटीज और पब्लिक हैल्थ वालों का आपसी तालमेल ठीक नहीं है जिसके कारण लोगों को दिक्कतें हो रही हैं । इसलिये मेरे विचार में अगर म्यूनिसिपल कमेटीज से यह काम लेकर पब्लिक हैल्थ को सौप दिया जाए तो

उचित रहेगा तथा काम में तेजी और सुधार आएगा । चौधरी लीला कृष्ण जी ने भी इसी बात पर जोर दिया है । क्या मिनिस्टर साहज इस बात का आश्वासन देंगे क्योंकि ऐसा न होने के कारण गलियों की हालत खराब है?

**श्री अध्यक्ष :** मिनिस्टर साहब ने इसका जवाब दे दिया है कि यह मामला दोबारा कैबिनेट के पास जा रहा है ।

**श्री बृज मोहन :** सर, इस काम की जल्दी आवश्यकता है क्योंकि म्यूनिसिपल कमेटीज के पास इस काम को करवाने के लिये साधन नहीं हैं, इंजीनियर्ज नहीं हैं जिस की वजह से गलियों और स्लम्ज एरियाज में पानी खड़ा हो जाता है और पाईपस टूट जाती हैं । काम ढंग से नहीं हो रहा है क्योंकि गलियां पहले पक्की बन जाती हें और सीवरेज का काम जब बाद में करना पड़ता है तो गलियों को तोड़ना पड़ता है, जिस कारण से एरिया में काफी गन्दगी फैल जाती है । इसलिये मेरा सुझाव है कि सीवरेज और वाटर पाईप्स वगैरह कई काम को टेक ओवर करने के बाद ही गलियों को पक्का किया जाए तो बेहतर रहेगा । क्या मन्त्री महोदय इस बात के लिये आश्वासन देंगे?

**श्री लछमन दास अरोड़ा :** स्पीकर साहब, पहले कुछ हमारी डिफिकल्टीज होती थीं । अब पहले वाटर पाईप्स और सीवरेज का काम करवाने के बाद ही सड्कों को पक्का किया जाता है ताकि बाद में तोड़ फोड करने से किसी प्रकार की

असुविधाएं न हों और न ही वाटर सप्लाई और सीवरेज में खराबी आये ।

**मास्टर राम सिंह :** स्पीकर साहब, आज से 20 साल पहले म्यूनिसिपल कमेटीज की तरफ से जो कस्बो में ट्यूबवैल्ज लगाये गये थे, वे अब आबादी बढ़ जाने के कारण कम पड रहे हैं । क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए और ज्यादा ट्यूबवैल्ज लगाने की सरकार कोशिश करेगी ताकि लोगों को पानी पर्याप्त मात्रा में मिल सके?

**श्री लछमन दास अरोडा :** स्पीकर साहब, यह मसला हरेक टाउन में खड़ा हो गया है । जिस जिस कस्वे से इस प्रकार की मांग आएगी, वहां पर हम सर्वे करवा करके और ट्यूबवैल्ज लगाने की कोशिश करेंगे ।

**श्री नेकी राम :** स्पीकर साहब, मेरा रतिया हल्का घग्गर नदी के ऊपर बसा हुआ हैं और उस क गन्दा पानी घग्गर नदी के अन्दर पड़ता है जबकि कोई गन्दा पानी किसी नदी में नहीं डाला जा सकता । क्या सरक इस बात के लिये कोई ऐं सा प्रबन्ध करने का विचार रखती है कि कहीं और दूसरी जगह पर इस के लिये जमीन एक्वायर कर ली जाए और उस जमीन में रतिया कस्वे का पानी डाला जाए । अगर ऐसा सरकार का नजरिया है तो क्या सरक बताएगी कि वह जमीन कितनी है और कहां पर हे?

**श्री लछमन दास अरोडा :** स्पीकर साहब । जहां तक गन्दे पानी को – नाले में डाल ने का सवाल है । ऐसी कोई नौबत नही आती क्योंकि गन्दे पानी के तो खरीददार बहुत है । जो लोग सब्जियां उगाते हैं वे इस कं इस्तेमाल कर लेते है ।

**सेठ राम दास धमीजा :** स्पीकर साहब, अम्बाला कैट ' ए ' क्लास म्यूनिसिपल कमेटी है । वहां एक हाउसिंग बोर्ड कलोनी है जिसमें 1100 मकान हैं । इन मकानो में सीवरेज चालू है लेकिन सीवरेज के आगे जाने का रास्ता नहीं है । वह पानी दो क् मरों वाले मकानो में वापिस आज जाता है । क्या मन्त्री जी उसके निकास का कोई इन्तजाम करवाऐंगे?

**श्री लछमन दास अरोड़ा :** स्पीकर साहब, अगला सवाल धमीजा साहब का इसी बारे में है । बेहतर होगा कि ये अपना सवाल उस सवाल का नम्बर आने पर पूछ लें ।

**चौधरी लीला कृष्ण :** स्पीकर साहब, मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या रतिया में सीवरेज सिस्टम की डिस्पोजल बढ़ाई जाएगी? चौधरी नेकी राम जी ने भी यही सवाल पूछा था जोकि बिल्कुल सही था ।

**श्री लछमन दास अरोडा :** स्पीकर साहब, जहां पर भी सीवरेज की डिस्पोजल बढ़ाने की आवश्यकता है वहां हर जगह बढ़ाई जा रही है । आगे भी जहा से डिमांड आएगी वहां पर भी बढ़ाई जाएगी ।

**Transfer of Housing Board Colony in Ambala Cantt. to Municipal Committee**

***1235. Seth Ram Dass Dhamija :** Will the Minister of State for Local Government be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to hand over the Housing Board Colony in Ambala Cantt. to the Municipal Committee, if so, the time by which such a proposal is likely to be implemented ?

**Minister of State for Local Government** (Shri Lachhman Dass Arora) : The Housing Board Colony Ambala Cantt. has already been handed over to the Municipal Committee on 18th April, 1984.

**सेठ राम दास धमीजा :** स्पीकर साहब, कागजों में तो कार्यवाही ठीक है लेकि न अमली तौर पर कुछ नहीं है । अभी पिछले महीने की बात है कि ट्यूबवैल्ज बिजली का बिल देना था जिसे बडीं मुश्किल से मन्त्री जी ने पे करवाया । वहां पर 1100 मकान हैं लेकिन न वहां पर कोई सड़क है और न ही कोई नाली है । वहां पानी का भी इन्तजाम नहीं है । वहां पर सीवरेज चालू है ले किन उसक आगे निकास का इन्तजाम नहीं है । सीवरेज का पानी मकानों में वापिस अ जाता है । क्या मन्त्री जी सीवरेज के पानी की डिस्पोजल का कोई इन्तजाम करेंगे ?

**श्री लछमन दास अरोड़ा :** स्पीकर साहब, यह कम्पलेंट पहले भी हमारे पास आई थी । हमने ऐडमिाइ ऐडमिनिस्ट्रेटर अम्बाला म्यूनिसिपल कमेटी तथा हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों को

बुला कर मीटिंग की थी । उसमें इनकी सभी डिफीकल्टीज को डिस्कस करके फैसला कर दिया है और इनके सारे काम चालू करवा दिए है । हाउसिंग बोर्ड उसको एक दो महीने में क्लयिर कर देग ।

**सेठ राम दास धमीजा :** स्पीकर साहब, इसके लिए मैं मन्त्री जी का धन्यवादी हूं । दोनों महकमें चूंकि इनके पास हैं इसलिए अव मसला हल होने की आशा है धन्यवाद ।

**Construction of four lane road at Barwala**

***1249. Chaudhri hider Singh Nain : Will** the Minister for Public orks (B&R) be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct four lane road in Barwala Town in Hissar district; and

(b) if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to materialise togetherwith the estimated cost thereof ?

**लोक निर्माण मंत्री (श्री फूल चन्द ) :**

(क ) जी हां ।

(ख) यह कार्य 12.58 लाख की अनुमानित लागत पर पहले ही हाथ में लिया हुआ है । इसे वर्ष 1987–88 में पूर्ण कर लिये जाने की संभावना है ।

**चौधरी इन्द्र सिंह नैन :** स्पीकर साहब, चौधरी अमर सिंह जी के पास जब यह महकमा था उस समय इन्होंने यह काम शुरू करवाया था और मैं आशा करता हूं कि मुलाना साहब अब इसको कम्पलीट करवा देंगे । इसके लिए मैं इनका आभार प्रकट करता हूं । स्पीकर साहब, सड्कों का और पानी का कोई मेल नही है । अगर सड़क पर लगातार पानी खड़ा रहे तो सड़क की लाइफ आधी हो जाती है । क्या मन्त्री जी सड़क के दोनों तरफ नालियां बना क र पानी की निकासी का कोई प्रबन्ध करेंगे?

**श्री फूल चन्द :** अध्यक्ष महोदय, हम उस सड़क को ऊंची करके फोर लेनिंग कर रहे हैं । पानी तो उसको छू भी नहीं पाएगा ।

**Lining of Bntana Branch**

***1262. Shri Bhalle Ram :** Will the Minister for Irrigation & Power be pleased to state the date by which the lining of Butana Branch from RD-83 to 191 is likely to be completed ?

**Irrigation & Power Minister** (Chaudhri Shamsher Singh Surjewala) : The lining of Butana Branch from RD-83200-119810 (Tail) is proposed to be taken up during .1987-88 and will be scheduled for completion in the year 1989-90.

**श्री भले राम :** क्या मन्त्री जी बताएंगे कि इसके ऐस्टीमेट्स या दूसरे कागज पूरे कर लिए हैं और इस पर कितना खर्च आएगा?

**चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला :** अध्यक्ष महोदय, बुटाना ब्रांच एक कैरियर चौनल है जो रोहतक, भिवानी, महेन्द्रगढ़ और जीन्द जिलों. को पानी पहुंचाती है । भिवानी सब ब्रांच कैनाल पर काहनौर सब ब्रांच के द्वारा लाइनिंग करने का काम काफी पहले शुरू किया था । इसकी ऐप्रूवल 7–8–84 को कर दी थी । क्योंकि यह कैनाल बन्द नहीं होती और लगातार चलती है, इसमें 'क्लोजर बहुत ही रेयर है । इसलिये पैरलल चौनल लेकर उसमें पानी चला दिया जाए और इसको खाली रख कर पक्का कर दिया जाए । इसके लिए 97.43 एकड़ जमीन एक्वायर करनी थी । वह इनके जिले की जमीन थी । लोगों के नुमायंदों ने सरकार पर इस बात के. लिए दबाव दिया कि लोगों की जमीन ऐक्वायर न की जाए और चलती नहर को बैड. से पक्का किया जाए । अब इसको क्लोजर के दौरान पक्का किया जाएगा । इस पर 1987–88 में काम शुरू हो जाएगा और उससे– अगले साल काम पूरा हो जाएगा । इस पर कितना खर्चा आएगा, यह सूचना इस समय मेरे पास नहीं है जोकि मैं बाद में किसी समय बता दूगा ।

**श्री भले राम :** स्पीकर साहब, मन्त्री जी ने कोई सर्वे करवाया होगा । मैं जानना चाहता हूं कि हरियाणा में जितनी छोटी माइनर्ज हैं या बड़ी नहरे हैं उनमें से 1987– 88 में कितनी की लाइनिंग की जाएगी और इस काम के लिए बजट में कितना ' पैसा रखा गया है?

**चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला :** स्पीकर साहब, यह काम वर्ल्ड बैंक की स्कीम के तहत फेज 2 में चल रहा है । पूरी स्टेट की सूचना इस समय मेरे पास नहीं हे ।

**श्री कंबल सिंह :** क्या मन्त्री जी बताएंगे कि बरवाला ब्रांच की लाइनिंग करना उनके विचाराधीन हे?

**चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला :** स्पीकर साहब, जब बरवाला ब्रांच के. बारे में सवाल आएगा तो बता दिया जाएगा ।

**चौधरी कुन्दन लाल :** अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में तीन माइनर कच्ची हैं । ये हैं बूढ़ा खेड़ा, ' जगोली और सरफत । क्या इनको पक्का करवाएंगे, अगर हां तो कब तक करवा देंगे?

**श्री अध्यक्ष :** यह तो बुटाना माइनर के बारे में सवाल है, आप उसके बारे में सवाल पूछ सकते हैं ।

**श्री भले राम :** क्या मन्त्री जो बताएंगे कि इस नहर के अन्दर कितने क्यूसिक पानी चलता है और पक्की होने के बाद कितने पानी की बढ़ोतरी इसमें होगी?

**चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला :** स्पीकर साहब, मुझे अफसोस है कि यह सूचना इस वक्त मेरे पास नहीं है । आप कहें तो मैं कल को बता सकता हू ।

**श्री अध्यक्ष :** कोई बात नहीं ।

**Maintenance of roads in the cities**

***1273. Shri Brij Mohan :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that maintenance of city roads in the State is being done by different agencies e.g. P.W.D., Municipal Committee, Market Committees, Housing Board and HUDA; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to entrust maintenance of such roads to one single agency ?

**Minister of State for Local Government** (Shri Lachhman Dass Arora)

(a) Yes, sir.

(b) No, sir.

**श्री बृज मोहन :** स्पीकर साहब, म्यूनिसिपल कमेटीज, मार्किट कमेटीज, हुड्डा व हाउसिग बोर्ड भी पी ०डब्ल्यू०डाइ० के अलावा लडके बनाते हैं । आपने भी देखा होगा कि जो सड़क इन अलग अलग विभागों द्वारा बनाई जाती हैं उनकी ठीक तरह से मैटीनैस नहीं होती । जब ये खराब हो जाती हैं तो इन सड्कों की मुरम्मत की जिम्मेदारी कोई नही लेता । पी०डब्ल्यू०डी ० जो सड़कें बनाता है वे तो कुछ हद तक दूसरी संस्थाओं द्वारा जो सड़कें बनाई जाती है उनकी अपेक्षा ठीक होती हैं । यह भी ठीक है कि पी०डब्ल्यू ०डी० के पास फंडज अवेलेबल होते हैं ।

पी०डब्ल्यू०डी० को हजारों मीलों के एरिया को मेनटेन करना पड़ता है । इस बारे में मैं यह सुझाव दूंगा कि जिन अलग अलग संस्थाओं द्वारा शहरों के अन्दर सड़कें बनाई जाती हैं उनको पी ०डब्ल्यू०डी ० को हैड ओवर कर दिया जाये तो अच्छा रहेगा । इस बात की तरफ कोई ध्यान नही देता कि जव एक बार रोडज बन जाती हैं तो वह जल्दी ' जल्दी यानि हर साल क्यों टूटती रहती हैए और उन सड़कों पर हर साल रिपेयर क्यों होती रहती है? जो रिपेयर की भी जाती है वह ठीक नहीं होती । मैं मन्त्री जी से जानना चाहूगा कि क्या इन सड्कों को जो पी ०डब्ल्यू०डी ० के अलावा दूसरी संस्थाओं द्वारा बनाई जा चुकी है, उनको पी ०डब्ल्यू०डी० को हैण्ड ओवर कर दिया जायेगा ? इसके साथ ही साथ शहरों में जल आपूर्ति और सीवरेज आदि का कार्य भी किमी एक के सुपुर्द कर दिया जाये । मैं मन्त्री जी से इन सारी बातों के बारे में तफसील में जानना चाहूंगा ।

**श्री लछमन दास अरोडा :** जहां तक माननीय मैम्बर का सुझाव है कि वेरियस संस्थाओं द्वारा जो सडकें बनाई जाती हैं उनको पी ०डल्यू०डी० को हैण्ड ओवर कर दिया जाये, इस पर विचार किया जा सकता है । लेकिन सारी सड़कें पी० डब्ल्यू०डी ० द्वारा मेनटेन करना संभव नहीं होगा । जेंने नेशनल हाईवेज हैं वे कई शहरों में बाई पास होकर गुजरती हैं । उन नेशनल हाईवेज की रिपेयर नेशनल हाईवेज वाले ही करेंगे । इसी तरह से हुड्डा अपनी किसी कालोनी में या और कोई एजैसी अपनी कालोनी में

जिन सड्कों को बनाती है उन सड़कों को जब तक पी ०डब्ल्यू ०डी० को हैण्ड ओवर नही किया जायेगा तब तक उनकी मैटीनैस वे ही एजैसीज करेंगी जिन्होंने सड़कें बनाई हैं । सरकार का ऐसा कोई इरादा इस समय नहीं है कि ऐसा सड्कों की मुरम्मत का कार्य किसी एक ही एजैसी से कराया जाये ।

**चौधरी इन्द्र सिंह नैन :** स्पीकर साहब, गवर्नमैंट ने पालिसी डिसिजन लिया है कि मार्किट कमेटीज अपनी आमदनी का 40 परसैट पैसा पी ०डब्ल्यू०डी० के पास जमा करवायेगी । जो ''सी'' ग्रेड की मार्किट कमेटीज हैं उनकी आमदनी बहुत थोड़ी होती है और वे अपने एरियाज में भी सड़कें बनाने में असमर्थ होती हैं । अगर वे कमेटीज पी ०डब्ल्यू०डी० वालों को कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं इसलिए आप इस एरिया मं यह सडक बना दें तो पी ०डब्ल्यू ०डी० वाले कहते हैं कि यह एरिया कमेटी का है इसलिए हम यहां पर सड़क नही बना सकते । मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसे एरियाज में भी सड़कें बनवाने का प्रबन्ध करेगी?

**श्री लछमन दास अरोडा :** यह बात तो दुरुस्त है कि मार्किट कमेटी अपनी आमदनी का 40 परसैट पैसा पी ०डल्यू०डी ० के पास नई सड़कें बनवाने के लिए जमा करवाती हैं । जहां तक इन्होंने ''सी'' ग्रेड कमेटीज के एरियाज में सड़कें बनाने का जिक्र किया है, उस बारे में मैं इनको बताना चाहता हूं कि मार्किटिंग कमे– टीज के फण्डज का एक पूल बनाया हुआ है । .अगर कहीं

पर ऐसी दिक्कत आती है तो वहां पर इस पूल में से पैसा खर्च किया जा सकता हए ।

**लोक निर्माण मंत्री ( श्री फूल चन्द ) :** स्पीकर साहब, सड़कों की मैटीनैसं के लिए साधनों की कमी थी, इसलिए यह एक नीति निर्णय लिया गया था कि मार्किट कमेटीज पी ०डब्ल्यू ०डी ० को अपनी आमदनी का 40 परसैंट पैसा देंगी । उसी नीति के अनुसार यह भी फैसला किया गया था कि जो सड़कें मार्किट कमेटीज ने बनाई हुई हैं उनकी मैंटीनैंस पी ०डब्ल्यू ०डी० करेगी । जहां तक मण्डी के एरिया में नई सड़कें बनाने का सवाल है उसके लिए मार्किट कमेटी पर कोई पाबन्दी या बैन नहीं है । वे अपनी सुविधा के मुताबिक जहां तक चाहें सड़कें बना सकते हैं ।

**श्री निहाल सिंह :** स्पीकर साहब, मार्किटिंग बोर्ड अपनी आमदनी का 40 परसैट पैसा पी ०डब्ल्यू ०डी ० को जमा करवाता है । मैं जानना चाहूंगा कि अगर यह बोर्ड अपनी सुविधा के लिए पी डब्ल्यू ०डी ० से कोई नई सड़क बनवाना चाहे तो क्या उसको प्रायरिटीं दी जायेगी ?

**श्री फूल चन्द :** अभी तक तो हम पुरानी सड्कों की मैटीनैंस को ही अहमियत दे रहे हैं । जब नई सड़कें बनाई जाएंगी तो मार्किटिंग बोर्ड की बात की भी अहमियत जरूर दी जायेगी ।

**सेठ राम दास धमीजा :** कैबिनिट ने फैसला किया था कि सरकार वह सारी सड़कें बनायेगी जो पहले मार्किट कमेटी ने बनाई हैं । हमारे यहां 1977 से पहले कैन्टोनमैंट बोर्ड था । कैन्टोनमैंट बोर्ड अपने एरिया में कोई सड़क या मकान बनाने की इजाजत नहीं देता था । हमारी वहां की स्थिति सारे प्रदेश से अलग है क्योंकि सारे हरियाणा में सिर्फ अम्बाला में ही कैन्टोनमैंट बोर्ड है । जिस समय चौधरी बंसी लाल जी डिफैस मिनिस्टर थे उस समय उन्होंने कैन्टोनमैंट बोर्ड से 60 परसैंट एरिया लेकर वहां पर म्यूनिसिपल कमेटी बनवा दी थी और 40 परसैटं एरिया कैन्टोनमैंट बोर्ड के पास रह गया था । अम्बाला कैट की अब भी चार सहके ऐसी हैं जो बाहर से अनाज मण्डी और सब्जी मण्डी को लिंक करती हैं । 7– 8 साल पहले तक तो कैन्टोनमैंट बोर्ड सड़कें नहीं बनने देता था लेकिन जब से हमारी वहां पर म्यूनिसिपल कमेटी बनी है और वहां की मार्किट कमेटी भी अपनी आमदनी का 40 परसैंट पैसा पी ०डब्ल्यू०डी ० को दे रही है तो भी वे सड़कें क्यों नहीं बनाई जा रही?

**श्री फूल चन्द :** उन सड़कों पर अम्बाला कैट की म्यूनिसिपल कमेटी का हक है । अम्बाला की कमेटी तो ''ए'' क्लास कमेटी है । उसको सड़क बनाने के लिए दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योँकि उसकी आर्थिक स्थिति सारे प्रदेश की म्यूनिसिपल कमेटीज से नम्बर एक पर है ।

**श्री बृज मोहन :** स्पीकर साहब, अभी मन्त्री महोदय ने बताया कि मार्किटिग बोर्ड को नई सड़कें बनाने पर या रिपेयर पर कोई पाबन्दी नहीं है लेकिन असलियत यह है कि मार्किटिंग बोर्ड भी अपने एरिया में सड़कें पूरी नहीं बनाता । जब हम उनसे बात करते हैं. तो वह कह देते हैं कि हमारी भी कुछ लिमिट है । महोदय ने जो बात कही है कि उन पर 'कोई सड़क बनाने पर बैन नहीं है, यह बात ठीक नही है । श्री लछमन दास अरोडा ने मेरे मेन सवाल का जवाब तो दिया है लेकिन मैंने अपनी सप्लीमैंटरी में अर्बन एस्टेट कैं. बारे में जो सवाल किया था उसका जवाब नहीं दिया है । अध्यक्ष महोदय, आपने भी पेपरों में पढ़ा होगा और देखा होगा कि हुड्डा की सड्कों की बहुत बुरी हालत है । हमारे यहां जीन्द के अन्दर हुड्डा का कोई एक्सीयन नहों बैठता । वह रोहतक में बैठता है । हुड्डा ने जो कालोनीज बनाई है उनमें स्ट्रीट लाईट व सीवरेज आदि का उचित प्रबन्ध नहीं है । क्या मन्त्री महोदय इस तरफ ध्यान देंगे?

**श्री लछमन दास अरोडा :** स्पीकर साहब, अगर कोई ऐसी बात होगी तो उसका ख्याल रखा जायेगा ।

**श्री मोहन लाल पीपल :** अध्यक्ष महोदय, अभी मन्त्री महोदय ने बताया है कि अगर कोई मार्किट कमेटी नई सड़क बनाना चाहे तो बना सकती है । लेकिन मैं मन्त्रो जी को बताना चाहता हूं कि ऐसा बिल्कुल भी नही है । मेरे हल्के में एक गांव के अन्दर मार्किट कमेटी ने सड़क बनाने के लिए पी ०डब्ल्यू ०डी ०

को एक स्कीम भेजी थी । उस स्कीम को पी ०डब्ल्यू ०डी ० वालों ने पास नहीं किया जिसके कारण आज तक वह सड़क बन नहीं पाई है जबकि वहां की मार्किट कमेटी 40 पारसैट पैसा बाराबर का दे रही है । मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या वहां पर वह सड़क बनाई जायेगी?

**श्री फूल चन्द :** अध्यक्ष महोदय, मैंने तो ठीक कहा है कि वे नई सड़क बनाना चाहें तो बना सकते हैं । उन पार कोई बैन नही है । हमने तो केवल एक नीति निर्धारित की हुंई है कि मार्किट कमेटी अपनी आमदनी का 40 परसैट पैसा पी० डब्ल्यू ०डी ० के पास जमा करवाने ।

**श्री अध्यक्ष :** मैम्बर साहेबान, को शायद मालूम होगा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की भी एक जजमैंट है । इसलिए इसमें थोड़ी बहुत रुकावट वगैरा हो सकती है ।

**चौधरी लीला कृष्ण :** स्पीकर साहब, मार्किट कमेटी तो यह कहती है कि हम एक इंच सड़क नहीं बया सकते । क्या मिनिस्टर साहब कैटेगरीकली कहेंगे कि मार्किट कमेटी सड़क बना सकती हे?

**श्री अध्यक्ष :** इसका जबाब तो ऐग्रीकल्चर मिनिस्टर देंगे, पी ०डब्ल्यू ०डी ० मिनिस्टर नहीं दे सकते ।

**चौधरी लीला कृष्ण :** स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से ऐग्रीकल्चर भिनिस्टर से यह पूछना चाहता हूं कि क्या मार्किटिंग

बोर्ड या मार्किट कारेटीज ऐपी सड्कों को बना सकती हैं जो परचेज सैन्टर्ज को ज्वाइन करती हें?

**कृषि मंत्री (श्रीमती पसली देवी ) :** स्पीकर साहब, मार्किट कमेटी' या मार्किटिंग बोर्ड पर सड़क बनाने की कोई पाबन्दी नहीं है लेकिन सड़कों का 40 परसैंट पैसा पी०डब्ल्यू०डी ० को चला जाता है । चूंकि बजट में गुंजाइश नही रहती इसलिए वे सड़कें बना नहीं पाते ।

**बहिन शांति देवी :** आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह बड़ी अच्छी बात हुई कि एक ही प्रश्न पर सभी मंत्रियों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं । इससे बातों बातों में सभी की तसल्ली हो जाएगी । स्पीकर साहब, ऐसा है कि मार्किट कमेटी का 40 परसैंट पैसा तो पी०डब्ल्यू ०डी० को मिल जाता है और 30 या 40 प्रतिशत मार्किटिंग बोर्ड को अपने कामों में खर्च के लिये मिल जाता है । कोई 30 परसैटं पैसा बचता है जिससे मार्किट कमेटी कुछ काम कर सकती थी लेकिन चूंकि रोक लग गई है कि बाहर की सड़क न बनाए बल्कि मार्किट कमेटी के अन्दर की सड़क बनाएं इसलिए काम नहीं हो पाता । इसके अलावा अगर ऐस्टिमेट बनाकर भेजते हैं तो वह पास होकर नहीं आता । मैं नहीं समझती कि अगर सड़कें ही मार्किट कमेटी नहीं वना सकती तो मार्किटिंग बोर्ड के दफ्तर उनमें एस०ई०, ऐक्सीयन और जे०ई० आदि वहां किस लिए बैठे हैं? जो सड़कें मार्किटिंग बोर्ड ने बनाई थीं उनके बारे में यह कहा जाता है कि ये कमेटी की थीं ये तो गलती से बन गई । अब

उन्हें न मार्किट कमेटी वाले बनाते हैं और न नगरपालिका वाले बनाते हैं । जब मिनिस्टर साहब से इस बारे में पूछा जाए तो ये कहते हैं कि मार्किट कमेटी की सडके है इन्हें हम नहीं बना सकते क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं । तो ये सड़कें कैसे बनेगी? ऐसा लगता है कि अब तो टूटी हुई सड्कों पर ही चलना होगा । यह मन में सोच कर बहुत ही अधिक दु:ख होता है और इन टूटी सड्कों को देख कर तथा इन पर चलने वाले परेशान लोगों को देखकर तो लज्जा अनुभव होने लगती है । क्या मन्त्री जी यह आश्वासन देंगे कि ऐसी सड़कें ठीक होंगी और नई सड़कें भी बनेंगी?

**श्री लछमन दास अरोडा :** स्पीकर साहब, फंडज के मुताबिक सारी सड़कों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं ।

**श्री कंवल सिंह :** स्पीकर साहब, ऐग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पर टैक्स लग कर यह पैसा आता है और यह देहात में द्राई लगना चाहिये । क्या मिनिस्टर साहब इसका आश्वासन देंगे.

**श्री फूल चन्द :** स्पीकर साहब, अभी अभी बहिन शांति देवी जी ने कहा कि अब तो टूटी हुई सड़कों पर ही चलना पड़ेगा । ऐसी बात नहीं है । आदरणीय मुख्य मन्त्री जी ने निर्णय लिया है कि सबसे पहले रोडज की रिपेयर की जाएगी । 8– 9 करोड़ रुपया टोटल बजट में से इम काम के लिए रखा गया है । इसके अलावा आदरणीय प्रधानमन्त्री जी ने जो 403 करोड़ रुपये की

सहायता दी है उसमें से भी 5 करोड़ रुपया केवल सड़कों के लिए ऐलोकेट किया गया हए । सभी खराब सड्कों की मुरम्मत का काम तेजी से जारी है । जहां तक शहरों की सड्कों का संबंध है, मुख्य मन्त्री जी ने डिवैल्पमैंट प्लान के तहत हर म्यूनिसिपल कमेटी को काफी सहायता दी है । वह पैसा सड़कों की मुरम्मत! ड्रेनेज और सीवरेज आदि पर लगाया जाएगा । जैसे ही और साधन उपलब्ध होंगे सड्कों की मुरम्मत की ओर और विशेष ध्यान दिया जाएगा चाहे सड़कें शहरों की हों या देहातों की हों ।

**चौधरी शकरूल्ला खां :** स्पीकर साहब, मेरे हल्के में एक सड़क है जमालगढ– खम्मी मण्डी पुन्हाना–दलावास । वह मार्किट कमेटी से बनवानी थी । जब मार्किट कमेटी से बनाने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा कि पी०डब्ल्यू०डी ० बनवाएगी । जब पी०डब्ल्यू०डी० से कहा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसा जमा करवा दो तब हम बनवाएंगे 9– 11– 1988 को 12 लाख रुपया जमा करवा दिया था लेकिन अभी उस सड़क का काम शुरू नहीं हुआ । पी ०डब्ल्यू०डी० वालों से जब पूछते हैं तो कहा जाता है कि अभी चूंकि ऐस्टिमेट ऐप्रूवत्न के लिए गया हुआ है इसलिए सड़क नहीं बन सकती । मैं मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा कि उस सड़क को कब तक बनाया जाएगा?

**श्री फूल चन्द :** स्पीकर साहब, माननीय सदस्य किसी नई सड़क की चर्चा कर रहे हैं । यह बात ठीक है कि जब तक ऐस्टिमेट मंजूर नहीं होगा तब तक काम शुरू नहीं किया जा

सकता । जो इन्होंने 40 परसैटं रुपया जमा करवाया है वह उस नीति के तहत जमा करवाया है जिसके तहत हम सड़क की मुरम्मत कर रहे हैं ।

**श्री भले राम :** स्पीकर साहब, यह फार्मर्ज का पैसा होता हए । कई जगह परचेज लैटर का बहुत ज्यादा डिस्टैस नहीं होता । केवल 3–4 किल्ले का या फर्लान्ग डेढ़ फर्लान्ग का फासला होता है । ऐसी सड़कों को डिस्ट्रिक्ट प्लान में ले लेना चाहिए । जो 6 करोड़ रुपया दिया गया है उसमें से कुछ ईटों का इन्तजाम करके इस काम को किया जाना चाहिए । क्या मन्त्री जी ऐसा करने पर विचार करेंगे?

**श्री फूल चन्द :** स्पीकर साहब, जहां तक मैं समझता हूं डि स्ट्रिक्ट प्लान पैसा तो गलियों, स्कूलो और तालाबों आदि की मुरम्मत तथा डिवैल्पमैंट के दूसरे कामों के लिए है । सड़कों की मुरम्मत का जहां तक संबंध है, उसके लिए मुख्य मन्त्री जी ने हाल ही में केन्द्र सरकार से बात की है । वे तो कहते है कि हरियाणा के हर गांव में चूंकि सड़क पहुंची हुई हए इसलिए ज्य पैसा नही दिया जा सकत लेकिन हमारे मुख्य मन्त्री जी ने सड्कों की रिपेयर पर ज्यादा बल दिया है और नई सड़कों की प्रायरिटी कम रखी है ।

**Mr. Speaker :** Question Hour is over.

## सदन की मेज पर रखे गए कागज पत्र

**श्री अध्यक्ष :** अब एक मिनिस्टर साहब टेबल औफ दी हाउस पेपर ले करेगे ।

**Irrigation and Power Minister** (Chaudhri Shamsher Singh Surjewala) : Sir, I beg to lay on the Table-

1. The General Administration Department notificationNo. GSR 11/Const/Art. 320/Amd. (1)/87, dated the 18th February, 1987 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) First Amendment Regulations, 1987 as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

2. The Statement showing loans raised by the Haryana State Electricity Board upto 15.1.1987 for which the State Government stood guarantee for repayment thereof as required under section 66 of the Electricity (Supply) Act, 1948.

3. The 19th Annual Statement of Accounts for the year 1985-86 of the Haryana State Electricity Board as required under section 69 (4&5) of the Electricity (Supply) Act, 1948.

4. The Annual Administration Report of the Haryana State Electricity Board for the year 1984-85 as required under section 75 (1) of the Electricity (Supply) Act, 1948.

## वर्ष 1987– 88 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ )

**श्री अधयक्ष :** प्रौनरेबल मैम्बर्ज, अब 1987–88 के बजट पर जनरल डिस्कशन

**चौधरी साहब सिंह सैनी (थानेसर ) :** अध्यक्ष महोदय, बजट पर कल से चर्चा चल रही है और मैं कल इस विषय पर बोल रहा था । सरकार की तरफ से हमारे समाज के अलग अलग वर्गों को जो सहूलियतें प्रदान की गई हैं उनकी मैं चर्चा कर रहा था । सरकार ने व्यापारी वर्ग को जो सहूलियतें दी हैं, बैकवर्ड क्लास के लोगों को जो सहूलियतें प्रदान की हैं और किसानों को जो सहूलियतें प्रदान की हैं उनके बारे में मैंने चर्चा की थी । आज मैं उन सहूलियतों की चर्चा करूंगा जो सरकार ने अपने कर्मचारियों को दी हैं । (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए । ) उपाध्यक्ष महोदय, सरकार' ने अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए भारत सरकार के चौथे पे कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है उसे 1–1– 1988 से लागू किया है । बजट स्पीच के पृष्ठ 28 पर लिखा है कि 31 मार्च, 1987 तक का पैसा कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खातों में जमा होगा और 1 अप्रैल, 1987 से बढ़ा हुआ वेतन दिया जाएगा ' इसके साथ साथ ऐम्पलाइज को स्वास्थ्य के बारे में भी काफी सहूलियतें दी हैं । सरकार ने पिछले साल फैसला किया था कि हर कर्मचारी को 150 रुपये साल में मैडिकल भत्ता दिया जायेगा । यह इसलिये किया गया था कि कुछ ऐमप्लाइज तो मैडिकल की री–इम्बर्समैंट करवा लेते थे और कुछ बिल्कुल नही ले पाते थे । इसलिये सभी कर्मचारियों को फायदा पहुंचाने के

लिए ऐसा किया गया था । ऐसा करारे के बाद कुछ कर्मचारियों की यह शिकायत आयी कि उन्हें इस स्कीम से लाभ नहीं हे । इसलिये इस साल के बजट में वित्त मन्त्री जी ने यह औप्शन दे दी कि अगर कोई कर्मचारी री–इम्बर्समैंट लेना चाहता है वह ले सकता है और अगर कोई 150 रुपये साल का मैडिकल भत्ता लेना चाहता है तो वह ले सकता है । सरकार ने आल्टरनेटिव सहूलियतें प्रदान कर दी हैं । इन सहूलियतों के प्रदान करने से 91 लाख रुपये का अतिरिक्त भार सरकार को उठाना पड़ेगा । इसी प्रकार से अपने ऐमप्लाइज को पैन्शन के बारे में भी काफी सहूलियतें दी हैं । उपाध्यक्ष महोदय भारत सरकार ने पैन्शन के बारे में कुछ सुधार किये हैं । जिन ऐमप्लाइज के सेवा निवृत्ति के समय औसत इमोलूमेंटस नौ सौ रुपये तक थे, उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था, उन्हें पैन्शन में नुक्सान हुआ था । इसलिए हमारे वित्त मन्त्री महोदय ने इस बजट के पेज 29 पर यह सहूलियत प्रदान की है कि जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं वे राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के तहत दी गई पैन्शन भी ले सकते हैं और अगर वे इसे नहीं लेना चाहते हैं तो भारत सरकार के नियम के अनुसार भी ले सकते हैं । हमारी सरकार ने यह आल्टरनेटिव सहूलियत प्रदान की हए । इस प्रकार की सहूलियतें कर्मचारियों को मिलने के बाद बहुत ही लाभ होगा । हमारी सरकार ने एक और भी बड़ा भारी कदम उठाया है । जो रकम कर्मचारियों के प्रोविडैन्ट फन्ड में जमा होती है उस पर 9 परसैन्ट व्याज दिया जाता था परन्तु अब उस पर 12 परसैन्ट व्याज करें

दिया है । इस प्रकार से खजाने पर 7.65 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा । ऐसा करने से हमारे कर्मचारियों को काफी लाभ होगा । उपाध्यक्ष महोदय इतनी सहूलियतें मिलने के बाद हमारे कर्मचारियों को खुशी होनी चाहिये लेकिन बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे विरोधी पक्ष के भाई हमारे कर्मचारियों को वहका कर उन्हे ऐजीटेशन करने के लिये बाध्य कर रहे हैं । उन से कुछ ऐमप्लाइज गुमराह भी हो रहे हैं और वे उस दिशा में चल रहे हैं । मैं आपके द्वारा अपने प्रदेश के ऐमप्लाइज से कहूंगा कि वे ऐसा कदम न उठायें और जो सरकार ने उन्हें फायदे दिये हैं उनका पूरा पूरा फायदा उठायें और अपोजिशन के साथियों के बहकावे में न आयें, ऐजीटेशन न करें । अगर कर्मचारी सरकार के खिलाफ कोई ऐसा काम करेंगे तो उन्हीं का नुक्सान होगा । सरकार चौथे आयोग की रिपोर्ट लागू करने वाली है । हमारी सरकार ने मुख्य सचिव के नेतृत्व में कमेटी बनायी है जो जल्दी ही अपनी रिपोर्ट देगी । बार बार मुख्य मन्त्री जी ने और दूसरे सदन के नेताओं ने यह आश्वासन दिया है कि ऐमप्लाइज को पूरा लाभ होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में जो बीस सूत्रीय कार्यक्रम चल रहा है अब मैं उसके बारे में चर्चा करना चाहता हूं । इस कार्यक्रम के तहत जहां हमारे प्रदेश के हरिजन भाइयों को फैसिलिटीज मिल रही हैं उसके साथ साथ हमारे गांवों का विकास भी हो रहा है । गांवों में जो बेरोजगार आदमी हैं चाहे वे हरिजन

हैं या बैकवर्ड हैं उन्हें कारोबार मिल रहा है, चाहे वह एन० आर० ई ० पी० की स्कीम के तहत या आर० एल ० ई० जी० पी० स्कीम के तहत मिल रहा है । हरिजन चौपालों और गलियों को बनाने के लिये सरकार ने काफी पैसा दिया है । इस तरह से हमारे देहात आगे बढ़ रहे हैं और लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मुहैया किया जा रहा है ।

उपाध्यक्ष महोदय, आपको पता होगा कि इन्दिरा आवास योजना के तहत भारत सरकार से पैसा मिलता है । हरिजनों को जहां भी मकानों की जरूरत होती है वहां पर बीस मकान की बना कर दिये जाते हैं । दो लाख रुपए में बीस मकान बना कर दिए जाते हैं । उस मकान में एक कमरा, किचन, फलश की लैटरीन और आगे बरामदा बना कर दिया जाता है । यह मकान मुक्त में दिया जाता है । ऐसी सभी योजनाओं से हमारे हरिजन वर्ग के लोगों को फायदा पहुंच रहा है । बीस सूती कार्यक्रम से हमारे प्रदेश के कमजोर वर्ग के लोगों को भी लाभ पहुंच रहा है ।

इसके अतिरिक्त हमारी सरकार ने एक और बात भी की है जिसका इस बजट में भी जिक्र है । हमारी सरकार ने डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड बनाया है । योजना का विकेन्द्रीयकरण किया है । सरकार जो निम्न क्षेत्रो में खर्चा करना चाहती है उनके लिए डिस्ट्रिक्ट पर प्लानिंग बोर्ड बना दिया है । मन्त्री महोदय उसके चेयरमैन हैं और डी ० सी ० वाइस चेयरमैन हैं । बी ० डी ० ओ० और म्यूनिसिपल कमेटी के ऐडिमिनिस्ट्रटर मैम्बर हैं । साथ में उस

हल्के का एम० एल० ए० भी उसमें होता है । जिस क्षेत्र में प्रायरिटी देने की जरूरत होती हए वहां पर पैसा दिया जाता है । इममें 2० प्रतिशत पैसा हरिजनों की भलाई के लिये होगा जो एं हरिजन बस्तियों में स्लम को खत्म करने के लिए और गलियां आदि बनवाने के लिए होगा । डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर पता होता है कि किस को किस चीज की जरूरत है और कौन सा काम प्रायरिटी पर होना है। ऐसा करके सरकार ने काफी बड़ा काम किया है । ऐसा करने से हमारे प्रदेश का और ज्यादा विकास होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट में इतनी ज्यादा सहूलियतें प्रदान करने के बावजूद भी वित्त मन्त्री जी ने जनता पर कोई टैक्स नहीं लगाया है । योजनाओं के लिए भी काफी पैसा मुकर्रर किया है । इन शब्दों के साथ मैं हाउस का ज्यादा समय न लेते कुछ इन बजट प्रस्तावों की पुरजोर ताईद करता हूं ।

**चौधरी हुक्म सिंह (साल्हावास ) :** डिप्टी स्पीकर साहब, दो तारीख को हमारे वित्त मन्त्री चौधरी कटार सिंह जो ने सन 1987–8 8 के बजट अनुमान पेश किये हैं । मैं उनका समर्थन करने के लिए खडा ददुआ हूं । उपाध्क्ष महोदय हर साल बजट इन्ही दिनों पेश किया जाता है । इस साल के बजट को पढ्ने से ऐसा महसूस होता है कि हमारा प्रदेश सब से आगे चला जायेगा । हमारा हरियाणा प्रदेश सन 1976 के बाद से दूसरे नम्बर पर था लेकिन आज हम पूरी जिम्मे– दारी के साथ यह कह सकते हैं कि

इस बजट के हिसाव से नम्बर एक पर आ जायेगा । इस बजट से हरियाणा के आम आदमी को फायदा होगा । वित्त मस्ती जी ने किसी भी बिरादरी को या संस्था को नही छोड़ा है जिसको फायदा पहुंचाने की कोशिश न की हो । किसान, हरिजन और बैकवर्ड क्लास के लोगों को पूरा फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है । सब से अहम बात तो यह है कि हमारे प्रदेश के आम आदमी की आमदनी बड़ी है जिससे यह महसूस होता है कि हमारे प्रदेश के आम आदमी को इस बजट से फायदा होगा । सन् 1978 से अब तक हमारा प्रदेश दो नम्बर पर चल रहा था लेकिन इस बजट से ऐसा लगता है कि नम्बर एक पर उग जायेगा । वार्षिक योजना सन 1987–88 की 585 करोड़ 75 लाख रु० की रखी गई है । उसमें से ज्यादा से ज्यादा पैसा बिजली और सिंचाई के लिए रखा गया है । उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा सारा भारतवर्ष ही कृषि प्रधान देश है लेकिन भारतवर्ष में से हरियाणा प्रदेश सबसे बड़ा कृषि प्रधान प्रदेश है जिसमें 80 प्रतिशत लोग कृषि और पशुपालन पर निर्भर करते है । हरियाणा सरकार ने कृषि का काम करने वाले किसानों के लिए ज्यादा ध्यान दिया है । सबसे ज्यादा पैसा बिजली के लिये और सिंचाई के लिए रखा है जिससे कि हरियाणा के किसानों को समय पर बिजली दी जा सके और पानी उनके खेतों में टेल तक पहुंच सके ताकि उनके खेतों की सिंचाई हो सके । डिप्टी स्पीकर साहब, यह तो प्रैक्टिकल बात है कि 1988–87 वर्ष के लिए पम्पिग सैट लगाने का लक्ष्य 10,000 का रखा गया था लेकिन जनवरी, 1987 तक 10,

138 पम्पिंग सैट लगा दिये गये हैं । उसके आगे आप देखें अगले वर्ष 20,000 ट्यूबवैल्ज कनैक्शन्ज देने का और 25,000 पम्पिंग सैट बनाने का लहरा निर्धारित किया गया है । ट्यूबवैल्ज कनैक्शन की किसी उद्योगपति को या किसी ट्सरे महाजन को या किसी दूसरे व्यक्ति को जरूरत नहीं पड़ती । यह तो 100 परसैन्ट किसानों को जरूरत पड़ती है । कहने का मतलब यह है कि 25,000 पम्पिंग सैट और 20,000 ट्यूबवैल कनैक्शन्ज का लाभ किसानों को 100 परसैन्ट मिलेगा । इसके अलावा वित्त– मन्त्री महोदय ने बाढ़ नियन्त्रण के लिये भी पैसा रखा है । इसके लिये पैसा रखना भी चाहिये था । आपके माध्यम से मैं इस बात की सराहना करता हू कि बहादुरगढ़, छारा और छुढानी को ड्रेन नं० 8 की तबाही से बचाने के लिये पैसा रखा गया हए । आप जानते हैं कि जे ० एल० एन० तो हरियाणा में एस० वाई० एल० का पानी लाने के लिये बनी हुई है । जब पिछले दिनों चौधरी बंसी लाल यहां पर मुख्य मन्त्री थे, उस वक्त इन्होंने उसे बनाया था । अब कुछ दिनों से जे० एल० एन० के साथ साथ सीपेज और लीकेज की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है । दो तीन जगह के किसानों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है । जे ० एल० एन० के साथ नाथ 8– 10 एकड़ जमीन सीपेज और लीकेज की वजह से बरबाद हो गयी है । पिछले दिनों जब चौधरी बंसी लाल जी झज्जर गये थे तो उन्होंने वहां पर जनता के सामने यह अनाउन्स किया था और उनको यह विश्वास दिलाया था कि जे ० एल० एन० के साथ साथ जो सीपेज और लीकेज हो रही है, उसके

लिये एक ड्रेन बना दी जायेगी और उस पानी को फिर से उसमें फीड कर दिया जायेगा । जो उपजाऊ जमीन है, उसको बरबाद होने से बचाया जायेगा । मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि एस० वाई० एल० का पानी लाने के लिये जो जे ० एल० एन० नहर बनाई गयी है, उसकी सीपेज और लीकेज को रोकने के लिये ड्रेन बनाने की जल्दी व्यवस्था करवायें । एस० वाई० एल० के लिये जो पैसा रखा गया है, यह बहुत ही सराहनीय बात है । वैसे तो भारत सरकार ने पूरा खर्चा ओट लिया है । उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रदेश के लोगों के लिये बहुत अच्छी बात हुई है और हरियाणा सरकार के लिये भी बहुत अच्छी बात हुई है क्योंकि बिना पैसे के किसी भी प्रदेश की तरक्की नहीं हो सकती । अब प्रदेश के पैसे की बजाये भारत सरकार का पैसा लगेगा । यह बहुत अच्छी बात हुई है ।

डिप्टी स्पीकर साहब, मंडियो के लिये और भंडारागार बनाने के लिये भी इसमें जिक्र किया गया है । कल्लर भूमि को सुधारने के लिये भी स्कीम बनाई गयी है । पूरे प्रदेश में और खास कर उपाध्यक्ष महोदय, आपकी तरफ करनाल, पानीपत, अम्बाला और रोहतक का कुछ हिस्सा ऐसा है जहां पर काफी कल्लर जमीन है । उसको बचाने के लिये 60,000 मीट्रिक टन रियायती दरों पर जिप्सम देने की स्कीम बनाई गयी है जो हरियाणा के किसानों के लिये एक अहम बात है । इसके साथ हो चार नयी मार्किट कमेटियां, 15 सब–मार्किट यार्ड और 15 खरीद

केन्द्र बनाने की भी स्कीम है । उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश में किसानों के जितनी नजदीक मंडियां होंगी उतनी ही उनको अपना अनाज बेचने में सुविधा होगी । यह बहुत अच्छी बात की गयी है । इससे किसानों को समय और धन दोनों की बचत होगी । मैं आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री जी और वित्त मन्त्री जी का धन्यवाद करता हू कि कोसली मंडी पर काम शुरू करा दिया गया है । 4– 5 महीने पहले कृषि मन्त्री श्रीमती प्रसन्नी देवी जी वहां पर फांउडेशन स्टोन रख आयी थी और पिछले दिनों मुख्य मन्त्री जी जब वहां पर गये तो वहां पर यह मांग की गयी कि कोसली मंडी का काम शुरू कराया जाये । मुख्य मन्त्री महोदय जी ने वहां के लोगों की मांग को बड़ा अहम समझते हुए एक महीने से वहां पर काम शुरू करवा रखा है । मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि उस मन्डी को काम जितनी जल्दी हो सके, पूरा कराया जाये ताकि वहां के किसानों को सुविधा गिल सके ।

इसी तरह से ग्रामीण विकास के बारे में भी इस बजट में चर्चा की गयी है । मुख्य मन्त्री जी से हल्के साव्हावास के लोगों ने 24 जनवरी को यह मांग की थी कि हल्का साल्हावास में एक नया ब्लाक मातनहेल बना दिया जाये । 20 तारीख को इन्होंने कैबिनेट मीटिंग करके एक नया ब्लाक मातनहेल बना दिया है । उसके लिये मैं वित्त मन्त्री, मुख्य मन्त्री और हरियाणा सरकार का बहुत आभारी हूं और वहां की जनता इनका शुक्रिया अदा करती है कि वहां की जनता की सुविधा के लिये एक नया ब्लाक बना दिया

गया है । इसी तरह से ग्रामीण विकास के लिए गवर्नर ऐड्रैस में आदर्श गांव के बारे में भी जिक्र किया गया है । हल्के साल्हावास में भी कई बड़े बड़े गांव हैं जिनकी आबादी 6,7 और 8 हजार तक की है । मैं उनके लिये यह प्रार्थना करूंगा कि मेरे हल्के के गांव लडान, मातनहेल, बहुझोलरी और झाडौदा में से किसी एक गांव को आदर्श गांव का जरूर दर्जा दिया जाये क्योंकि यह काफी बैकवर्ड इलाका रहा है । ऐसा होने से वहां पर उस गांव में सड़कें, गलियां और दूसरे सारे काम हो जायेंगे और उस गांव के लोगों को सुविधाएं मिलेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय, पशुपालन के बारे में बहुत अच्छी बात की गयी है । वर्ष 1987– 88 में 40 नयी पशु चिकित्सा डिस्पैन्सरियां और 30 वर्तमान पशु चिकित्सा डिस्पैन्सरियों का दर्जा बढ़ाकर उनको पशु चिकित्सा अस्पताल बनाने का जिक्र किया गया है । यह बहुत अच्छी बात है । मैं भी इस बारे में एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश के किसानों का दूसरा काम पशुपालन का भी है । किसान खेती के अलावा पशु पालन का काम करते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, आप किसान हैं इसलिये सारी बातें आपके नौलेज कें हैए । आज किसान के घर में ऊन, दूध पैदा होता हे । यही नहीं हमारा प्रदेश दूध के उत्पादन में पिछले काफी समय पहले तो दूसरे नम्बर पर था, आज पता नहीं कौन से नम्बर पर है । नेहरा साहब यहां पर बैठे हुए हैं । मैं उनसे एक बात कहने की माफी चाहूंगा । उन्होंने कल ही एक सवाल के

जवाब में बताया था कि रोहतक जिले में सिर्फ चार हल्कों में वर्ष 1 986–87 में डिस्पैन्सरियां बनाई गयी हैं जिसमें मेरे हल्के साल्हावास का नाम शामिल नहीं था । नेहरा साहब, साल्हावास के लोग भी किसान हैं और वहां पर भी पशुपालन का काम बहुत ज्यादा होता है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि इस बार तो आप मेहरबानी करें, ज्यादा नहीं तो कम से कम एक डिस्पैन्सरी जरूर देने की कृपा करें । सेहलगा झांसवा या रेडुवास झाडोदा या किसी भी दूसरे गांव में आप डिस्पैन्सरी जरूर देने की कृपा करें । इसके साथ ही सहकारिता के लिये भी इस बजट में पैसा रखा गया है. । वित्त मन्त्री जी ने यह पैसा रखकर बहुत अच्छी बात की है । सहकारिता किसानों के लिये ज्यादा से ज्यादा कर्जा सस्ते व्याज पर लेने के लिये बनाई गई है । वहां से किसानों को कर्जा मिल जाता है । इसी तरह से उद्योगों के बारे में भी बहुत अच्छी बात की गयी है कि रोहतक तहसील और झज्जर तहसील को इंडस्ट्रीयली– बैकवर्ड डिक्लेयर किया गया है । हमें उम्मीद है कि सरकार वहां पर कोई न कोई फैक्टरी लगाने की कोशिश करेगी और कुछ उद्योग किसी न किसी उद्योगपति के भी लगेंगे । इससे वहां की तरक्की जाएगी और वहां के नौजवानों को रोजगार मिल सकेगा । मैं आपके माध्यम से उद्योग मन्त्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि वह भी हमारी इस मामले में मदद करें और हल्का साल्हावास भी झज्जर तहसील में पड़ता है । वहां पर कोई न कोई फैक्टरी वगैरह जरूर लगवायें ताकि वहां के नौजवानों को रोजगार मिल सके ।

**11.00 बजे**

डिप्टी स्पीकर साहब, इसमें औद्योगिक प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक शिक्षा के बारे में भी जिक्र आया है । यह बहुत अच्छी बात है । विल्ट मन्त्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा है कि राज्य के व्यावसायिक शिक्षा संस्थान 1०+2 शिक्षा पद्धति को लागू करने में सहायता दे रहे हैं । इस काम के लिये सरकार ने 2.50 करोड़ रुपए रखे हैं । डिप्टी स्पीकर साहब, पिछले चार बजट गुजर गए हैं और मैं हर बजट पर कहता रहा हूं कि साल्हावास के दक्षिण में महेन्द्रगढ़ पड़ता है जोकि साल्हावास से 45 किलोमीटर है, पश्चिम में भिवानी पड़ता है जोकि 45 किलोमीटर है, पूर्व में गुड़गांव पड़ता है जोकि' सत्तर किलोमीटर है और उत्तर में रोहतक पड़ता है जो 85 किलोमीटर है । हमारे यहां नजदीक में आई० टी ० आई० की कोई व्यवस्था नहीं छैं । उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि हर साल बेरोजगारी की समसग बढ्ती जा रही है और इसका कारण यह है कि हम अपने यहां नौजवानों को तकनीकी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं । हमारा सौभाग्य है कि सरकार ने इस साल तेरह नए व्यावसायिक शिक्षा संस्थान खोलने का फैसला किया है । इससे हमारे नौजवानों को बड़ी मदद मिलेगी । अगर हर साल प्रान्त में दस बारह आई० टी ० आइज० खोल दिए जाएं तो बेरोजगारी की समस्या काफी हद तक सुलझ सकती है क्योंकि जो भी लड़का आई० टी ० आई० से ट्रेनिंग लेकर बाहर आएगा उसके हाथ में कोई हुनर होगा । वह लडका अपना काम

कर सकेगा । उसको देश में या अपने प्रदेश में कुछ न् कुछ काम मिल सकेगा । अगर सभी बच्चों को तकनीकी शिक्षा मिलेगी तो अपने आप आने वाले पांच सात साल में बेरोजगारी खत्म हो जाएगी क्योंकि अगर हमारे जवानों के हाथों में कोई काम आ जाए तो वे कहीं भी काम कर सकते हैं । मैं अपने शिक्षा मन्त्री, वित्त मन्त्री और मुख्य मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि मेरे हल्का साल्हावास में चाहे कोसली या मातनहेल में किसी भी एक जगह आई० टी ० आई० चालू किया जाए । मेरे यहां गांव बिरोहरड में लोगों ने अपनी कमाई में से रुपया खर्च करके 27 कमरे स्कूल भवन के लिए बना रखे हैं । इसी तरह से मातनहेल जो बहुत बडा गांव है वहां पर भी स्कूल के लिए भवन बनाया हुआ है । मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि जब हम 21वीं शताब्दी की ओर बढ़ रहे हैं तो साल्हावास हल्के में किसी जगह भी एक आई० टी ० आई० खोला जाए । आई० टी ० आई० खोलने के लिए जो भी शर्तें होंगी हम उनको पूरा करेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं सड्कों के बारे में कहना चाहता हूं । सरकार ने सड़कों के लिये काफी पैसा रखा है । यह सौभाग्य की बात है कि चौधरी बंसी लाल दुबारा इस प्रान्त के मुख्य मन्त्री बनकर आए हैं । जो लड़के चौधरी बंसी लाल बनाकर गए थे उनकी मरम्मत न तो जनता पार्टी की सरकार ने की और न ही उनके बाद जो सरकार आई उसने की । चौधरी बंसी लाल ने आते ही उन सकडों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया । चौधरी

बंसी लाल ने फैसला किया है कि कुछ तो नई सड़कें बनाई जाएंगी और कुछ सड़कों की मरम्मत की जाएगी । मेरे हल्के में दस बारह सड़कों की मरम्मत हुई है । मैं वित्त मन्त्री जो से प्रार्थना करूंगा कि जो सड़क एक गांव को दूसरे गांव से मिलाती है या एक जिले को दूसरे जिले से मिलाती है उन सड्कों को प्रायरिटी बेसिज पर बनाना चाहिए । मेरे यहां झामरी से ढलानवास का फासला तीन वार किलोमीटर का है, यह छोटा सा टुकड़ा है अगर जनहित में इसको मिला दिया जाए तो जमींदारों को बड़ी सुविधा होगी । एक सड़क लडायन से सुन्धहरेटी है तथा दूसरी सडक सेहलंगा से पातुवास है, मेरी प्रार्थना है कि इनको भी बनाया जाना चाहिए । उपाध्यक्ष महोदय, साल्हावास से भिवानी जाने के लिए किसानों को काफी असुविधा होती है इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इस लिंक रोड को मिलाया जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं । सरकार ने शिक्षा के लिए काफी रुपया रखा है । वर्ष 1987–88 के दौरान 94 विद्यालय भवन और 18 रिहायशी क्वार्टर पूरे करने के लिए 160 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है और इसी वर्ख में लडकियो के लिए 100 नए प्राथमिक विद्यालय खोलने का प्रोविजन हए । उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 1987–88 के दौरान, सौ प्राथमिक विद्यालयों का दर्जा बढ़ाकर मिडल विद्यालय, पचास मिडल विद्यालयों का दर्जा बढ़ा– कर उच्च विद्यालय तथा पच्चीस उच्च विद्यालयों का दर्जा बइऋाकर सीनियर माध्यमिक विद्यालय (10+2

प्रणाली ) बनाने का प्रस्ताव है । मैं इमका स्वागत करता हु । उपाध्यक्ष महोदय, जिस परिवार में अधिक से अधिक पढ़े लिखे लोग होंगे तो वह परिवार ऊंचा उठेगा, जिस गांव में पढे लिखे लोग होंगे वह गांव उन्नति करेगा, जिस तहसील में पढे लिखे लोग अधिक होंगे वह तहसील तरक्की करेगी और जिस जिले प्रान्त और देश में अधिक से अधिक पढ़ेलिखे लोग होंगे वहां भी बहुत अधिक उन्नति होगी । हरियाणा सरकार तीन चार किस्म की शिक्षा को बढ़ावा दे रही है और सरकार ने तीन चार किस्म की शिक्षा के लिए काफी पैसा रखा कुछ । उपाध्यक्ष महोदय. टूमना और गामडी में इस समय गवर्नमैंट मिडल स्कूल्ज हैं । लोगों की मांग है कि इन दोनों स्कूलों को हाई स्कूल कर दिया जाये । गामडी में स्कूल भवन के लिए पन्द्रह कमरे बना रखे हैं । इसलिए इनको जल्दी से जल्दी हाई स्कूल किया जाए । कालियावास, बिठला, नौगावों और सुधहरेटी जहां इस समय प्राईमरी स्कूल्ज हैं इनको मिडल स्कूल बना दिया जीए तो ठीक रहेगा । उपाध्यक्ष महोदय. मेरे हल्के के लोगों की मांग है कि साल्हावास, लडायन और विरोहरड में 10 + 2 की क्लासिज शुरू की जाएं । विरोहरड में गांव वालों ने 27 कमरे बना रखे हैं, भवन तैयार है । पूरा देहात का इलाका है । वहां पर एक नवोदय स्कूल खोला जाए । इसी प्रकार गांव भूरावास में 25 कमरे तैयार हैं । झाडोदा और लडावन में पुराने भवन में दरारें पड़ गई हैं वहां पर भवन ठीक करने व मरम्मत के लिए रकम दी जाए । उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के प्रसार के लिए सरकार जो कदम उठा रही है यह बहुत

सराहनीय कदम हैं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं सह–शिक्षा के बारे में कुछ कहना चाहता हुं । हमारे यहां सह–शिक्षा की नीति चल रही है । दम ग्यारह साल तक जब बच्चे प्राईमरी क्लासिज में पढ़ते हैं अगर उस स्टेज तक सह शिक्षा में पढ़ते रहें तो कोई नुक्सान की बात नहीं होनी क्योंकि उनको कुछ पता नहीं होता दुनियावी बातों का । जब बच्चा, चाहे वह लडका है या लड़की है दसवीं के बाद कालेज स्टेज पर आता है तो उसको समझ होना है । कह अपने भविष्य के लिए खुद जिम्मेदार होता है और कोई भी कदम उठाने से पहले उसके नतीजे के बारे में वह सोच सकता है । इस स्टेज पर भी अगर सह–शिक्षा रहे तो कोई नुक्सान नहीं है । छठी क्लास से दसवी क्लास तक पढ़ने वाले बच्चे चाहे वह लडका है या लड़की है अपने भले बुरे के लिए और अपने भविष्य के बारे में भ्रमिक होते हैं । वे कोई भी गल्त फैसला ले सकते हैं । उनको अधिक अपने भविष्य के बारे में ज्ञान नहीं होता । उपाधक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है कि छठी से दसवीं तक की शिक्षा का जो स्तर हे बह लड़के और लडकियों का अलग अलग किया जाए । इस स्तर पर सह–शिक्षा नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह उमर कच्ची उमर कहलाती है । दसवीं के बाद उनको समझ आ जाती है ।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा के बारे में अपने विचार रखना चाहता हुइ । सरकार ने पिछले वर्ष काफी स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को दी हैं और वर्ष 1987– 88 के दौरान 150 उप केन्द्र, पचास प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा दस

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है । मेरे हल्का साल्हा– वास में दो पी ०एच ०सी ० पर काम चल रहा है । ये पी ०एच० सी ० कोसली और मातनहेल में बन रही हैं । मेरी स्वास्थ्य मन्त्री से प्रार्थना है कि गांव खोरडा, भूरावास, खानपुर और ढलानवास में एक–एक उपकेन्द्र खोला जाए ताकि वहां पर जनता को स्वास्थ्य सुविधा मिल मकें । अब इनको बड़ी परेशानी रहती है क्योंकि नजदीक में कोई सुविधा नही है । उपाध्यक्ष महोदय, रोहतक मैडिकल कालेज में अन्य सरकार ने जो रकम दी है वह एक सब से ज्यादा सराहनीय काम है । इससे लोगों में बड़ी खुशी फैली है । इससे पूरे प्रदेश की जनता को काफी सुविधा मिलेगी । चौधरी बंसी लाल ने प्रधान मन्त्री से मिलकर प्रदेश की जनता के लिए बहुत अच्छें फैसले लिए हैं । प्रधान मन्त्री ने इस प्रदेश की जनता की भलाई के लिए बहुत बड़ी रकम दी है । यह सब चौधरी बंसी लाल की वजह से ही मुमकिन हो सका है । प्रधान मन्त्री ने इस प्रदेश को जो आर्थिक मदद दी है उससे इस प्रदेश की जनता को बड़ी सुविधा मिलेगी ।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं सिंचाई के संबंध में कुछ कहूंगा । मेरे हल्के साल्हावास में 11– 11– 1983 को झांसवा माईनर के नाम से एक माईनर मन्जूर की गयी थी और 1984 में उस पर कुछ काम भी आरम्भ हो गया था । लगभग 20 परसैन्ट काम उस पर हो चुका है लेकिन बाद में आज तक उसका काम रुका पड़ा है, पूरा नहीं हुआ है और न ही वहां के किसानों को

उनकी जमीनों के बदले में मुआवजा ही दिया गया है । मुआवजे के ये नियम हैं कि अगर 3 साल तक किसानों को मुआवजा न दिया जाए तो उसके बाद औटोमैटिकली वह अवार्ड कैन्सल हो जाता है बोर दोबारा मुआवजा देने के लिए केस रिवाईव करना पड़ता है । इसलिये मेरा यह कहना है कि एक तो वह माईनर कम्पलीट करवायी जाए दूसरे किसानों को शी अ ही उनका मुआवजा दिया जाए । अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो किसानों के साथ सरकार की तरफ से बहुत भारी ज्यादती होगी । अगर अब तक किसान उसी अपनी जमीन पर बुवाई करते तो उससे अनाज पैदा करते लेकिन किसान बेचारा आज दोनों से वंचित रह गया है । इसलिये मेरी सरकार इए प्रार्थना है कि इन दोनों बातों पर ध्यान दिया जाए । एक तो माईनर कम्पलीट करवाई जाए और दूसरे किसानों को जल्दी से जल्दी उनका मुआवजा दिलवाया जाए । इसके साथ साथ मैं एक बात और कहूंगा कि मुख्य मन्त्री महोदय ने प्रदेश के किसानों के लिये जो राहत दी है, वह राहत 1947 से ले कर आज तक शायद ही किसी और दूसरी सरकार ने दी हो । किसानों तथा गरीब आदमियों को हर प्रकार से सहूलियतें मुहैया की गयी हैं, इसका साफ प्रमाण हमारा यह बजट है । यह रिकार्ड की बात है ।

उपाध्यक्ष महोदय, यह भी एक प्रशंसनीय बात है कि हमारे मुख्य मन्त्री चौधरी बंसी लाल जी ने कभी भी दूसरे मुख्य मन्त्रियों की तरह जनता को यह नहीं कहा कि मैं मुख्य मन्त्री

बनूंगा तो किसानों को यह दूंगा, फलां रियायत दूंगा लेकिन उन्होंने अपने आप ही इस बात को महसूस किया कि किसानों और दूसरे बैकवर्ड क्लास के लोगों को, गरीब तबके के लोगों को कुछ न कुछ राहत की आवश्यक्ता है । इस– लिये उन्होंने अपने आप ही 113 करोड़ रुपया खालें पक्की करने का और 6– 7 करोड़ रुपया उगाही का माफ कर दिया है । शायद ही इतना बड़ा फायदा किसी और सरकार ने लोगों का किया हो । इसके लिए वे सचमुच में प्रशंसा के पाल है ।

**श्री उपाध्यक्ष :** चौधरी हुकम सिंह जी, वाइंड–अप कीजिये और मैम्बरों ने भी बोलना है ।

**चौधरी हुक्म सिंह :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक दो मिनट में समाप्त करता हूं । मैं कह रहा था कि किसानों के लिये इस सरकार ने काफी राहत दी है चाहे वह बीजों की शक्ल में हो, चाहे वह कोई और टैक्स की शक्ल में हो और चाहे छोटे इंजनों की शक्ल में हो, हर प्रकार से टैक्स में छूट दी गयी है । चूड़ियों पर भी बिक्री टैक्स माफ कर दिया गया हए । टाईप की मशीनों पर बिक्री कर 12 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है । सरकार ने किसानों के लिये सभी किस्म के बीजों पर जो छूट दी है उससे प्रदेश के जमींदारों का हौसला बढ़ेगा और वे ज्यादा अनाज पैदा करेंगे । इस प्रकार व्यापारी वर्ग को भी जो छूट दी गयी है उस से भले ही राज्य सरकार को कुछ कम कर मिले किन्तु उत्पादन में वृद्धि होगी । इससे हरियाणा प्रदेश की उन्नति

अवश्य होगी । हर आदमी की वित्तीय स्थिति अच्छी होगी । इसलिये इस बजट को बड़ा ही हितकारी और गरीबों का बजट ही कहना होगा ।

डिप्टी स्पीकर साहब, इसी प्रकार से आगे मैं यह कहूंगा कि हरियाणा सरकार अपने कर्मचारियों की वेतन वृद्धि में जो बढ़ोतरी करने जा रही है, वह बड़ा ही सराहनीय कार्य है । इस से सभी क्लास के कर्मचारियों को फायदा होगा । इस तरह का अच्छा काम सारे भारत में भव से पहले हमारी हरियाणा स्टेट ने ही किया है कि उसने चोगे पे कमिशन की रिपोर्ट को यूं का यूं मान लिया है और पहली जनवरी. 1986 से 31 मार्च, 1987 तक का बकाया कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खातों मे जमा कर दिया जाएगा । अब भविष्य निधि में जमा पैसे पर भी नौ प्रतिशत की बजाय 1 2 परसैन्ट ब्याज मिलेगा । डिप्टी स्पीकर साहब, हमारी सरकार ने कोई ऐसी बात नही छोड़ा है जो इस बजट के अन्दर न दी गयी हो और जिमसे गरीब हरिजन को, बैकवर्ड क्लासिज के लोगों को औररू किसानों को छूट न दी गयी हो ।

डिप्टी स्पीकर साहव राज्य सरकार पिछड़े वर्गों के विकास के लिए बहुत अच्छे कदम उठाने जा रही है । सरकार ने बजट के अन्दर यह प्रस्तावित किया है कि जहां किसी ग्राम सभा क्षेत्र में पिछडे वर्गो की संख्या 2० प्रतिशत या अधिक होगी वहा इन वर्गो से एक पंच चुनाव या नामजदगी द्वारा नियुक्त किया जाएगा । यह एक आम आदमी को ऊपर उठाने के लिये सरकार

द्वारा उठाया गया एक सराहनीय कदम है । इसलिये मैं अन्त में यही कहूंगा कि यह वजट हुक बहुत अच्छे तरीके से और मुझ–बूझ के साथ वनाया गया है । मैं इमका पुरजोर समर्थन करता हूं और आपका धन्यवाद करता हुआ अपना स्थान लेता हूं क्योंकि आपने मुझे बोलने का समय दिया ।

**चौधरी रोशन लाल आर्य (छछरोली ) :** उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 1987–88 का जो बजट इस सदन में वित्त मन्त्री महोदय ने पेश किया है, उसमें किसी प्रकार का कोई टैक्स नही लगाया गया है और न ही किसी विकास के कार्य में किसी प्रकार की कटौती की गयी है । इस तरह से कई प्रकार की हमारी सरकार की उपलब्धियों के बारे में इस बजट अभिभाषण मै बतलाया गया है जिनकी. प्रशंसा किये बगैर मैं नही रह सकता । उपाध्यक्ष महोदय, इस वजट के अन्दर जितना कुछ लिखा गया है और दिया गया है उसके ऊपर वर्णन करने के लिए अगर सही ढंग से बोला जाए तो कम से कम 3 या 4 घण्टे का समय लग सकता है लेकिन मैं समझता हू कि मुझे बोलने के लिये इतना समय नहीं मिल सकता । इसलिये जहां मैं इसका समर्थन करता हूं वहां मैं कुछेक मुख्य मुख्य बातों पर अपने विचार रखूंगा और साथ ही साथ सरकार की कुछ योजनाओ पर अपने विचार भी प्रकट करना चाहूंगा ताकि जो सरकार के विकास के कार्यों की गति है, उसमें और तेजी आये और जहा कहीं कोई अवरोध हो, उसमें सरकार को दूर करने में कुछ मदद मिले । वित्त मन्त्री महोदय व रैवेन्यू

मिनिस्टर महोदय बैठे है, अगर ये सुनेंगे तौ चन्द शब्द कहना चाहूगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, सब से बड़ी समस्या तो इस समय हरियाणा के अन्दर बाढ नियन्त्रण की है और इस काम के लिये 13 करोड़ रुपया रखा गया है । बहुत अच्छी बात है । इस बारे में केवल मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि नीचे से जो योजनाएं बनाने वाले हैं, पता नहीं वे किस जगह पर बैठ कर बाढ़ नियन्त्रण की योजनाएं बनाते हैं क्योंकि वे बाढ़ नियन्त्रण ऐसी जगहों पर करना चाहते है, जहां कभी बाढें आयी ही न हों । यमुनानगर का इलाका है, वहां पर आये साल बाढ़ का प्रकोप होता है । वहां पर आये साल लोगों की जमीन बाढ़ के कारण कट जाती है और आबादी को काफी खतरा हो जाता है जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है । इसलिये मेरा निवेदन है कि यह जो बाढ़ नियन्त्रण के लिये 13 करोड़ रुपया रखा गया है, इस रुपये का लाभ इन यमुना के इर्द–गिर्द लगने वाले गांवों को भी मिलना चाहिये और इस इलाके के लोगों की सुरक्षा का पूरी तरह से प्रबन्ध होना चाहिये । इसलिये मैं इसके लिपे वित्त मन्त्री महोदय से इस बात का आश्वासन चाहूंगा कि मेरे छछरौली हल्के और यमुनानगर के हल्के के साथ लगते गांवों के लिये बाढ़ नियन्त्रण के लिये पूरा पूरा ध्यान रखा जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हरियाणा के अन्दर वृक्षारोपण में भी हरियाणा

सरकार ने बड़ी प्रगति की है । वन–सम्पदा हरियाणा में ज्यादा हैं । आगामी वित्त वर्ष के दौरान वृक्षारोपण और वन्य जीव परिरक्षण पर 20 करोड़ रुपये से अधिक खर्च करने का प्रस्ताव है । आशा बुश कि हम अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंच पाएंगे । अगर हमारे किसान भाई हमारी सरकार को इस में सहयोग देंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सरकार को इस प्रोग्रैस से दोहरा लाभ होगा । एक तो पर्यावरण ठीक होगा और जो भी आज के हालात के मुताबिक दूषित वातावरण हैं, हमारे वन उनको कंट्रोल करेंगे । इसके साथ–साथ मैं एक और बात सरकार के नोटिस मैं लाना चाहता हु कि मेरे हल्के छछरौली में आग से कई साल पहरने एक जू बनाये जाने का सरकार का प्रस्ताव था, पता. नही उस स्कीम को कैसे रोक दिया गया । मेरे विचार में वह फाईल कहीं दबी पड़ी होगी । इसलिये सरकार से मेरा निवेदन है कि सरकार इस केस की ओर भी ध्यान दे । क्या मन्त्री महोदय इस तरह का आश्वासन देंगे? उपाध्यक्ष महोदय, मैं बीमार होने की वजह से आज सैशन में कुछ लेट आया था जिसकी वजह से मेरा एक सवाल बीच में रह गया था । वह सवाल मैंने इसलिये उठाया था कि मेरे हल्के में 'कुछ गांव ऐसे हैं जिनने जबरदस्ती पेडू लगाए जा रहे हैं । दो सौ के करीब हरिजन मुझे मिले थे । उन्होंने कहा कि हमारे पशु कई दिनों से हमारे घरों में ही बंधे हैं । हम उनको बाहर लेकर जाते है तो वन विभाग वाले हमें पीटने के लिए आते हैं । देश में हमारी सरकार सब से ज्यादा हरिजनों की हिमायती है । हम और कामों पर बहुत पैसा खर्च करते हैं लेकिन एक आधा

मूर्ख आदमी ऐसा भी है जो सरकार की इमेज को बिगाडना चाहता है । ये नीचे वर्ग के लोग हमारे मुख्य मन्त्री चौधरी बंसी लाल जी के बहुत समर्थक हैं लेकिन मैं यह समझता हूं कि जो कर्मचारी इस सरकार से तनखाह लेते हैं उनमें से कुछेक गड़बड़ करना चाहते हैं । इसलिये मेरी प्रार्थना है कि वन विभाग के कर्मचारियों को रोका जाए कि वे हरिजनों को तंग ने करें । हमारे लिए यह बहुत भारी समस्या है । लोग बहुत परेशान हैं कयोंकि गैर–कानूनी तरीके से काम हो रहा है । अगर सरकार अपने वन महकमे के कर्मचारियों को गलत काम करने से रोकेगी तो मैं बड़ा आभारी हूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार देश में पहली सरकार है जिसने अपने कर्मचारियों के लिए चौथे पे कमीशन की रिपोर्ट लागू करने का ऐलान किया है । हमारा राज्य दूसरे राज्यों से दस करोड़ रुपया अधिक अपने कर्मचारियों को दे रहा है लेकिन इसके बावजूद भी हमारे कुछ कर्मचारी विपक्ष के हाथों में खेल कर ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि ऐसा लगे कि सरकार ने अपने कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं दिया । मैं चाहूंगा कि जहां जहां पर ऐसी लूपहोल्ज हैं उनको एक्सपोज किया जाए । मैं सरकारी कर्मचारियों से भी निवेदन करूंगा कि वे इस प्रकार के लोगों के बहकावे में न आएं । कर्मचारियों को तो हमारे मुख मन्त्री जी का आभारी होना चाहिए जिन्होंनें– देश में सब से पहले अपने

कर्मचारियों को यह सुविधा दी है और बैक डेट से दी है । तो इस का जो लोग विरोध कर रहे हैं वे न तो कर्मचारियों के हितैषी हैं और न ही हरियाणा के हितैषी हैं । कर्मचारियों को ऐसे राजनैतिक लोगों से दूर रहना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी' खुशी हे कि हमारे पी ० डब्ल्यू ० डी ० के मन्त्री मेरे जिले से संबंध रखते हैं । इन्होंने प्रान्त की बड़ी भारी सेवा करने का इरादा बनाया हुआ है । 1987–88 के बजट में सड़कें बनाने के लिऐ 5.2 करोड़ रुपए रखे गए हैं । यह बहुत अच्छी बात है और जरूरी भी था । मैं तो समझता हूं कि सड़कें बनाने के लिए इस महकमे को और भी ज्यादा पैसा दिया जाता । आदरणीय मन्त्री जी मेरे मिल हैं । मैंने इनको दो सवाल किए थे लेकिन दोनों को गोल कर गए । उनके बारे में ये मुझे अकेले में भी नहीं बताते और असैम्बली में भी नहीं बताते । अगर मेरे द्वारा सवाल देने में इनको कोई दिक्कत आती हो तो कोई बात नहीं । हमें यह चाहिए कि हम सभी हल्कों में सड़कें और पुल बनाएं । मैं अपनी सरकार से तथा सभी मन्त्रिगण से निवेदन करूंगा कि सभी हल्कों में एक जैसा 'काम होना चाहिए । मेरे हल्के ने 18 हजार रुपए एक सड़क बनाने के लिए जमा करवा रखे हैं लेकिन वह सड़क नहीं बनाई जा रही है । मैं जानना चाहता हू कि क्या हमारे रुपए असली नहीं हैं? मैं खास तौर से बुडिया और खारवान लिंक रोड की बात करता हूं । यह लिंक रोड बनने से दो हरिजन बस्तियां आपस में मिल जाती हैं ।

ये बस्तियां बहुत पुराने जमाने की हैं । (इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य, श्री भले राम पदासीन हुए ) ये बस्तियां राजा बीरबल की बसाई हुई हैं । मैं चाहूंगा कि मन्त्री जी मेरी इस बात को नोट करके इस पर अमल करें । परिवहन के बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि इस क्षेत्र में हमारे प्रदेश ने सारे देश में अपना नाम कमाया है और कई बार राष्ट्रीय स्तर का एवार्ड भी प्राप्त किया है । लेकिन इसी सत्र के दौरान कुछ बातें आई थीं जिनको मैं दोबारा नही कहना चाहता । मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हू कि बस क्रू शैल्टर्ज के लिए विशेष मान दण्ड निर्धारित किए जाएं । बस क्यू शैल्टर्ज विशेष तौर पर देहातों में उन स्थानों पर बनाए जाएं जहां आस पास खड़े होने का कोई स्थान न हो । यह सुविधा न होने से खास तौर से बच्चों और स्त्रियों को हर मौसम में बहुत तकलीफ होती है । मैं चाहूंगा कि जहां हमारी रोडवेज सारे देश में नम्बर एक पर दु वह इस मामले में भी हमारी सरकार का नाम ऊंचा करेगी ।

चेयरमैन साहब, अब मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं । वर्ष 1987– 88 के दौरान लड़कियों के 100 नये प्राथमिक विद्यालय खोलने का प्रावधान है । यह बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि जब तक स्त्री शिक्षा नहीं होगी तब तक हमारे समाज का कल्याण नहीं होगा । मैं निवेदन करूंगा कि ये सारे स्कूल देहातों में खोले जाएं खास तौर से जहां वीकर सैक्शंज और हरिजन लोग रहते हैं । इन इलाकों में इन स्कूलों के– खेलिने की बहूत जरुरत

हैं । हम शिक्षा के ऊपर ऊना पैसा खर्च करते हैं, उसमें से कुछ हिस्सा इस बात के लिए भी खर्च करें कि हमारी शिक्षा का जो ढंग है वह इस प्रकार का हो कि हमारी भारतीय संस्कृति का प्रभाव आने वाली पीढ़ी पर 'पड़ सके । मैं इस बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूं । हमें अपनी शिक्षा प्रणाली में संस्कृत और दर्शन शास्त्र को बढावा देना चाहिए । संस्कृत के बारे में आप कहेंगे कि यह तो बहुत पुरानी भाषा है । मैं आपको मिसाल. देता हूं कि अमरीका में कम्प्यूटर का सब से बड़ा केन्द्र है । कम्प्यूटर के अन्दर संस्कृत भाषा फीड की जाती है और उसके आधार पर कम्प्यूटर पूरा डैटा देता है । अमरीका वालों भै भी इस बात को माना है कि दुनिया में केवल संस्कृत ही ऐसी भाषा है जो कम्पयूटर के अन्दर पूरी उतरती है, इसमें कोई गल्ती नहीं होती । जैसे हमारे कुरुक्षेत्र के अन्दर संस्कृत का विद्यालय खोला गया है, इसी तरह और जगह भी खोले जा सकते हैं । अगर इसके लिए कोई कदम उठाए जाएं तो बहुत ज्यादा खर्चा नही होगा । जो थोड़ा बहुत खर्च होगा उससे प्रदेश को बहुत फायदा होगा । संस्कृत में ही हमारे मूल ग्रंथ लिखे गए हैं । अगर यह पढ़ाई शुरु कर दी जाती है तो उनमें से कुछ न कुछ अच्छी बातें हमारे बच्चों के सामने आएंगी । मैं समझता हूं कि ऐसा करने से हमारे समाज के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा । हमारे कालेजों में जो सलेबस शामिल किया जाता है उनमें दर्शन शास्त्र विषय को भी शामिल किया जाना चाहिए । मैंने कई कालेजों में देखा है कि बच्चे दर्शन शास्त्र को पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए इस विषय को पढ़ाने की उन

कालेजों में कोई व्यवस्था नहीं है । कालका में जो कालेज है वहां पर भी मैं गया था । उस कालेज के काफी बच्चे दर्शन शास्त्र विषय को पढ़ने के इच्छुक हैं । यह कोई नीरस विषय या बच्चों को दूर ले जाने वाला विषय नहीं है । यह वह विषय है जो मनुष्य को पहले मनुष्य बनाना सिखाता है । यदि हम अच्छे इन्जीनियर, डाक्टर और वकील तैयार करते हैं तो हमें ऐ सी भी शिक्षा देने की कोशिश करनी चाहिए जिनके पढ़ने से मनुष्य अच्छा मनुष्य बन सके । देश भक्ति की भावना और राष्ट्र निर्माण के संस्कारों का होना प्रत्येक मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यवक है । चेयरमैन साहब, आपने भी देखा होगा और अखबारों में पढ़ा होगा कि हमारे देगा के कुछ लोग शराब के लालच में या दूसरे लालच में आकर 150– 150 और 200–200 रुपये के अन्दर अपने देश के नक्शे वगैरा या और गोपनीय बातों को बाहर वालों को बता देते हैं जो कि देश के लिए बहुत ही हानिकारक बात है । यदि दर्शन शास्त्र जैसे विषय हम अपने बच्चों को पढायेंगे तो उनमें देशभक्ति की भावना पैदा होगी और फिर चाहे उनकी जान भी चली जाये, वे कोई गलत काम अपने देश के खिलाफ नहीं करेंगे । मैं समझता हूं कि मेरी इस बीत को मंत्री जी ने नोट कर लिया होगा और जरूर इन पर कुछ कार्यवाही करेंगे ।

चेयरमैन साहब, स्वास्थ्य तथा चिकित्सा के लिए जो पैसे रखे गए हैं वे ठीक हैं । मैं स्वास्थ्य के बारे में ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जितने भी हमारे हौस्पिटल चल रहे हैं, उनके ऊपर

डाक्टरों की. तन्खाह और दवाइयों आदि का बहूत भारी खर्च होता है । इसके लिए मैं चाहूंगा कि सरकार को इस दिशा में ज्यादा ध्यान देना चाहिए और इस काम के लिए जितना पैसा खर्च करने की आवश्यकता हो उतना अवश्य खर्च करना चाहिए । सरकार ने मैडिकल कालेज का जो दर्जा बढायी है वह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है । अब रोहतक मैडिकल कालेज का स्टैडर्ड पी० जी ० आई० जैसा होगा । जिस प्रकार से पी ० जी ० आई० के अन्दर हिमाचल, यू० पी ० और जम्मू कश्मीर से लोग ईलाज के लिए आते हैं उसी प्रकार की सुविधा अब रोहतक के अन्दर भी होगी । नई मशीनें आ जाने के बाद व दूसरी जरूरियात पूरी होने पर काफी सुविधा मिला करेंगी । इससे प्रदेश की जनता को बहुत बडा लाभ होगा । इस मैडिकल कालेज का स्टैडर्ड ऊंचा हो जाने से हमारे प्रदेश की जनता को उच्चतम और सर्वश्रेष्ठ सुविधा उपलब्ध होगी । इसके साथ साथ मैं स्वास्थ्य मंत्रीली जी के ध्यान में यह भी लाना चाहूंगा कि जहां पर हम किसी काम के लिए पैसा रखते हैं तो उस की चौकिंग के लिए भी हमारी जिम्मेवारी बनती है कि आया वहां पर काम ठीक हो रहा या नहीं । इस बारे में मेरी सभी मत्रियों से प्रार्थना है कि उनके विभाग के लिए बजट में जो नए काम करने कें लिए पैसा रखा गया है, मौके पर जा कर देखना चाहिए कि काम ठीक हो रहा या नहीं । यदि मंत्री जी खुद अपने लैवल पर इस बात की निगाह रखेंगे तो काम और अच्छी प्रकार से होगा । इससे नीचे के स्तर पर जो काम करने वाले लोग हैं उनमें भी काम करने में तेजी आयेगी । छछरौली में कुछ

समय पहले बच्चों का एक डाक्टर लगाया गया था लेकिन अब वहां पर कोई डाक्टर नहीं है । मेरी इस बारे में स्वास्थ्य मंत्री जी से प्रार्थना है कि वहां पर बच्चों का एक डाक्टर जल्दी से जल्दी भिजवाया जाये । यमुनानगर के अन्दर बहुत बड़ा हौस्पिटल है । वहां के आमपाम की आजादी करीब डेढ़ लाख है । उस हौस्पिटल में कोई सर्जन नहीं है । इसलिए मती जी से मेरी प्रार्थना है कि वहां पर एक सर्जन डाक्टर जल्दी से जल्दी. भिजवाने की कृपा करें ।

चेयरमैन साहब, तकनीकी शिक्षा के बारे में भी मैं कुछ शव्द कहना चाहूंगा । मेरे हल्के के अन्दर एक पौलिटैक्निक खोला जोना है । इमके लिए हमने 26 एकड जमीन भी सरकार को दी है । इसके अतिरिक्त जो कुछ भी सरकार को चाहिए हमारे एरिया के लोग देने के लिए तैयार हैं । इस पौलिटैक्निक का केस भारत सरकार के पास गया हुआ है । मैं चाहूंगा कि इस स्कीम को भारत मरकार से मन्जूर करवा कर हमारे क्षेत्र का भला किया जाये । ‘ पहले छछरोली में जे० बी ० टी ० स्कूल भी था और पटवार स्कूल भी था, जो अब बन्द है । इसलिए हम चाहते हैं कि छछरोली में यह पोलिटैक्निक जल्दी से जल्दी खुलवाने की व्यवस्था की जाये ।

चेयरमैन साहब, अब मैं जनस्वास्थ्य के बारे में कहना चाहूगा । हमारी सरकार ने इस काम के लिए बहुत पैसे रखे हैं । पीने के पानी की समस्या मनुष्य के लिए सबसे पहली समस्या है ।

जो सरकार पीने के पानी का प्रबंध करती है, वह बहुत महत्वपूर्ण काम करती है । मेरे क्षेत्र में पिछले दो वर्षों के दौरान इस काम के लिए तकरीबन एक करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं । इस बारे में मेरा सरकार को सुझाव है कि जहां पर भी वाटर सप्लाई स्कीम बनाई जाये, वहां पर आस पास की छोटी छोटी बस्तियों का भी ख्याल रखा जाना चाहिए । जब भी कोई योजना बनाएं जाये तो इस तरफ अवश्य ध्यान दिया जाये । कई जगह ऐसा हुआ है कि छोटी छोटी बस्तियों को किसी भी योजना के तहत पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है । मैं समझता हूं कि भविष्य में सरकार इस प्रकार की जो योजनाएं बनाये, उनमें इन छोटी छोटी बस्तियों को ध्यान में रखे । अब मैं पर्यटन के बारे में कुछ कहना चाहुंगा । पर्यटन में हमारे प्रदेश का नाम सारे देश में सबसे आगे आता है । जब राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन की चर्चा होती है तो उस समय हरियाणा का नाम सबसे ऊपर आता है । सरकार कुरुक्षेत्र. में भी नया पर्यटन केन्द्र खोलने जा रही है । जहां पर धार्मिक स्थान है और जहां पर बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं वहां पर ऐसे पर्यटन केन्द्र अवश्य खोले –जाने चाहिए । इन पर्यटन केन्द्रों के अन्दर आम आदमी का भी ख्याल रखा जाना चाहिए । स्टैंडर्ड राजे–महाराजाओं जैसा किया जाता है तोर आम आदमी के लिए भी इंतजाम किया जाना चाहिए चाहे इसके लिए उस पर्यटन केन्द्र के अन्दर अलग से सैक्शन ही क्यों न खोलना पड़े । यह मैं इसलिए कह रहा हू कि जव कोई आदमी किसी तीर्थ स्थान पर जाता है तो वह भी उन पर्यटन केन्द्रों में विश्राम कर सके ।

चेयरमैन साहब, अब मैं खेल कूद की बात कहना चाहूंगा । खेल कूद के लिए जो 142 लाख रुपये रखे गए हैं, ये बहुत कम हैं । इस राशि को बढाया जाना चाहिए । हमारे प्रान्त क् बहुत तगड़े तगड़े पहलवान हैं । यदि प्रदेश के अन्दर ठीक ढंग से चयन किया जाये तो हमारे यहां पर कई खेलों की अच्छी अच्छी टीमें तैयार हो सकती है । जिस प्रकार से पी ० टी ० उषा का नाम सारे देश में ऊंचा हुआ है, उसी प्रकार से यदि सही चयन यहां से किया जाये तो मैं समझता हूं कि यही के बच्चे भी हमारे प्रदेश का नाम ऊंचा कर सकते हैं । इस चयन के दौरान किसी वर्ग विशेष का ख्याल नहीं रखा जाना चाहिए । इस बारे में मेरी खेल कूद मंत्री जी से प्रार्थना है कि वे कोई ऐसी योजना बनायें जिसके जरिए अच्छे बच्चों का चयन हो सके चाहे वे किसी भी जाति से संबंध क्यों न रखते हों । यह तभी संभव होगा जब हरियाणा के सारे क्षेत्रो में जाकर देखा जायेगा । जो अच्छे खिलाड़ी हैं, उनको आगे आने का मौका दिया जाना चाहिए । यदि ऐसा किया जाता है तो मैं समझता हूं कि यहां पर कई टीमें तैयार हो सकती हैं और हरियाणा का नाम ऊंचा हो सकता है ।

चेयरमैन साहब, अब मैं प्राकृतिक आपदाओं पर बोलना चाहूंगा । पिछले दिनों मेरे हल्के में भी ओले पड़े थे । उस समय किसानों का जो नुकसान हुआ था, उसका रिलीफ अभी तक सरकार की तरफ से किसानों को नही दिया गया है । अम्बाला जिले में कई स्थानों पर ओले पड़े थे । राजस्व मैली भी अम्बाला

जिले के रहने वालें ही हैं । शायद वे अपने हल्के के लोगों को भी पैसे न दिलवा पाये हों । मैं चाहूंगा कि जिन जिन किसानों का ओलों की वजह से नुकसान हुआ है, उनको तुरन्त सहायता प्रदान की जाये ।

चेयरमैन साहब, जो बजट वित्त मंत्री जी ने हरियाणा की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए पेश किया है उसके लिए आभार प्रकट करता हू । यह अच्छा बजट हमारे मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा और प्रधान मंत्री जी के सहयोग से ही संभव हो पाया है । इसलिए मैं इन सबका धन्यवाद करते हुए अपना भाषण यहीं पर समाप्त करता हू ।

**श्री मोहन लाल पीपल (पटौदी–अनुसूचित जाति ) :** चेयरमैन महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे समय दिया । दो मार्च को वित्त मली जी ने जो साल 1987–88 का बजट पेश किया वह बहुत ही सराहनीय है । यह गरीबों के हित का बजट अक्ष और किसान भाइयों को बहुत राहत देने वाला बजट है । इसमें व्यापारियों को भी कई तरह की छूटें दी गई हैं और नौकरी करने वालों को भी कई तरह की रियायतें दी गई हैं । चेयरमैन महोदय, हमारी राजस्व प्राप्ति 127507 करोड़ रुपये की होगी और खर्चा 1०84 34 करोड़ रुपये का होगा । इस तरह से सरप्लस 190. 73 करोड रुपये का होगा जिसमें से भिन्न भिन्न कटौतियां करने के बाद घाटा 34.63 करोड़ रुपये का रह जाएगा । यह घाटा टैक्स की बैटर रियेलाइजेशन से और नौन–प्लान

ऐक्सपैंडिचर में इकोनोमी करने से पूरा किया जाएगा । चेयरमैन महोदय, सिंचाई और बिजली के लिए 195 करोड़ रुपया सरकार खर्च करना चाहती है । यह बहुत ही ज्यादा सराहनीय काम है । सिंचाई और बिजली प्रदेश की तरक्की का एक ऐसा सायन है जिसकी वजह से प्रदेश में –अनाज का उत्पादन बढ़ेगा । बिजली की वजह से उद्योग भी बढ़ेंगे और औद्योगिक उत्पादन भी बढ़ेगा और सरकार को बहुत ज्यादा टैक्स मिलेगा । अनाज का उत्पादन ज्यादा बढ़ने से किसानों का स्तर ऊपर उठेगा । चेयरमैन साहब, पिछले दिनों मुख्य मंत्री चौधरी बंसी लाल जी ने जो खालों के पक्का करने पर आए खर्च के 113 करोड़ रुपयों की वसूली न करने का एलान किया वह बहुत ही सराहनीय काम किया है । इसके अलावा, चौधरी बंसी लाल जी ने जो जमीन का मालिया माफ किया है उसकी वजह से किसान भाइयों को बहुत ज्यादा खुशी हुई है । (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए । ) अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के जो भाई अपने आपको किसानों का असली हितैषी समझते हैं उनको भी हरियाणा में राज करने का समय मिला था । उनकी सरकार 1977 में बनी थी । मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने जो खाल पक्के करने का 113 करोड़ रुपया माफ किया है उसे माफ करने से चौधरी देवी लाल जी को किसने रोका था? चौधरी देवी लाल जो ने उसे अपने कलम से क्यों माफ नही किया?

स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से सिंचाई तथा बिजली मत्री जी से एक प्रार्थना करना चाहता हूं । मेवात प्रोजैक्ट कैनाल की प्रोपोजल सरकार के विचाराधीन है । मेरी प्रार्थना है कि प्रशासकीय अनुमति देकर के उसके काम को जल्दी से शुरु किया जाए ताकि वहां के किसान भी प्रदेश के दूसरे इलाकों के किसानों की तरह अपने खेतों से दो फसल ले सकें और खुशहाल हो सकें । अध्यक्ष महोदय, इस काम। के शुरु होने से उन 40 गांवों के लोगों को भी काम मिलेगा जिनकी फसलें ओला– वृष्टि से खराब हुई हैं । इसके अलावा, इस तरहं से तावडू. क्षेत्र, पटौदी, गुडगांव शहर, जहां हुड्डा की तरफ से सैक्टर्ज बनाए गए हैं, को पानी मिलेगा । इसलिए मैं एक बार फिर प्रार्थना करूंगा कि मेवात प्रोजैक्ट कैनाल की प्रशासकीय अनुमति देकर के काम को जल्दी से जल्दी शुरु करवाया जाए ।

अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री, श्री राजीव गांधी जी ने हरियाणा की डिवैल्पमैंट के लिए 403 करोड़ रुपये देने का जो एलान पलवल में किया, उसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं । उनके इस फैसले के लिए भी कि एस० वाई० एल० नहर का सारा खर्चा केन्द्रीय सरकार उठायेगी हम उनके कृतज्ञ हे । स्पीकर साहब, सही मायनों में तो हरियाणा की डिवैल्पमैंट का श्रेय स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गाधी जी को जाता है जिन्होंने इस प्रदेश को 1966 में अपनी कलम से बनाया था और समय समय पर इतना पैसा दियार जिसकी वजह से हरियाणा तरक्की के लिहाज से भारतवर्ष

में नम्बर 2 पर आ' सका । चौधरी बंसी लाल जी पहले भी इस प्रदेश के लगभग साढ़े सात साल मुख्य मंत्री रहे हैं और इनके कार्यकाल में जो प्रगति प्रदेश ने की वह कम सराहनीय नही है । लेकिन श्रीमती गांधी जी का, जो आज हमारे बीच में नही हैं, सारा हरियाणा प्रदेश हमेशा ऋृणी रहेगा । सन 1966 में जब हरियाणा बना था तो दुसरे प्रदेशों का यह विचार था कि हरियाणा अपने नौकरी पेशा कर्मचारियों को तनख्वाह भी नही दे सकेगा और यह प्रदेश टूट जाएगा और तीन तीन, चार चार जिले जो साथ लगते प्रदेश है उनको बाट दिए जाएंगे लेकिन श्रीमती गाधी जी, जो स्वर्ग में है, की वजह से और चौधरी बंसी लाल जी की रहनुमाई के अन्दर सन 1968 से 1975 तक जो प्रगति हरियाणा ने कीं, वह अनुकरणीय है । आज हिन्दुस्तान के अन्दर हमारा प्रदेश तरक्की के लिहाज से सबसे आगे है ।

अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले कहा, आज चौधरी देवी लाल जी बहुत दावा' करते है किसान भाइयो का हितैषी होने का लेकिन जब उनको हरियाणा में राज्य करने का मौका मिला था और पंजाब के मुख्य मत्री उनके पगडी बदल यार सरदार प्रकाश सिंह बादल थे, वे एम ० वाई ० एल ० नहर को नहीं बनवा सके । एस ० वाई ० ० नहर तव बनती अगर उनकी नीयत साफ होती । स्पीकर साहब अगर यह नहर उभ समय बनाई जाती, तो कम पैसे में बन जाती लेकिन उन्होंने हरियाणा के हित को नही देखा । वे तो हमेशा अपने दोस्त प्रकाश सिंह बादल को खुश करने की

बात करते रहे । अध्यक्ष महोदय, लगभग साढ़े चार साल के अर्से के अन्दर चौधरी देवीं लाल जी जब एक दिन के लिए सैशन में आए तो उन्होंने केवल एक बात कही कि अगर पंजाब में जाति चाहते हैं तो श्री प्रकाश सिंह बादल को पंजाब का मुख्य मत्री बना दिया जाए । वहां उस समय कांग्रसे सरकार थी और सरदार दरबारा सिह जी मुख्य मत्री थे । क्या उन्होंने कभी सोचा है कि जो प्रकाश सिंह बादल हमारे हरियाणा के फायदे के लिए बनने वाली एस ० वाई ० एल ० नहर को तोड़ने के लिए संघर्ष शुरु कर सकता है, उसकी' उन्हें वकालत नही करनी चाहिए? लेकिन इन सब बातों के बावजूद आज चौधरी देवी लाल जी ढिंढोरा पीटते हैं कि वे किसानों के सच्चे हितैषी है । अध्यक्ष महोदय, आप यह भी याद करें कि सन् 1977 में सरदार प्रकाश सिंह बादल और चौधरी देवी लाल दोनों ने मिल क्र एस ० वाई ० एल ० के केस को मुप्रमि कोर्ट ने डाल दिया था । वर्ष 1981 में केन्द्रीय सरकार में राव बीरेन्द्र क्हि जी कृषि और सिंचाई मंत्री होतें थे । उन्होंने तीनों मुख्य मत्रियों को बैठा कर वह केस सुप्रीम कोर्ट से वापस करवाया था और श्रीमती इंदिरा गांधी की क्रुपा से हरियाणा को 3 5 एम ० ए ० एफ ० पानी मिला था । उनके कर कमलों से ही कपूरी गाव मे एस ० वाई ० एल ० नहर की खुदाई के काम का उद्घाटन हुआ था लेकिन आज विपक्ष के भाई हरियाणा की जनता को बरगलाते फिर रहे है ।

स्पीकर साहब, हमारे वित्त मंत्री जी ने सड़कों के लिए 5.2 करोड़ रुपये का प्रोविजन इस बजट में रखा है जो कि बहुत कम है । मैं वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस पैसे को बढ़ाया जाये । स्पीकर साहब, रिवाडी में मीटर गेज की पांच रेलवे लाईने हैं । मेरे ख्याल में किसी भी जगह हरियाणा में मीटर गेज पांच रेलवे लाईनें नहीं जाती हैं । वहां –पर 24 घण्टे में आठ घण्टे रेलवे फाटक बन्द रहती है । वहां पर रेलवे पुल की आवश्यक्ता है और इस पुल के लिए सरकार के पास केस गया हुआ है । इसलिए मेरा निवेदन है कि जब उस पुल के लिए सरकार के पास केस गया हुआ है तो उसे अनुमति दे कर तुरन्त बनवाने का प्रबन्ध करें । जो फाटक 24 घण्टे में आठ घण्टे बन्द रहता है उससे जनता को काफी दिक्कत होती है । अगर यह पुल बन जायेगा तो उससे जनता को काफी राहत मिलेगी ।

स्पीकर साहब, वित्त मंत्री जी ने परिवहन विभाग के लिए 13 करोड़ रुपया खर्च करने का प्रस्ताव रखा है । परिवहन मली जो भी यहां पर बैठे हुए हैं, मैं उनसे एक ही निवेदन करूगा कि जब हरियाणा प्रदेश की ट्रांसपोर्ट सब से आगे है तो सफाई के मामले में सब से पीछे क्यों है? मुझे पिछले दिनों बंगलौर जाने का अवसर मिला । वह प्रदेश सफाई के लिहाज से नम्बर एक पर है । जब हमारे प्रदेश के बस अड्डे इतने अच्छे ढंग से बनाये गये हैं तो उनकी सफाई इतनी अच्छी क्यों नहीं होती है? इसलिए मैं परिवहन

मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उनेकी सफाई की ओर विशेष ध्यान दिया जाये ।

स्पीकर साहब, वित्त मंत्री जी ने तकनीकी शिक्षा पर 4.5 करोड़ रुपया रखा है । मैं तकनीकी शिक्षा के बारे में अपने हल्के की बात भी हाउस में रखना चाहता हूं । मेरा पटौदी का क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है । वहां पर उससे बड़ा कोई कस्बा नही है । इसलिए वहां पर एक आई० टी ० आई० की शाखा खोली जानी चाहिए ताकि वहां पर जो गरीब और किसानों के बेटे हैं तकनीकी शिक्षा पा कर रोजगार प्राप्त कर सकें । जो लोग आज के दिन केवल खेती पर ही निर्भर करते हैं उनके बच्चे आई० टी ० आई० से पढ़ कर दस्तकारी का भी काम कर सकेंगे और उनका जीवन स्तर भी ऊंचा उठ सकेगा ।

अनुसूचित जाति के भाइयों को ऊंचा उठाने के लिए हर साल काफी स्कीमें बनती हें । पिछले दिनों अनुसूचित जाति के भाइयों को 33 प्रतिशत अनुदान दे कर हरिजन कल्याण निगम से कर्जा दिलाया गया था । यह सारा श्रेय श्रीमती इन्दिरा गांधी जी को जाता है । जब सन् 1969 में इन्दिरा जी ने बैकों का राष्ट्रीयकरण किया तो उसके बाद से हर भारत का नागरिक बैक से उद्योग के लिए कर्जा ले सकता है । सन् 1969 से पहले इन बैंकों से बड़े बड़े लोग ही फायदा उठाते थे । इन बैकों के राष्ट्रीयकरण से हरिजन भाइयों को सब से बड़ा लाभ यह हुआ कि 20 परसैन्ट नौकरियां उनके लिए रिजर्व हो गई जिसके कारण

हरिजनों के बच्चे नौकरियों में लगे । सन् 1969 से पहले ये बैक इसी प्रकार थे जिस प्रकार पहले हरिजन मन्दिर में नहीं जा सकता था । वह बैक में कर्जे के लिए भी नहीं जा सकता था । हरिजनो के पास पैसा जमा करने के लिए तो होता नही था इसलिए वे बैकों में नही जाते थे और न ही उन्हें वहां नौकरियां मिलती थी । सन् 1969 में बैकों का राष्ट्रीकरण होने के बाद 20 परसैन्ट नौकरियां मिली और कर्जे भी मिलने लगे । उन्होंने यह बहुत ही सराहनीय कार्य किया था ।

स्पीकर साहब, हमारे मुख्य मत्री जी ने अभी पिछले दिनों केन्द्र सरकार के चौथे दे कमीशन की रिपोर्ट मान कर बहुत ही बढिया काम किया है । नौकरी पेशे वालों के लिए किसी भी प्रदेश में चौथे पे कमीशन की सिफारिश नहीं मानी गई है लेकिन हरियाणा सरकार ने चौथे पे कमीशनें की रिपोर्ट को मान कर एक नम्बर का बढ़िया काम किया दूसरे प्रदेशों के अन्दर यह रिपोर्ट अभी तक मानी नहीं गई है । हरियाणा के पहले मुख्य मंत्री हैं जिन्होंने इस पे कमीशन की रिपोर्ट को माना है । इसलिए मेरी नौकरी पेशा भाइयों से एक अपील है कि विपक्ष के भाइयों के कहने पर जो वे गलत पालिसी अपनाये हुए हैं वह उनके हित में नहीं है । जब मुख्य मंत्री जी ने पे कमीशन कनई रिपोर्ट को मान लिया है तो उन्हें ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए । हमारी सरकार ने पैन्शन के मामले में भी काफी छूट दी है । इन शब्दों. के साथ मैं वित्त मैली जी ने जो बजट पेश किया है उसका समर्थन करता

हूं । उन्होंने एक अच्छा बजट पेश किया है । इतमें कोई भी कर नहीं लगाया है । उद्योग– पतियों का भी टैक्स माफ किया है । चूड़ियों पर भी टैक्स माफ करके सरकार ने एक सराहनीय कार्य किया है । अन्त में एक बार फिर मैं वित्त मली जी का आभार प्रकट करता हूं ।

**चौधरी सूजे सिंह पुनिया (ऊचाना कलां ) :** अध्यक्ष महोदय, आदरणीय वित्त मैली जी ने दो मार्च, 1987 को जो बजट पेश किया है मैं उसका अनुमोदन करने के लिए खड़ा हुआ हू । बजट को पढ्ने से महसूस होता है कि ग्राम उत्थान की तरफ पूरा पूरा ध्यान रखा गया है । इस बजट का 72 परसैन्ट रुपया पानी, कृषि और बिजली के लिए रखा गया है । यह इस बात का प्रतीक है कि हरियाणा में अन्नोत्पादन बड़ी तीव्रगति से बढ़ाया जायेगा ।

स्पीकर साहब, हमीर युवा प्रधान मत्री भी हमारे प्रदेश पर बड़ी कृपा दृष्टि रख रहे हैं । उन्होंने पलवल की जनसभा में 403 करोड़ रुपये की. सहायता देने की अनाउन्समैंट की थी जिसके कारण हमारे प्रदेश का विकास बड़ी तेजी से होगा, हरियाणा में खुशहाली आयेगी तथा विकास और निर्माण के कार्य बड़ी तेजी से होंगे ।

**12.00 बजे**

स्पीकर साहब, आदरणीय राजीव गान्धी जी ने प्रशासन में एक नयी दिशा दी है वह है ईमानदारी और स्वच्छता की । वे

राष्ट्र से भष्टाचार का उन्मूलन करना चाहते हैं । उन्ही के नक्शे कदम पर चलते हुए हमारे मुख्य मैली चौधरी बंसी लाल जी ने भी एक नई सोच दी है वह है स्वच्छ प्रशासन और विकास के कार्य । बजट में भिन्न मदों पर पैसा रखा गया है । मैं एक एक मद्द पर बहस करना चाहता हूं । आप जानते हैं कि हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है । कृषि के क्षेत्र में पैदावार बढ़ाने के लिए सिंचाई आवश्यक है । स्पीकर साहब, पंजाब समझौते के मुताबिक एस० वाई० एल० का निर्माण 15 अगस्त, 1988 तक होना था लेकिन दुर्भाग्य से पूरा नहीं हो सका । सदन के नेता और सदन के सभी सदस्य बार–बार सदन में और बाहर भी यह कह चुके हैं कि इस नहर का निर्माण कार्य केन्द्रीय सरकार को अपने हाथ में लें लेना चाहिये ताकि इस नहर का निर्माण कार्य जल्दी से जल्दी पूरा हो सके, इस नहर के पानी से हरियाणा की रेतीली भूमि की सिंचाई हो सके, हरियाणा की पैदावार बढ़ सके, लोगों का जीवन खुशहाल हो और लोगों का जीवन–स्तर भी ऊंचा हो । अध्यक्ष महोदय, एस० वाई० एल० हरियाणा की जीवन रेलो है । इस नहर का पानी आने से हरियाणा की बहुत तेजी से तरक्की होगी, तेजी से पैदावार बढ़ेगी और हरियाणा के लोगों का जीवन स्तर भी ऊंचा होगा । इसके अलावा बिजली की. मद पर भी काफी पैसा रखा गया है । आज कल बिजली रोजमर्रा के कामों के लिये बहुत आवश्यक हो गयीं. है । विशेष तौर पर देहातों में पीने के पानी के लिये लोग बिजली का काफी इन्तजार करते हैं । चारा, भूसा और आटा पीसने के लिये भी लोग बिजली का इन्तजार करते हैं

लेकिन बिजली कई बार आती ही नहीं है । कुछ दिन पहले बिजली की स्थिति थोड़ी कमजोर रही है लेकिन अब स्थिति काफी सुधर रही है । आप यह देखें कि बिजली की मांग और पूर्ति में काफी फर्क है । इसी बात को देखते हुए 34 परसैट पैसा बिजली के लिये रखा गया है । इस मद के लिये यह काफी' ज्यादा पैसा रखा गया है भविष्य में उम्मीद यह है कि बहुत सी ऐसी योजनाएं जो अभी निर्माणाधीन हैं, वह जल्दी से जल्दी पूरी होंगी और लोगों की ' मांग और पूति का अन्तर कम होगा । इस बजट में यह दर्शाया गया है कि आने वाले साल में यानी 1987–88 में 20,000 ट्यूबवैल कनैक्शन्ज दिये जायेगे जिससे इरीगेशन और बढ़ेगी हमारे माननीय मंत्री जी हाउस में मौजूद हैं । मैं आपके माध्यम से इनसे एक प्रार्थना करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में पिछले दिनों 18 फरवरी और 24 फरवरी की रात को काफी बड़ी ओला–वृष्टि हुई है । उससे 12– 13 गांवों की फसलें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गयी हैं । उनमें से 5–6 गांवों के कुछ लोगों ने ट्यूबवैल कनैक्शन्ज के लिये दरख्वास्तें दी हुई हैं । वहां पर नीचे का पानी बहुत अच्छा हए । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि उन किसानों को जिन्होंने ट्यूबवैल के कनैक्शन के लिये प्रार्थना पल दे रखे हैं उन्हें प्रायरिटी के आधार– पर कनैक्शन दिया जाये ताकि वह अपनी क्षतिपूर्ति करने में समर्थ हो सकें और आर्थिक तौर पर भी सम्पन्न हो सकें ।

इसके अलावा पशुपालन और मछलीपालन की बात भी बजट में आयी है । अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात बड़ी गम्भीरता से कहना चाहता हूं कि हरियाणा में बेरोजगारी की बहुत गम्भीर समस्या है । देहातो में विशेष कर बेरोजगार पढे लिखे और अनपढ किसानों में यह गम्भीर रूप धारण करती जा रही है । कृषि का सहायक उद्योग–धन्धा पशुपालन, मुर्गीपालन और मछली पालन है । इनके अलावा रेशम उद्योग है, खुम्बियों की खेती है या फूलों की खेती है । मेरे कहने का मतलब यह है कि यह सभी खेतीबाड़ी के सहायक उद्योग धन्धे हैं । मैं आपके' माध्यम से सरकार से यह अनुरोध जरूर करूंगा कि वह किसानों को बचाये । अध्यक्ष महोदय आप खुद एक किसान हैं । आपको पता है कि खेती के लिये जमीन तो बढ़ेगी नहीं । पहले ही जोते बहुत छोटी होती जा रही हैं । एक–एक, दो–दो एकड़ के मालिकान आ गये हैं और बेरोजगारी से नौजवान लोग परेशान हैं । अगर कृषि और कृषि के सहायक उद्योग धन्धों को उद्योग के रूप में मान्यता दे दी जीये तो नौजवानों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी । खास कर उन नौजवानों को जिनके पास भूमि कम है –या भूमिहीन परिवार से सम्बन्ध रखते हैं । मुर्गीपालन, पशुपालन, मछली पालन, खुम्बियों की खेती इत्यादि को भी यदि सरकार उद्योग धन्धों के रूप मैं मान्यता दे दे तो इससे बड़ी भारी सहायता मिलेगी ।

अध्यक्ष महोदय, जमीन खरीदने के लिये 13 प्रतिशत रजिस्ट्री का खर्चा देना पड़ता है । इसके अलावा दूसरे खर्चे भी हैं

। अगर कृषि और उसके सहायक उद्योग–धन्धों को उद्योग के रूप में मान्यता दे दी जाये तो उन्हें भी सबसिडी जमीन खरीदने के लिए मिल सकती है जिससे बेरोजगार लोगों को सहायता मिल सकेगी और उनको रोजगार के ज्यादा अवसर भी जुटाये जा सकेंगे । इससे बेरोजगारी की स्मस्या पर भी कुछ हद तक काबू पाया जा सकेगा ।

सहकारिता के विषय में भी मैं अर्ज करना चाहूंगा । हमारे इलाके में सहकारी क्षेल में एक शूगर मिल है । इसका एरिया 24 किलोमीटर का है । इस एरिया के अन्दर कुछ गांव ऐसे भी हैं जो सड़कों से सीधे नहीं मिले हुए हैं । लोगों को घूमकर लैटर पर या मिल के गेट पर जाना पड़ता है । प्रावधान यह है कि 8 किलोमीटर रेडियस के जो गांव हैं, अगर वहां के लोग गन्ना देंगे तो वह मिल के गेट पर गन्ना लेकर आयेंगे । जो भी किसान वहां पर गन्ना लेकर आयेगा, उसको ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन चार्जिज देने पड़ेंगे । मेरे इलाके में कुछ गांव ऐसे हैं जैसे बरनपुर और भींसला, वहां से दो किलोमीटर का चक्कर लगाकर जाना पड़ता है । अगर उनको मोहनगढ और झील से मिला दिया जाये तो वहां के लोगों को काफी सहूलियत मित्र सकती है । सिर्फ दो–अढाई किलोमीटर का टुकड़ा है । इससे सरकार को और मिल को भी ट्रांसपोर्टेशन चार्जिज कम देने पड़ेगे ।

इसके अलावा मेरे इलाके में कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर पानी टेल तक नहीं पहुंचता । मिल के अधिकारियों ने भी सरकार

को यह लिखा है कि 15 दिन के लिये इस नहर में पानी छोड़ दिया जाये ताकि वहां के इलाके में गन्ना बोया जा सके ।

इसके अलावा बजट में सड़क, परिवहन और शिक्षा के लिये भी पैसा रखा गया है । शिक्षा के क्षेत्र में सरकार लड़कियों की शिक्षा के लिये ध्यान दे रही है । लड़कियों की शिक्षा के लिये बहुत से प्राइमरी स्कूल खोलने का प्रस्ताव भी है । मेरे इलाके में एकें कन्या गुरुकुल गैडाखेडा है । वहां के लोगों ने 20–25 लाख रुपया इस संस्था के भवन निर्माण पर खर्च किया है । 2– 3 मात्र से यह बड़े सुचारु रूप से चल रही है । मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि इसको स्थायी रूप में मान्यता दे दी जाये ताकि जो अनुदान के रूप में राशि इनको मिल सकती है, वह मिलने लग जाने और यह संस्था अच्छी तरह से चल सके । धन्यवाद ।

**श्री भले राम (बड़ौदा–अनुसूचित जाति ) :** स्पीकर साहब, दो दिनों से बजट पर बहस चल रही हए और मेरे से पहले साथियों ने भी बजट की प्रशंसा की है । प्रशंसा बिल्कुल ठीक की है क्योंकि जो बजट पेश किया गया है, वह सारी बातों को ध्यान में रखते हुए बैलैल्हड बजट है । बजट बनाते समय यह जरूर सोचा जाता है कि जिस मद में धन की ज्यादा आवश्यकता है, इन आर्डर आफ प्रायरिटी चाहे वह एग्रीकल्चर का बजट हो या बिजली का हो, रख दिया जाता है । जिस प्रकार घर का मालिक अपना बजट बनाते समय खाने का ज्यादा ध्यान रखता है और फिर कपड़े आदि का, ठीक इसी प्रकार से स्टेट का बजट होता है । हमारे

वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है. वह सभी बातों को छगन में रखते हुए किया है जिनका मैं इसमें कुछ जिक्र करूंगा । हमारी स्टेट की क्उ?ल आमदनी 1970–71 में 4654 करोड़ रुपये थी लेकिन 1985–86 में यह बढकर 5379 करोड़ रुपये हो गई । स्पीकर साहब, इसके साथ ही साथ मैं यह भी बताना बहुत जरूरी समझता हु कि हमारी स्टेट के जो नागरिक हैं उनकी पर–कैपिटा इंकम जो 1984–85 में 3259 रुपए थी वह 1985–86 में बढ़कर 3669 रुपए हो गई । इससे जाहिर होता है कि यह बहुत प्रोग्रैसिव बजट है । स्पीकर साहब, जो सातवी फाईव ईयर पन है वह 2900 करोड़ रुपए की है । उसमें ज्यादा पैसा सिंचाई, बिजली और सोशल फेयर पर खर्च किया जाएगा । दूसरे कामों पर भी पैसा खर्च किया जाएगा लेकिन ज्यादा पैसा इन तीनों पर खर्च किया जाएगा । 1986–87 की वार्षिक योजना के लिए 525 करोड़ रुपया रखा गया या । सामाजिक–आर्थिक विकास की गति में तेजी लाने के लिए अब इस राशि को बढ़ाकर 589 करोड रुपया कर दिया गया है । इससे जाहिर होता है कि हमारी स्टेट हर प्रकार से प्रगति की राह पर है । मैं सब से पहले सोशल वैलफेयर और शिड्यूल्ड कास्ट्स के बारे ने कुछ बोलना चाहूंगा । स्पीकर साहब, ये लोग सदियों से दबे हुए थे और जब देश आजाद हुआ था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि दुमें राजनैतिक आजादी तौ प्राप्त हो गई है लंकिन अब आर्थिक और सामाजिक आजादी प्राप्त करनी है और उन लोगों को आगे बढ़ाना है जो सदियों से आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं । हमारी

सरकार ने इस ओर विशेष ध्यान दिया है और वित्त मंत्री जा' ने इस काम के लिए दस करोड़ रुपए से ज्यादा रखे हैं । स्पीकर साहब, यह रुपया हरिजन बच्चों की फीस माफ करने पर खर्च होगा, हरिजन लड़कियों को जो मुफ्त वर्दी दी जाती हैं उन पर खर्च होगा, हरिजन बच्चों को जो वजीफे दिए जाते है उन पर खर्च होगा और हरिजन बच्चों को जो किताबें मुफ्त दी जाती हैं उन पर खर्च होगा । इस पैसे में से हरिजन बच्चों को जो कोचिंग दी जाती है उस पर भी यह पैसा खर्च होगा । इन प्रोत्साहनों से लाभ उठाने वाले विद्यार्थियों की इस समय 2.04 लाख की संख्या बढ़कर वर्ष 1987–88 के दौरान 2.96 लाख हो जाएगी । सीकर साहब, हरिजनों के कल्याण के लिए एक हरिजन कल्याण निगम बनाई हुई है । निगम ने चालू वर्ष के दौरान अनुसूचित जातियों के 16,000 लाभ–ग्राहियों तथा पिछड़े वर्गों के 4,000 लाभ–ग्राहियों को सहायता प्रदान की है । अगले साल यह निगम और भी स्कीम्ज शुरू करने जा रही है जिससे हरिजन तथा पिछड़े वर्ग के लोगों को ज्यादा फायदा होगा । स्पीकर साहब, मैं एक बात सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं । कुछ स्कीम्ज ऐसी हैं जो बहुत पुरानी हो चुकी है और उन स्कीम्ज से बच्चों को बड़ी डिफिकल्टी होती है । मिसाल के तौर पर ग्यारहवीं क्लास से लेकर बी ० ए० तक हरिजन बच्चों को दो सौ रुपया मिलता है । यह रुपया उनको किताब और स्टेशनरी की दूसरी चीजें खरीदने के लिए मिलता है । बी० ए० के बाद एम० ए० तक के लिए चार सौ रुपया मिलता है । स्पीकर साहब, इस दो सौ या चार सौ

रुपए को लेने के लिए जो प्रोसीजर है वह बहुत ही कम्पलीकेटिड है ।दो सौ रुपया लेने के लिए तीन रुपए का एक स्टाम्प पेपर लेना पड़ेगा । सवा दो रुपए का ऐग्रीमैंट बौड और उसके साथ दस पैसे का डी० फार्म । उसके पश्चात उसको टाईप कराना पड़ेगा । पांच दस रुपए टाईप कराने पर लग जाएंगे । दो गवाही विटनैस के तौर पर होंगी और एक शियोरिटी होगी । दो सौ रुपया लेने के लिए इतनी फारनेलटीज पूरी करनी पड़ेगी । स्पीकर साहब, बैक से जब पांच हजार रुपया लेते हैं तो वहां कोई गारन्टी नहीं है । पर्सनल शियोरिटी पर पैसा मिल जाता है तेकिन दो सौ या चार सौ रुपया लेने के लिए इतने झमेले करने पड़ते हैं । मैं बहन जी से प्रार्थना करूंगा कि इस मामले पर गौर करें और हरिजन बच्चों की इस डिफिकल्टी को दूर करें । स्पीकर साहब, दूसरी बात यह है कि शड्यूल्ड कास्ट्स के बच्चों से शड्यूल्ड कास्ट होने का सर्टिफिकेट लिया जाता है । यह सर्टिफिनेट पांचवी में लेते हैं, आठवीं में लेते हैं और फिर दसवीं में लेते हैं । मेरी सजेशन यह है कि स्कूल में एक ही बार यह सर्टिफिकेट लेना चाहिए । एक बार जिसने हरिजन लिख दिया वह हमेशा ही हरिजन रहेगा । बार–बार सर्टिफिकेट लेने की कोई जरूरत नही है । दसवीं का या बी ० ए० का जो सर्टिफिकेट है उसमें एक कौलम बना दिया जाए जिसमें अगर वह हरिजन है तो वह लिख दिया जाए जिससे वह कभी इंटरव्यू के लिए कहीं जाए तो पता लग जाए कि वह शड्यूल्ड कास्टस है । सरकार से मेरी प्रार्थना है कि मेरी इस बात पर गौर किया जाए ।

स्पीकर साहब, शड्यूल्ड कास्ट्स बच्चों से इन्कम का सर्टिफिकेट लिया जाता है । जिस फैमिली की दस हजार की इन्कम है उसको सरकार की ओर से रियायतें मिलती हैं । यह बहुत पुरानी लिमिट है । मेरी प्रार्थना है कि यह लिमिट अठारह हजार कर दी जाए । स्पीकर साहब, इस बजट में सभी लोगों को काफी रियायतें दी गई हैं । खासतौर पर मैं मुलाजिमों का जिक्र करूंगा । हरियाणा स्टेट पहली स्टेट है जिसने केन्द्रीय सरकार के वेतन मान अपने कर्मचारियों को दिए हैं । 25 तारीख से पहले मुख्य मन्त्री चौधरी बंसी लाल ने इस बात का एलान कर दिया था कि सैन्टर्ल ग्रेड पहली अप्रैल से दे दूंगा लेकिन इसके बावजूद 25 तारीख को बहुत से मुलाजिमों ने छुट्टी ले ली । जब उनकी सारी मांगे मानी जा रही हैं तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए । उनको सोचना चाहिए कि स्टेट गवर्नमैंट के और बहुत से खर्चे हैं और सरकार ने बहुत सारे काम करने हैए । उनको विचारना चाहिए कि केवल कर्मचारियों को पैसा नहीं देना है बल्कि स्टेट में डिवैल्पमैंट के दूसरे काम भी करने हैं । उनको कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जो स्टेट के हित में न हो ।

स्पीकर साहब, अब मैं फ्लड के बारे में कहना चाहता हूं। हर साल कहीं न कहीं फ्लड आ जाता है । मेरी प्रार्थना है कि इनका कोई परमानैन्ट इलाज कर दिया जाए । जब भी कोई आपत्ति आती है तो सरकार की तरफ से लोगों की हर किस्म की मदद की जाती है । पिछलें साल भी यह मुसीबत आई और केन्द्र

ने सवा सतरह करोड़ रुपया दिया । सरकार ने फारमर्ज को खाद तथा बीज पर सबसिडी दी और बहुत सी जगहों पर तकावी लोन माफ किया । सरकार ने गांवों के अन्दर बहुत से काम शुरू किए जिससे कि लोगों को रोजगार मिल सके । जब भी कोई नैचुरल कैलेमिटी आई है तो सरकार ने लोगों की पूरी मदद की है । अभी पिछले दिनों स्टेट में बहुत सी जगहों पर ओले पड़े । मुख्य मन्त्री जी ने दिल खोलकर लोगों की मदद का एलान किया । स्पैशल गिरदावरी कराने का एलान किया अरि चार करोड़ रुपया लोगों की मदद के लिए दिया । इसलिए इस बजट को फारमर्ज का बजट भी कहा जा सकता है ।

स्पीकर साहब, अब मैं रोड्ज का जिक्र करूंगा । वर्ष 1987– 88 के लिए 52 करोड़ रुपया रखा गया है । चौधरी बंसी लाल ने एलान किया है कि हर गांव को सड़क से जोड़ दिया जाएगा । स्पीकर साहब, कुछ सड़कें बहुत जरूरी हैं और उनका डिस्टैंस भी कम है । मेरी प्रार्थना हए कि उन सड़कों को जरूर बनाएं । जहां पर लोगों को कोई कम्पनसेशन नहीं देना पड़ता और वहां दो तीन किलो मीटर की सड़क बननी है उनको टौप प्रायरिटी देनी चाहिए । बहुत सी सड़कें टूटी पड़ी हैं लेकिन यह बहुत मुश्किल होगा कि सभी सड्कों की मरम्मत की जाए, आहिस्ता– आहिस्ता यह मरम्मत का काम किया जाना चाहिए ।

स्पीकर साहब, हमारे यहां बेरोजगारी की समस्या काफी है । इस बारे में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं । स्पीकर साहुब,

मशरूम जिसको हमारे देहात में खुम्बी कहते हैं इसका बिजनैस काफी प्रौफिटेबल है । इसके लिए ज्यादा जमीन भी नही चाहिए । यह घर में ही शैड बनाकर उगाई जा सकती है ।

**श्री अध्यक्ष :** आपका टाईम खत्म हो गया है । अब आप खत्म करें ।

**श्री भले राम :** मुझे आप थोड़ा सा टाईम और दे दीजिए । स्पीकर साहब, मैं कह रहा था कि मशरूम का विजनैस अगर हमारे नौजवान शुरू कर दें तो काफी हद तक बेरोजगारी खत्म हो सकती' है । इसका बीज हमारे यहां ऐग्रीकल्चर यूनि–वर्सिटी मे नहीं मिलता । इसका बीज सोलन में मिलता है । स्पीकर साहब, इसको दिल्ली की मार्किट में बेचा जाता है । इस पर कंट्रोल होना चाहिये । मशरूम की पैदावार के लिये सरकार को लोगों के लिये सबसिडी व लोनज देने चाहियें और इसके साथ साथ परचेजिंग सैन्टर्ज का प्रबन्ध भी सरकार की ओर से होना चाहिये । यह एक बहुत अच्छा धन्धा है जिससे हमारे नौजवान साथियों को काफी फायदा होगा । सरकार को इसके लिये कोई न कोई टेर निंग देने का भी प्रबन्ध करना चाहिये ताकि नौजवान मायी घर बैठे ही अपना धन्धा कर सके । इससे आगे स्पीकर साहब, मैं गोहाना में आई ० टी ० आई ० के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा । पहले वह आई ० टी ० आई– ० का काम पब्लिक हैल्थ सैन्टर की बिल्डिग में चलाया जा रहा हए, अव वहां पर जुलाई में बिल्डिग बनकर तैयार हो जाएगी । स्पीकर साहब, वहां

पर इस वक्त कुछेक ट्रेडज नही हैं जैसे बिजली, मिस्त्री, लोहार, ट्रैक्टर मिस्त्री और वैल्डर वगैरह । इन के वहाँ न हे के कारण लड़को को सोनीपत या पानीपत जाना पड़ता है जिससे उनको काफी दिक्कतें आती हैं । इसलिये मेरी प्रार्थना है कि गोहाना के अन्दर जब जुलाई के महीने में आई ० टी ० आई ० की बिल्डिग बनकर तैयार हो जाएगी तो वहां पर इन ट्रैडज को भी इंट्रोड्यूस किया जाए । जिससे इस इलाके के बच्चों को और दूसरे अन–ऐम्पलायड को फायदा हो सके । इन शव्दों के साथ मैं इम बजट भाषण का जोरदार समर्थन करता हुआ और आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हू क्योंकि आपने मुझे बोलने का समय दिया ।

**बहिन शांति देवी ( करनाल ) :** अध्यक्ष महोदय, सदन में जो बजट पेश किया गया है, मैं इसका समर्थन करती हई थोड़े से शब्दों में अपने विचार इस सदन के सामने रख रही हू । सभी जानते हैं कि बजट बनाना भी एक कला है । भूतकाल की वास्तविक आय और वास्तविक व्यय को दृष्टि में रखकर, भविष्य के लिये अनु– मानित आय और अनुमानित व्यय के लेखे. जोखे को रखना, वास्तव में बजट कहलाता है । वजट बड़ा ध्यानपूर्वक और चिन्तन, मनन से बनाकर रखा जाता है । घरेलू जीवन में नौकरी–पेशा परिवार में भी बजट बनाकर चलना बड़ा आवश्यक होता है । घर की गृहिणी के लिये यह बड़ा ही आवश्यक है कि वह अपने साधनों को ध्यान में रखते हुए, घर–गृहस्थी को चलाये

क्योंकि घर के सदस्यों के हर साल वस्त्र, भोजन, मकान, बच्चों की पढ़ाई और बच्चों के रहन सहन का ध्यान रखा जाता हए ताकि आगे आने वाले समय में परिवार के लिये दुविधा न हो सके । परिवार के लिये अगर कोई घाटे का बजट होग तो वह उस परिवार को बरबाद कर के रख देगा । अगर परिवारों का सन्तुलित बजट हो तो ब्याह–शादियों व दूसरे कामों के लिऐ ठीक नहीं होता है इसलिये बचत का बजट परिवार की बेहतरी के लिये जरूरी है । सरकारों के बजट तो प्रायः घाटे के ही बनते हैं । हमारी सरकार ने भी यहां पर घाटे का बजट पेश किया है और कोई नया टैक्स नहीं लगाया है । अतरू इस घाटे को पुराने पड़े टैक्स वसूल करके पूरा कर लेगी । – अगर टैक्स की वसूली सही ढंग से हो जाए तो सरकार का काम भीं सुचारू रूप से चल सकता है । सरकार को दान तो कोई देता– नहीं है, लेकिन उल्टा सरकार से अनुदान लेते हैं । इस बजट के बारे में तो मैं यही कह सकती हूं कि यह बजट बहुत अच्छा है और इसमें कृषि, परिवहन, सिंचाई, बिजली, खेलकूद, उद्योग, शिक्षा, चिकित्सा की देखरेख और बढ़ौतरी के लिये काफी रुपया दिया गया है । यह बहुत ही अच्छी बात हए । अध्यक्ष महोदय, जो हमारी कृषि है, उसका आधार बिजली और पानी है । इसलिये बिजली. और पानी की सप्लाई किसानों को पूरी होनी चाहिये ताकि खेती अच्छी हो, अच्छा बीज किसानों को उपलब्ध कराया जाए । इस से भी खेती अच्छों होने की संभावना है तथा उत्पादन बढ़ सकता है ।

अध्यक्ष महोदय, सरकार की ओर से किसानों का हर प्रकार से ध्यान रखा गया है ताकि किसानों का जीवन स्तर ऊंचा हो और वे देश के लिये और प्रदेश के लिये जी जान से काम करें और उत्पादन को बढ़ाये ।

अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्यमन्त्री महोदय जी के निवेदन पर श्री राजीव गांधी जी हरियाणा में आये थे । उस समय उनके सामने बिजली की समस्या रखी गयी थी ताकि हरियाणा को उचित मात्रा में बिजली की सप्लाई हो और हरियाणा को उसका पूरा शेयर मित्ने । पानीपत और फरीदाबाद के थर्मल प्लांटस ठीक काम करें तो वहां से बिजली के उत्पादन की कमी शीघ्र ही पूरी होने की संभावना है । इस बात के लिये बजट में पूरा प्रावधान रखा गया है ।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से हमारे हरियाणा में सड़कों का भी बड़ा महत्व है । किसानों की पैदावार को मंडियों तक पहुंचाना, गांव से गांव को मिलाना, यह तभी सम्भव हो सकता है जब हमारे प्रान्त में बड़ी माता में सड़कें होंगी । इसके लिये इस में बहुत अच्छा प्रावधान किया गया है । आपको पता ही है कि हमारे मुख्यमन्त्री महोदय ने पिछले कार्यकाल में सड्कों का जाल बिछाया था और उन सड़कों के जाल को आज और आगे बढ़ाने का बजट के अन्दर प्रावधान रखा गया है और साथ ही साथ उनकी मुरम्मत का भी प्रबन्ध किया गया है । पर्याप्त माता में इसके लिये पैसा उपलब्ध कराया गया है । हो सका तो मार्किट

कमेटियों से भी हुस काम के लिये और पैसा उपलब्ध कराया जा सकेगा ताकि किसानों और आम लोगों को आने जाने में किसी प्रकार की असुविधा न हो और हरियाणा की शान बढ़े । इसी तरह सरकार ने पशुपालन के लक्ष्य को बढ़ावा देने के लिये काफी उचित कदम उठाये हैं । किसान पशु रखते हैं, उनका पूरी तरह से ख्याल रखा गया है । किसान की कहावत है कि ' 'देशों में देश हरियाणा, जहां दूध दही का खाना '' । पशुओं के लिये बढ़िया स्वास्थ्य व्यवस्था जुटाने का सरकार ने प्र बन्ध किया है । आगामी साल में लगभग 4000 परिवारों को मुर्गी पालन, सूअर पालन, भेड़ों औंर बछड़ो के पालन हेतु सरकार के । तरफ से सहायता देने की संभावना है । यहां यह भी बताना मैं अपना कर्त्तव्य समझती हूं कि आज के युग में वनों का मनुष्य के जीवन में बड़ा महत्व है । जब इन्सान पैदा होता है तो उसे जन्म घुट्टी देते हैं और जब मरता है तो अन्त्येष्टि के समय वन की लकड़ी काम में आती है । अतः वन सम्पदा को बढ़ाना बहुत ही जरूरी है और इसके लिये बजट में पूरा प्रावधान रखा गया है । अगर इस पैसे का सदुपयोग होगा तो इससे हरियाणा को काफी लाभ होगा । हरियाणा में वनों के लिये खाली जमीन न होने के कारण सरकार ने वृक्षारोपण के अन्तर्गत खेतों की भेडों पर पेड लगाने रेल–पटरियों, सड़कों और नहरों के साथ की बंजर भूमियों के उपयोग द्वारा वनों को काफी महत्व दिया है । बरसाती पानी का सदुपयोग करके भूमि संरक्षण में काफी प्रभावशाली तरक्की की है । आपको पता है कि वनों के लगने से आय भी बढ़ेगी और वहां

का दृश्य भी बड़ा सुहावना और लुभावना दिखायी देगा । यही एक च। य वरण की शुद्धि का तरीका है । इससे न तो बीमारियां फैलेगी और न ही गन्दगी का फैलाव होगा । वृक्ष कार्बन डाइआक्साईड खाते हैं और 'मनुष्य के लिये आक्सीजन छोड़ते हैं जिसकी मनुष्य को सख्त जरूरत है । इसलिये सरकार का वनों का काम बड़ा ही सराहनीय है । वनों की लकड़ी से लोगों की रोजमर्रा की आवश्यकताओं की भी पूर्ति होती है । वनों से पानी मिलता है, पानी से रोटी मिलती है और रोटी से मनष्य मात को जीवन की उपलब्धि होती है । इसलिये मैं एक बार फिर यही कहूंगी कि वनों के लिये जो इस बजट में रुपया रखा गया है, वह बहुत ही आवश्यक था । अगर उसका सदुपयोग होगा तो हरियाणा अवश्य तरक्की के पग पर अग्रसर होगा ।

अध्यक्ष महोदय, हरियाणा की परिवहन सब से बढ़िया है । इस समय 322 नई बसें हरियाणा में लाने का प्रस्ताव है । प्रतिदिन 11 लाख वाली सफर करते हैं लेकिन ड्राईवर्ज और कंडक्टर्ज को कुछेक हिदायतें देने की जरूरत है । इनको इस लिहाज से और सावधान किया जाना चाहिये ताकि बस यात्रियों कौ किसी प्रकार की असुविधा न कुए । ठीक स्टापेजो पर बसों को रोका जाए और समय पर बसों को पहुंचाया जाए । करनाल के बारे में मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि अगर हरेक बस करनाल रुक कर जाए तो उससे करनाल वासियों को सुविधा प्राप्त होगी । इससे आगे मैं शिक्षा के बारे में भी सरकार से कुछ कहना

चाहती हूं । शिक्षा से मनुष्य का जीवन बनता है । इस प्रकार की शिक्षा बच्चों को दी जानी चाहिये जिससे मानव जीवन सुखी हो सके और उनका जीवन स्तर ऊंचा उठ सके । सरकार ने इस लिहाज से शिक्षा को बढावा देने के लिये बहुत से स्कूल, कालेज खोले हैं और प्राइमरी से मिडल और मिडल से हाई तक स्कूलों को अपग्रेड भी किया है । बहुत से कालेज उच्च शिक्षा के लिये खोले गये हें लेकिन बच्चों की बुनियादी शिक्षा की तरफ सरकार को खास ध्यान देना चाहिये ताकि वे बड़े होकर नौकरी की न सोच कर कोई न कोई अपना काम धन्धा –आरम्भ कर सकें । मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि लार्ड मैकाले की शिक्षा यहां पर नहीं देनी चाहिये जिससे कि बच्चे अपने जीवन का स्तर ऊपर न उठा सकें । लार्ड मैकाले की नीति थी कि भारत में इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिये जिससे अंग्रेजी राज में सस्ते क्लर्क मिलते रहे । हिसार में कृषि कालेज से बहूत से छात्र शिक्षा प्राप्त करके निकलते हैं लेकिन उन में बहुत कम ऐसे होंगे जिन्होंने अपना कोई धन्धा किया हो । इसी तरह इंजीनियर्ज भी जो पढ़कर निकलते हैं वे भी नौकरियां की तलाश में भागते हैं । इसका कारण यह है कि उन लोगों की वित्तीय स्थिति बड़ी नाजुक होती है जिससे वे अपना कोई काम धन्धा नही कर पाते । इसलिये मेरी सरकार से रिकवैस्ट है कि बच्चों को कोई न कोई इस प्रकार की टैक्निकल शिक्षा दी जानी चाहिये जिससे कि वे पढ्ने के बाद अपना कोई काम धन्धा आरम्भ कर सकें और इस के लिये सरकार को ऐसे बच्चों को वित्तीय सहायता भी देरी चाहिये । अगर

सरकार को ओर से बच्चों को इस तरह का प्रोत्साहन होगा तो इसमें प्रान्त की भलाई है और इंडस्ट्रीज को भी बढ़ावा मिलेगा । आशा है कि सरकार मेरे इस सुझाव पर अवश्य छगन देगी । शिक्षा के साथ–साथ हमारी सरकार सौंदर्यकरण की तरफ! सड़कों की तरफ और भवन निर्माण की तरफ भी बहुत ध्यान दे रही है, यह बहुत अच्छी बात है । इसके साथ–साथ मानव के चरित्र निर्माण की तरफ भी बहुत छगन देने की जरूरत है । स्कूलों में शिक्षा, शिक्षार्थी और शिक्षक, तीनों का संबंध है । हम स्कूलों में ऐसा आचरण पैदा करें ऐसा वातावरण बनाएं ताकि सही रूप में वहां से एक अच्छा मानव बनकर निकल सके । आप सब जानते हैं कि देश को अच्छा इंजीनियर चाहिए, अच्छा नेता चाहिए, अच्छा मास्टर चाहिए, अच्छा डाक्टर चाहिए, अच्छा गुरु चाहिए और अच्छा शासक चाहिए । तो यह कहां से मिलेंगे । ये कोई बाजार से नहीं खरीदे जा सकते और न ही वृक्षों से तोड़े जा सकते हैं । ये खानों से भी नहीं निकलते । इनको तो स्कूलों और कालजों ने तैयार करना है । इसलिये हमें चरित्र निर्माण की तरफ भी ध्यान देना चाहिए । चिकित्सा के बारे में वैसे तो कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया । परमात्मा ने मनुष्य को इतनी बुद्धि दी है कि वह अपने स्वास्थ्य के बारे में बड़ा सजग है लेकिन फिर भी दुर्घटनाग्रस्त होने से या कोई और बात से मनुष्य रोगी हो जाता है । उसके लिए. सरकार ने उपचार का प्रवन्ध किया है । जगह जगह हस्पताल और डिस्पैसरीज खोली जा रही हैं लेकिन गरीब लोगों को मुक्त दवाई देने का खास प्रबन्ध नहीं है । अगर इस

बजट में इस बात का भी प्रबन्ध हो तो इससे गरीबों की बहुत मदद होगी । रोहतक में मैडिकल कालेज को पी ० जी ० आई० के समान बनाया जा रहा है इससे भी लोगों को बहुत राहत मिलेगी और यह हरियाणा के लिये बड़ी शान की बात है । हमारे यहां समाज कल्याण का काम भी बहुत अच्छा चल रहा है । यह अच्छी बात है कि इसके जरिए गरीब लोगों की सेवा हो रही है । मैं चाहूगी कि समाज कल्याण विभाग की तरफ से गरीब और हरिजन लोगों की अलग से बस्तियां न बनाई जाएं बल्कि शहरों में सभी लोग मिल कर रहें । इससे जात पात की समस्या समाप्त होगी । इसके अलावा जो हरिजन चौपाल बनाने की स्कीम है यह भी बहुत अच्छी है । (घंटी ) इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करती हू और आपका भी धन्यवाद करती हू ।

**चौधरी धर्मवीर गाबा (गुड़गांव ) :** स्पीकर साहब, 2 मार्च 1987 को फाइनैस मिनिस्टर साहब ने जो बजट पेश किया, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । इस बजट में सब से अच्छी बात यह है कि यह एक बैलैन्सड बजट है । इसमें सैल्फ रिलायंस और प्रोडक्शन की परमोशन की भी बात आई है । इसके अलावा. प्लान की डिसैटरलाइजेशन की भी– बोत आई है जोकि बहूत अच्छी बात है । ऐसा करने से आज हमें जिला हैडकवार्टर पर बेसिक नीडज का पता चलेगा और जो प्लानिंग यहां से बनेगी उसको आगे अमली जामा पहनाया जाएगा । इसके अलावा अच्छे बजट का सबूत इस बात से भी मिलता है कि हमारी पर– कैपिटा

इंकम 96 प्रतिशत? बढ़ी है । हो सकता है कि इस. बजट से अगले साल यह इंकम और भी बढ़ जाए । स्पीकर साहब, सब से पहले हं ऐजुकेशन के बारे में कहना चाहता हूं । यह बात ठीक है कि स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए पैसा रखा गया है । इसमें कहा गया है कि 100 प्राइमरी स्कूलों –को मिडल तक अपग्रेड किया जाएगा, 50 मिडल स्कूलों को हाई स्कूल तक अपग्रेड किया जाएगा और 25 हाई स्कूलों को सीनियर माध्यमिक विद्यालय बना दिया जाएगा । मैं किस्त मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐजुकेशन को इतनी प्रायरिटी देने के बावजूद भी इतनी कम रकम इसके लिये क्यों रखी गई है । 94 स्कूलों की बिल्डिग और 18 रिहायशी मकान बनाने के लिए केवल 180 लाख रुपए रखे गए हैं । क्या यह सोचा जा सकता है कि 1 लाख 80 हजार रुपए में एक स्कूल की बिल्डिंग बन जाएगी? मेरी गुड़गांव कास्टिचुऐंसी में एक स्कूल भीम गढ़ी है उसके लिए कुछ पैसा मंजूर हुआ था लेकिन वह पैसा किसी और स्कूल को ट्रांसफर कर दिया गया है । मैं चाहता हूं कि ऐजुकेशन के साथ ऐसा मजाक न किया जाए । इस स्पीच में यह भी लिखा है कि द्रोणाचार्य गवर्नमैंट कालेज गुडगांव को मौडल कालेज के रूप में 'निएपा' द्वारा एडाप्ट किया गया है और इसे एक औटोनौमम कालेज के रूप में डिवैल्प किंवा जाएगा । मैं समझता हूं कि जिन साहेबान ने यह पालिसी बनाई है वे इसके पौस एंड कौन्ज भी जरूर देखेंगे क्योंकि 'निएपा' के अन्डर आने से यह कालेज एक औटोनौमस बौडी हो जाएगी । इस कालेज से जो डिग्री मिलेगी क्या उसको दूसरी स्टेटस

रिकोगनाइज करेंगी । कहीं ऐसा न हो कि बच्चे वहां से ग्रेजुएशन करके भटकते फिरें । औटोनौमस बौड़ी होने से न तो वहां से कोई टीचर ट्रांसफर हो सकेगा और न ही उस कालेज में गवर्नमैंट की कोई 'से' होगी और न ही किसी यूनिवर्सिटी के साथ इसकी एफीलिएशन होगी। तो आप ही अन्दाजा लगाएं कि इसका क्या हश्र होगा । मैं आशा करता हूं कि इस स्कीम को लागू करने से पहले इसके प्रौस एंड कौन्ज जरूर देख लें । कही ऐसा न हो कि गुड़गांव के बच्चे बेरोजगार हो जाएं । इसके साथ साथ उर्द लैगवेज के लिए 10 लाख रुपए रखे गए हैं । उर्दू एक बेहतरीन जबान है, इसकी परमोशन जरूर होनी चाहिए । मैं यह जानना चाहता हूं कि इतनी कम रकम से आप उर्दू की लाइब्रेरी खोलेंगे या स्फूत खोलेंगे । इतनी कम रकम में आप कहां कहां पर स्कूल खोलेंगे । मैं समझता हूं कि हरियाणा के अन्दर हर लैंगवेज को वढ़ने का हक हए, इसलिये यह रकम बहुत थोड़ी है । ऐजुकेशन के तहत टैक्निकल ऐजुकेशन भी डराती है । यह ठीक है कि आपने सिरसा में वीमैन पोलेटैक्निक खोल दी है और एक इंस्टीव्चूट आफ हौस्पिटल इंजीनियरिंग रोहतक में खोल दिया है । मैं चाहता हू कि आप ऐसा प्रावधान कर दें जिससे कि साउथ हरियाणा में भी टैक्निलक ऐजुकेशन दी जा सके । आज हमारी हालत यह है कि आई ० टी ० आईज ० के अन्दर जितनी सीटें बहुत पहले हुआ करती थीं, आज भी उतनी ही हैं । आपको पता है कि कितनी पापुलेशन बढ़ चुकी है और उसके हिसाब से कितने और बच्चे इनमें पढ़ना चाहते हैं लेकिन इनकी सीटें नही बढ़ी हैं ।

मैं प्रार्थना करूंगा कि इन आई ० टी ० आईज ० के अन्दर सीटें और बढ़ा दी जाएं ताकि इनमें और बच्चे दाखिल हो सकें । इसी तरह से मैं हैल्थ ऐजुकेशन के बारे में भी रिकवैस्ट करूंगा । मैडिकल कालेज रोहतक को जरूर अपग्रेड किया जाए लेकिन आज हमें जो डिफीकल्टी नजर आती है वह नर्सिज को क्लासिज की है । इसके लिए क्या प्रोवीजन किया गया है मैं समझता हू कि वित्त मन्डी जी इस बारे में जरूर ध्यान देंगे ।

स्पीकर साहब, अब मैं हैल्थ की बात कहना चाहूंगा । मेरी कांस्टिचुऐंसी में आज तक एक भी प्राईमरी हैल्थ सैन्टर नहीं खुल सका है । इसके लिये कौन जिम्मेदार है? हमने वहां पर हैल्थ सैन्टर खुलवाने के लिए पंचायत की तरफ से जमीन भी दी हुई है लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर यह सैन्टर नही खुल पाया है । गढ़ी हरस्वरूप और वजीराबाद में लोगों ने प्राइमरी हैल्थ सैन्टर खोलने के लिए पंचायत की तरफ से जमीन हैल्थ विभाग को दी हुई है लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर आज तक प्राइमरी हैल्थ सैन्टर नहीं खोला जा सका । यदि वहां पर यह सैन्टर खोल दिया जाए तो सरकार की बड़ी मेहरबानी होगी । मैं चाहता हूं कि जिस हिसाव से डिवैल्पमैंट के काम हो रहे हैं उसका कुछ हिस्सा मेरी कांस्टिचुऐंसी में रहने वाले लोगों को भी मिलना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय अब मैं पावर के बारे में जिक्र करना चाहूंगा । सरकार ने इस योजना के लिए वार्षिक योजना का 34

प्रतिशत भाग रखा है । बिजली और सिंचाई का आपस में चोली–दामन का सम्बन्ध है! इस समय प्रदेश में 4 लाख के करीब ट्यूबवैल्ज हैं । आज हरियाणा में 80–81 प्रतिशत एरिया के अन्दर सिंचाई हो रही है । हरियाणा सारे हिन्दुस्तान की जमीन के एक परसैन्ट हिस्से में बसा हुआ है । इसके विपरीत पैदावार के लिहाज से हम सबसे ज्यादा फख्र कर सकते हैं । यहां का किसान बहुत मेहनती है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता । सरकार की अच्छी नीतियां और अच्छे प्रोग्राम भी सहायक रहे हैं । पहले हरियाणा में 29–30 लाख टन के आसपास पैदावार होती थी लेकिन आज 80 लाख टन हो गई हए । यह सब सरकार की अच्छी पालि– लियो के कारण ही संभव हो सका है । बजट में दर्शाया गया है कि यमुनानगर पन बिजली परियोजना के 8 मैगावाट वाले 2 यूनिट चालू किए गए हैं और दो यूनिट निकट भविष्य में चालू किए जाने हैं । सुरजेवाला साहब मरने या न मानें लेकिन यह असलियत है कि हरियाणा में जहां जहां पर इंडस्ट्रिालाइजेशन हुई थी, वहां से आग्न इण्डस्ट्रीज शिफ्ट होनी शुरू हो चुकी हैं । यह सब पावर शार्टेज की वजह से ही हो रहा है । जो लगातार चलने वाली इण्डस्ट्रीज हैं उनको दिन में 8 घंटे बिजली की सप्लाई होती है और जो दूसरे यूनिट हैं उनको 4 से 6 घंटे ही बिजली सप्लाई होती हए । हमारे साथ लगते एरिया दिल्ली में इण्डस्ट्री को 24 घंटे बिजली मिल रही है । अगर इण्डस्ट्रीज यहां से चली गई तो हम हर लिहाज से पिछड़ जायेगे । जब इण्डस्ट्रीज होंगी तभी तो हम कुछ सेल कर पायेंगे, तभी

हमें कुछ रैवेन्यू प्राप्त होगा । जब यहां पर मैनुफैर्क्चारंग ही नहीं होगी तो फिर सेल कहां से होगी और सरक र को राजस्व कहा से प्राप्त होगा । सरकार की यह पालिसी तो ठीक है कि वार्षिक योजना का 34 प्रतिशत हिस्सा बिजली की जनरेशन के लिए खर्च किया जायेगा ताकि हम यहां इण्डस्ट्रीज और सिंचाई के लिए बिजली दे सकें । अध्यक्ष महोदय, आपको भी पता है कि हमारे यहां सिंचाई के लिए भी बिजली नहीं है । महेन्द्रगढ़ और गुड़गांव जिले में सारी सिंचाई ट्यूबवैल्ज के जरिए ही संभव है क्योंकि वहां पर नहर नहीं है । अगर बिजली नहीं मिलेगी तो फिर वहां के लोगों का जो हश्र होगा वह सब को पता ही हए । कुदरती मार को तो किसान सहन कर लेता हए । वह भी इसलिए कि उसके आगे कुछ कर पाने में असमर्थ है । हमारी तरफ का एरिया ऐसा एरिया तो हए नहीं कि एक साल में तीन तीन फसलें किसान ले सके । वहां तो जो कुछ भी किसान को मिल सकेगा वह बिजली की सुविधा से ही मिल सकेगा । इसलिए मैं चाहूंगा कि वहां कर इस ओर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि वहां अपना गुजारा चला सके ।.

अध्यक्ष महोदय, सरकार ने बजट के अन्दर खेलों के लिए जो 142 लाख रुपये रखे हैं, मैं समझता हूं कि ये बहुत कम है । बजट में कहा गया है कि फरीदाबाद में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट का मैदान तैयार किया गया है । क्या इस मैदान से हमारी खेलों की सभी जरूरियात पूरी हो जाएंगी? इस बारे में मैं प्रार्थना

करूंगा कि जिन जिन स्कूलों में स्पोर्टस के ग्राउन्ड बन सकते हैं वहां पर भी ग्राउंड बनाने. के लिए कुछ रकम बजट में रख ली' जाये ताकि सभी बच्चों को स्पोर्टस की प्रमोशन मिल सके और वे उसका फायदा उठा सकें ।

अध्यक्ष महोदय, जब से चौधरी बंसी लाल जी मुख्यमंत्री बने हैं तब से एक आत्म विश्वास की भावना पैदा हुई है । लेकिन इस आत्म विश्वास का कुछ लोग नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं । इस बारे में भले राम जी ने और दूसरे साथियों ने भी जिक्र किया है । यहां के कर्मचारियों को हमारी सरकार दूसरी सरकारों के मुकाबले 10 करोड़ रुपया अधिक दे रही है । हमारे मुख्यमंत्री जी ने फोर्थ पे कमीशन की रिपोर्ट दूसरे सूबों से पहले यहां पर लागू की है । सरकारी कर्मचारी सरकार के तमाम कामों में बराबर के हकदार हैं । इसलिए उनका यह हक बनता है । लेकिन कुछ लोग इसका नाजायज फायदा उठाने पर तुले हुए हैं । जब मुख्य मती जी 113 करोड़ रुपया माफ कर सकते हैं और रैवेन्यू माफ कर सकते हैं तो कर्मचारियों को सुविधा देने में वे पीछे क्यों रहे? कुछ लोग कर्मचारियों को धड़का रहे हैं । दूसरी स्टेटस 1–4–87 से फोर्थ पे कमीशन की रिपोर्ट को लागू करेंगी जबकि हमारे मुख्यमंत्री जी ने फोर्थ पे कमीशन की रिपोर्ट को 1–1–86 से लागू करने की घोषणा की है । मैं समझता हू कि इसके बावजूद भी यदि कर्मचारी आन्दोलन करते हैं तो यह सही नही है । इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं ।

**सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला ) :** स्पीकर साहब, बजट पर बहस चल रही है और आज बहस का अन्तिम दिन है । सरकार की प्राथमिकता इस बात से परखी जाती है कि उसने लोगों की सुविधा के लिए बजट में क्या क्या रखा है? इस साल की प्लान 585 करोड़ रुपये की होगी । इसमें से 166. 69 करोड रुपये पावर जनरेशन पर खर्च होंगे और 182.47 करोड़ रुपये इरीगेशन पर खर्च होंगे । चौधरी बंसी लाल जी की सरकार प्रान्त के किसानों की खेती के लिए, पीने के पानी के लिए प्रायरिटी बेसिज पर काम कर रही है । अध्यक्ष महोदय, मुख्य गैती महोदय ने आज से लगभग 6 महीने पहले कार्यभार संभाला था । जिन नीतियों की घोषणा उन्होंने की थी उनमें से एक यह थी कि किसान के खेत के अन्तिम छोर तक पानी जायेगा, उसके लिए व्यापक प्रबंध किया जायेगा और इस काम के लिए नहरों में सुधार भी किया जायेगा । इसी प्रकार से इन्होंने इस बात की भी घोषणा की थी कि बिजली की उत्पादकता आने वाले समय में बढ़ सकेगी और इसके साथ साथ ट्रांसमीशन की तरफ भी सरकार व्यापक तौर पर ध्यान देगी । इस अर्से मैं जो कार्य हुए हैं उनका संक्षेप में ब्योरा आपके जरिए हाउस को देना चाहूंगा । अध्यक्ष महोदय, जो नई स्कीमें शुरू की गई हैं उनमें नहर विभाग के नए रजबाहे बनाने और पुराने रजवाहों को आगे बढ़ाना डेए । वे 217 हैं । इनमें से यमुनानगर सिस्टम, गुड़गांव कैनाल, लिफ्ट इरीगेशन स्कीम और जे ० एल० एन० कैनाल में 163 स्कीमें हैं और भाखडा एरिया में 54 है । इसके अलावा नहरों

के सुधार के लिए भी काम किया जायेगा । जिन नहरों की पटरियां टूट गई थी या टूटी हुई हैं और जिन नहरों की रिपेयर और मेन्टिनैस व लाईनिग आदि होनी हैं वे 562 हैं । इनमें से 388 स्कीमें तो यमुनानगर सिस्टम, गुड़गांव कैनाल, लिफ्ट इरीगेशन स्कीम और जे ० एल० एन० कैनाल की है और बाकी भाखडा एरिया की स्कीमें हैं । इन 562 स्कीमों में से 240 स्कीमों पर काम चल रहा है । इन 240 स्कीमों में से भाखडा एरिया में 69 स्कीमों पर काम चल रहा है और 171 स्कीमों पर गुड़गांव कैनाल यानी यमुना सिस्टम की तरफ काम पत्र रहा है । इसके अतिरिक्त 14 करोड़ रुपये और सिंचाई के लिए खर्च किए गए हैं । यह अपने आप में एक कीर्तिमान है । जब से यह प्रान्त बना है तब से आज तक इस प्रान्त ने बहुत तरक्की की है । जितने कम समय में इस प्रान्त ने तरक्की की है उतनी तरक्की आज तक किसी भी प्रान्त ने नही की है । सरकार किसानों को उनके खेतों तक अधिक से अधिक पानी पहुंचाने का प्रयत्न कर रही है । सरकार जिस तरह से किसानों को पानी दे रही है उसका दूसरा कोई उदाहरण आपको कहीं भी नही मिलेगा । मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए बताना चाहूगा कि इस कार्य के मुकाबले 1977 में कुत 6 स्कीमें मंजूर की गई । 1978 में कोई स्कीम मंजूर नही हुई और 1979 में केवल 9 स्कीमे मंजूर हुई । इस तरह से अध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी सरकार के पूरे कार्यकाल मे कुल 15 स्कीमे मंजूर हुई जिन पर टोटल 40 लाख रुपया व्यय हुआ था । लेकिन अब इस थोड़े से अर्से में हमारा इतना कार्य करने का

प्रोग्राम है और इस मरकार ने काफी काम किया भी है । अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं यह भी बताना चाहूगा कि यहां पर सिंचाई की किस प्रकार से बढ़ौतरी हुई है । 196 छह 7 में भाखडा सिस्टम से 7, 91, 484 हैक्टेयर एरिया इरीगेट होता था और डब्ल्यू ० जे ० सी० सिस्टम से 5, 01, 659 हैक्टेयर एरिया इरीगेट होता था । दोनों सिस्टम्ज से इरीगेट होने वाला एरिया 1 2, 93, 143 हैक्टेयर था । 197 5–76 में जब कांग्रेस सरकार ने कार्यभार छोड़ा तो उस वक्त हरियाणा में भाखडा सिस्टम से 9, 18,444 हैक्टेयर, डब्ल्यू० जे ० सी० सिस्टम से 7, 32, 943 हैक्टेयर और लिफ्ट कैनाल जो बनाई गई थी उससे 28, 260 हैक्टेयर एरिया इरीगेट होता था । टोटल एरिया जो इरीगेट होता था वह 16,77, 647 हैक्टेयर था । अध्यक्ष महोदय, 1977–78 में जनता पार्टी की सरकार आने के बाद यह एरिया भाखडा सिस्टम के 9, 16,444 हेक्टेयर से घट कर 8, 63, 901 हैक्टेयर रह गया, डब्ल्यू० जे ० सी० सिस्टम के 7,32, 943 हैक्टेयेर से घट कर 6, 36,033 हैक्टेयर रह गया, लिफ्ट कैनाल के 28, 260 हैक्टेयर से घट कर 26, 949 हैक्टेयर रह गया और टोटल इरीगेटिड एरिया 16,77,6 47 हैक्टेयर से घट कर 15,26,883 हैक्टेयर रह गया जबकि वर्ष 1985–86 के अन्त में हरियाणा में टोटल इरीगेटिड एरिया 19,45, 421 हैक्टेयर, लिफ्ट कैनाल से इरीगेटिड एरिया 54,790 हैक्टेयर, डब्ल्यू० जे ० सी ० सिस्टम से इरीगेटिड एरिया 7,83,240 हैक्टेयर और भाखडा सिस्टम हैं इरीगेटिड एरिया 11,07, 391 हैक्टेयर है । इस प्रकार से आप देखेंगे कि कौन से समय में

कौन सी सरकार के वक्त में सिंचाई की कितनी सुविधा बढी है । इसी तरह से, अध्यक्ष महोदय, मैं संक्षेप में जो नहरों को बनाने का काम हुआ हए उसके बारे में हाउस को बताना चाहता हूं । फर्स्ट फेज में, जो 16–8–78 से आरम्भ होकर 28–2–83 को खत्म हुई, 159 कैनाल्ज पक्की की गई जिनकी टोटल लैग्थ 2, 913 किलोमीटर थी और इन पर 94. 30 करोड़ रुपया खर्च किया गया । दूसरो फेज में, जो 1–3–83 से शुरू हुई 148 नहरें पक्की करनी हैं, जिनकी लम्बाई लगभग 1986.77 किलोमीटर होगी और खर्चा 78.18 करोड़ रुपये होगा ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से यह भी बताना चाहूंगा कि विजली के कनैक्शन्ज की इस दौरान में क्या पोजिशन रही है । सन् 1967 में जनरल कनैक्शन्ज 2,81,778 थे जबकि 31 मार्च, 1986 को इनकी संख्या 13,89,282 थी जो अब 15 लाख के करीब है । इस साल का टारगैट 60,000 कनैक्शन्ज का था जो चौधरी बंसी लाल जी के मुख्य मती बनने के बाद रिवाइज होकर 1,50,000 का हो गया है । इसी प्रकार से ट्यूबवैल्ज के कनैक्शन्ज की बात है । चौधरी देवी लाल जी के राज में वर्ष 1977–78 और 1978– 79 में 10 और 12 हजार से ज्यादा कनैक्शन्ज– रिलीज नहीं हुए जबकि इस वर्ष हमने 25,000 कनैक्शन्ज देने का लक्ष्य बनाया है । इसी प्रकार से माननीय सदस्यों कीं जानकारी के लिए मैं बिजली की डिस्ट्रिब्यूशन के बारे में भी कुछ जानकारी देना चाहूंगा । इस काम के लिए हमने इस साल 25 करोड़ रुपया खर्च

करने का प्रावधान किया है जबकि पिछले साल केवल 18 करोड़ रुपये का प्रावधान था । बहुत से नए बिजली घर बनाए गए हैं और नई लाईनें बना करके सिस्टम को सुदृढ़ किया जा रहा है ।

स्पीकर साहब, मैं थर्मल प्लान्टस की भी थोड़ी सी चर्चा यहां करना चाहूंगा क्योंकिं उनके बारे में काफी लोगों को गलतफहमी भी है और यह भी ठीक है कि बहुत अच्छी स्थिति हर समय उनकी नहीं रहती । लेकिन फिर भी जो अच्छा काम है उसकी जानकारी न तो माननीय सदस्यों को है और न ही लोगों को है । सबसे पहले मैं फरीदाबाद थर्मल प्लान्ट के बारे में बताना चाहूंगा । 1986 में फरीदाबाद का पूरे सारन का प्लान्ट लोड फैक्टर 441 था जिसके लिए उसे भारत सरकार से 2 लाख रुपये का ईनाम मिला है । पानीपत में कई तरह की समस्यायें रही हैं । एक तो नए युनिटस होने की वजह से टाथिंग प्रौबनम थी दूसरे उनके वाईटल पार्टस खराब होने से कुछ सैट–बैक रहा लेकिन मैं हाउस को बताना चाहूंगा कि इस वक्त फरीदाबाद का युनिट भी और पानीपत के युनिटस भी काफी जैनरेशन कर रहे हैं । इसके अलावा । प्रधान मैली जी की कृपा से हमको सैन्ट्रल प्रोजैक्टस से पूरा हिस्सा मिल रहा है । पिछले लगभग दो महीने से तकरीबन 6– 7 लाख युनिटस ऐक्सट्रा बिजली हमें सैन्ट्रल पूल बे मिल रही है जिसकी वजह से बिजली की उपलब्धि में काफी सुधार हुआ है । इस बात का जिक्र माननीय सदस्यों ने भी गवर्नर ऐड्रैस पर बोलते हुए और बजट पर बोलते हुए किया है कि बिजली की

उपलब्धि पिछले कुछ दिनों से अच्छी है । फिर भी मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन दिलाना चाहूंगा कि इस वक्त जो युनिटस काम कर रहे हैं और बिजली का जो शेयर हमें मिल रहा है उसमें आने वाले समय में और ज्यादा सुधार करने की हम उम्मीद रखते है । म्उझे यह भी उम्मीद है कि डोमैस्टिक यूज के लिए जो आज कल लोगों को बिजली नहीं मिल रही है उसे भी निकट भविष्य में बिजली' बोर्ड देगा ।

स्पीकर साहब, गाबा साहब ने महेन्द्रगढ़ और गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट को कम बिजली देने के बारे में जो बात कही वह ठीक नही है । इस बारे में मैं हाउस को यह बत चाहूंगा कि लगभग तीन चार महीने पहले जब नारनौल का 220 के ० वी ० सब स्टेशन चालू नहीं हुआ था, बिजली की कंजम्पशन के लिए कुरुक्षेत्र जिला और करनाल जिला ऐग्रीकल्चरल सैक्टर में सबसे पहले नम्बर पर था लेकिन अब महेन्द्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट नम्बर एक पर है और करनाल तथा कुरुक्षेत्र उससे पीछे हैं । सबसे ज्यादा बिजली की उपलब्धि महेन्द्रगढ जिले में है क्योंकि सरकार की नीति है कि जहां नहरों का पानी नहीं पहुंचा है, सूखा इलाका है! जमीन रेतीली हैं वहां बिजली देने में प्रार्थीमकता दी जाए । नहर का पानी भी सब जगह पहुंचे, इसके लए भी सरकार वचनबद्ध है । मुझे इस बात की खुशी है कि सिंचाई विभाग के सारे अधिकारी एवं कर्मचारी, हैडक्वार्टर के भी और फील्ड के भी । इस काम में जुटे हुए हैं । नहरों की डी–सिल्टिंग का काम लगभग खत्म कर

दिया गया है और दूसरे सुधार के काम तेजी से चालू हैं । मुझे उम्मीद है कि मुख्य मैली जी का आश्वासन कि हर नहर की टेल तक पानी पहुंचे, बहुत जल्दी पूरा होगा । अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं ।

**13.00 बजे**

**समाज कल्याण राज्य मन्त्री ( श्रीमती करतार देवी ) :** अध्यक्ष महोदय, सदन में दो दिन से बजट पर चर्चा चल रही है । माननीय सदस्यों ने बार बार बजट की प्रशंसा करते हुए यह रिपीट किया है कि हरियाणा सरकार ने हरियाणा के चहुमुखी विकास को ध्यान में रखते हुए कृषि! बिजली, सिंचाई और अन्य सभी योजनाओ के लिए यथोचित पैसा दिया है । स्पीकर साहब । मैं समय का ख्याल रखते हुए केवल सोशल वैल्फेयर विभाग के बारे में अर्ज करना चाहती हूं क्योंकि कई माननीय सदस्यों ने कई मदों के बारे में जिक्र किया है । स्पीकर साहब, मेरा ख्याल है कि यह पहला अवसर है जब हयूमैन रिसोर्सिज को टौप प्रायरिटी देते हुए स्टेट के कमजोर अंगों के लिए पैन्शन, प्लाटस, मकान और चौपालों के लिए पैसा दिया है । सोशल वैल्फेयर विभाग अलग अलग दो विंगों में काम करता है । जहां तक समाज कल्याण विभाग का सम्बन्ध है उसके बारे में कांग्रेस सरकार ने बार बार इस बात को ध्यान में रखते हुए कार्य किया है । हमारे महान नेताओं ने आजादी से पहले और संविधान सभा के सैशन में कहा

था कि यह संघर्ष निरन्तर उस समय तक जारी रहे गा जब तक कि हर आदमी की आंख के आंसू नहीं पोंछ देंगे । इसीलिए हमारी सरकार उन कमजोर और असहाय लोगों के लिए विभिन्न योजनाओं को चला रही है जिसमें वृद्धो । विधवाओं! अपंगों को पैन्शन दी जा रही है! अगर अपंग पढ़ते हैं तो उन्हें वजीफा भै। दिया जाता है । अगर उसकी आयु 21 साल से ज्यादा है तो उसे पेन्शन दी जाती है । इन सभी उपलब्धियों के लिए मुख्यमंत्री जी ने काफी पैसा दिया है क्योंकि निसहाय लोगों ने दो दो साल से फार्म भरे हुए थे लेकिन उन्है पैन्शन नहीं मिली थी लेकिन अब इतना पैसा मिल गया है कि उन्हें पैन्शन मिल जायेगी । स्पीकर साहब, कुछ लोग ऐसे होते है जो दुखिया को और ज्यादा दुखी करते है । उनके दुख का राजनैतिक तौर पर फायदा उठाना चाहते हैं । हमारे प्रदेश में एक विरोधी दल के ऐसे नेता है जो इस बात को नहीं जानते है कि हमने सं 3 हजार लोगों को, अलग अलग कैटेगरी के लोगों को 80 और पचास रुपये के हिसाब से पैन्शन मासिक दर से दी हु ई है । ये विरोधी दल के भाई पब्लिक जलसों में जा कर कहते हैं कि अगर आप मेरा समर्थ न करोगे तो आप लोगों की पैन्शन कर दूंगा । स्पीकर साहब, इस पैन्शन का भी अपना इतिहास है । जब श्रीमती इन्दिरा गान्धी जी ने राजे महाराजाओं के प्रिवी पर्सिज बन्द कर दिये तो उनका ध्यान उन लोगों की तरफ गया जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी की थी । उन्होंने कहा कि' जब देश आजाद है, डैमोक्रेसी है, सभी एक ही देश के नागरिक हैं, यहां कोई विदेशी सरकार नहीं है तो इन

स्वतंत्रता सैनानियों को भी पैन्शन देनी चाहिए जिन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी. है । स्पीकर साहब, आपको पता ही है कि आज उन कुर्बानियों के बलबूते पर हम इन ट्रैजरी बैन्चों पर बैठे हुए हैं और आजादी का सुख भोग रहे हैं । इस बात को ध्यान में रख कर उन्होंने यह पैन्शन का प्रावधान किया । सन् 1969 में जब चौधरी बन्सी लाल जी मुख्य मंत्री थे उस समय से असहाय और स्वतंतता सेनानियों को पेन्शन मिल रही है । सन् 1984 में चौधरी भजन लाल मुख्य मंत्री, ने विधवाओं, अपंगों की पैन्शन चालू की थी और अगले साल शायद 49 हजार लोगों को पैन्शन देने का प्रावधान किया गया है ।

स्पीकर साहब, आप जानते हैं कि महिलायें इस समाज का ऐसा कमजोर अंग हैं जिनके बारे में कुछ ध्यान नहीं किया जा सकता । उन बेचारियों के पैदा होते ही घर वालों के मन में परेशानी पैदा हो जाती है । प्रगतिशील से प्रगतिशील परिवार भी यह कहने लगता है कि लड़की हो गई है । पता नहीं लड़की होने के बाद उन पर क्या आफत आ जाती है । वे बेचारिया तरह तरह के—' अत्याचारों और आपत्तियों की शिकार होती हैं । कितनी ही बेचारियां दहेज प्रथा की भी शिकार होती हैं । स्पीकर साहब, जहां हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में विशेष प्रावधान किया वहां मुसीबतजदा बहिनों के लिए सोशल वैल्फेयर विभाग थे सोशल वैल्फेयर ऐडवाइजरी बोर्ड की भी स्थापना की है ताकि उन औरतों को काम दे सकें और वे कोई ट्रेनिंग लेकर इस

आफत के समय में अपने पैरों पर खड़ी हो कर अपने परिवार की आमदनी को सप्लीमैंट कर सकें । हमारे यहां करनाल, रोहतक और फरीदाबाद में महिला आश्रम हैं जहां पर विधवा' बहिनों को विपत्ति काल में टेरनिंग दे कर अपने पैरों पर खड़ा किया जाता है । दूसरी जो वौलन्टरी एजैन्सी है, उन्हें भी जनरल ग्रान्टस–इन–एड से पैसा देते हैं । इसी प्रकार से हमारी सरकार ने बच्चों के ऊपर भी पूरा ध्यान दिया है क्योंकि समाज का भविष्य बच्चों पर निर्भर करता है । इसलिए ही सरकार ने कई महत्वपूर्का फैसले लिए हैं । हरियाणा सरकार भारत की पहली सरकार होगी जहां हर गांव में आई० सी ० डी ० एस० का प्रोग्राम चलायेंगे । आई० सी ० डी ० एस० के मायने ये नहीं हैं कि एक आंगनवाड़ी में एक ही बहिन को काम मिल जायेगा बल्कि उस आंगनवाड़ी में उन देहात के बच्चों को पौष्टिक आहार दिया जायेगा जिन्हें पौष्टिक आहार की आवश्यकता है ताकि आगे आने वाले समय स्वस्थ नागरिक बन सकें । यह बात इसलिए की जा रही है ताकि उनकी बुनियाद ही ठीक हो जाये और भविष्य में वे अच्छी उन्नति कर सकें । अगर हम बच्चों का ध्यान रखेंगे तो हमारा राष्ट्र बनेगा । आई० सी ० डी० एस० स्कीम में अनुपूरक पोषण, प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जांच आदि का भी प्रबन्ध किया गया है ताकि कोई जान लेवा बीमारी उनको न लग सके । जो बहिने वहां पर काम करती हैं उनके साथ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी काम करना चाहिए । उन्हें चाहिए कि वे गर्भवती महिलाओं को घर पर जा कर चौक करें । यह हरियाणा सरकार की बहुत बड़ी

उपलब्धि है कि गर्भ से लेकर बड़ा होने तक पौष्टिक आहार का प्रबन्ध किया जा रहा है । इसी प्रकार से बड़े बड़े शहरों में बाल अपराधियों के लिए अलग से रहने का प्रबन्ध किया है क्योंकि उन्हें आम कैदियों के साथ नहीं रखा जाना चाहिए । छोटे बच्चे चाहे किसी के बहकावे में आ कर अपराध करते हैं या गलती से करते हैं उन्हें आम कैदियों से अलग रखा जाना चाहिए ताकि वे उनसे और अपराध न सीख सकें । स्पीकर साहब, हरियाणा में तो यह बाल अपराध प्रवृत्ति अभी कम है लेकिन समस्या की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए हम उनका अलग से प्रबन्ध करने जा रहे हैं । कुछ लोग अन्दरूनी तौर पर समाज. को खोखला करने की साजिश कर रहे हैं । वे छोटे बच्चों को बहका कर गलत काम करवाते हैं । जे। लोग शराब पीते हैं, वे शराब का व्यापार भी करते हें । वे यह नाजायज धन्धा उन छोटे बच्चों से करवाते हैं । जो लोग अफीम खाते हैं, वही लोग बच्चों से अफीम भी बिकवाते हैं । समैक की छोटे बच्चों को भी आदत कई बार पड जाती है । जब समैक नहीं मिलती है तो उन्हें चोरी जैसे अपराध की आदत पड़ जाती है । इसलिए, अब सरकार की मन्शा है! कि आम कैदियों के साथ उन्हें न रख कर अलग से रखा जाये ताकि उन्हे बहुत सारे और अपराधों की जानकारी न हो जाये । उन बच्चों की मन्शा नहीं होती है कि अपराध जगत में प्रवेश करें । इसलिए हमने स्टेट आफटर केयर होम सोनीपत में बनाया है और इस तरह के और– भी औवजर्वेशन होम बनायेगे। इस मामले में सब से ज्यादा सहयोग स्वैच्छिक संगठन ही दे सकते हैं । हमारी स्टेट मैं

स्वैच्छिक संगठन बहुत कम हैं लेकिन तमिलनाडू और कर्नाटक में काफी है । वहा के लोगों. के मन में एक भावना है कि दूसरे को ऊंचा उठायें । वे लोग अपना एक मिशन बना लेते हैं कि मैंने बच्चों या महिलाओं के फील्ड में काम करना है । स्वैच्छिक संगठन के माध्यम से ये लोग समाज में आगे आते हैं और वे सरकारें भी ऐ से संगठनो को काफी सहायता करती हैं । जनरल ग्रान्टस इन एड देकर प्रोत्साहन दिया जाता एं ताकि वे महिलाओं और बच्चों के वैल्फेयर के लिए काम करें । स्पीकर साहब, वैल्फेयर डिपार्टमैंट का दूसरा काम शड्यूल्ड कास्टस एन्ड बैकवर्ड क्लासिज के लोगों का वैल्फेयुर करने का है । यह भी कांग्रेस पार्टी का पहला लक्ष्य रहा है और महात्मा गान्धी ने अपने 18 रचनात्मक प्रोग्राम में इसे सर्वोच्च प्रायरिटी दीं थी । उन्होंने हरिजनों की सेवा की तरफ ज्यादा ध्यान दिया था । उस समय तो हरिजनों पर बहुत ज्यादा पाबन्दियां थी और इन्सान को इन्सान नहीं समझा जाता था लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तो तभी से इन लोगों को. संरक्षण की गारन्टी दो हुई है । इसीलिए हमारी कांग्रेस सरकार ने इनके लिए समय समय पर अच्छे प्रोग्राम बनाये हैं । जिन हरिजनो के कच्चे मकान हैं, उन्हें ग्रान्ट के रूप में दो दो हजार रुपये की राशि देने का प्रावधान किया है । प्लाट देने का भी प्रावधान किया गया है। विमुक्त और इसरी जाति के लोगों के लिए और भी कई सुविधायें दी हैं । उन लोगों के बच्चों को, जो स्कूल में शुरू में दाखिल होंगे, कापियां और किताबे देने के लिए कुछ राशि रखी है । यह सब से नयी स्कीम है कि हरिजनों के जो बच्चे फर्स्ट डिवीजन में

मैट्रिक पास करेंगे उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए हजार बारह सौ रुपये की राशि दी जायेगी । इसका भी बजट में प्रावधान किया गया है । जिन बच्चों के मां बाप अनपढ़ होते हैं और बच्चे मैट्रिक में पढ़ते हैं उन्हें साइंस, मैथेमैटिक्स और इंगलिश की कोचिग के लिए कुछ राशि का बजट में प्रावधान किया है ताकि उनकी बुनियाद मजबूत बने और कम्पीटीशन के युग में भी आगे आ सकें । इतना ही नही एच० भी ० एस० और आई० ए० एस० की कोचिंग के लिये भी हमने ट्रेनिंग सैटर खोले हुए हैं । उनको न केवल स्कूली शिक्षा और कालेज की शिक्षा के क्षेत्र में वजीफे दिये जाते है बल्कि नौकरियों में भी आरक्षण किया गया हए । पहले से ज्यादा इस बात का ध्यान रखा गया है कि हर डिपार्टमैंट में रिजर्वेशन पूरी की जाये । स्पीकर सर, जब मैं रिजर्वेशन की चची कर रही हूं तो मुझे वह ख्याल भी आता बुश जब काग्रेस पार्टी की सरकार इस देश. में नही रहीं थी । उस समय कुछ लोगों ने सबसे पहला मुद्दा यही उठाया था कि आरक्षण समाप्त किया जाये । आरक्षण विरोधी एक नहर देश में चल पड़ा थी कि यह रिजर्वेशन खत्म होनी चाहिये । खुशी की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के दोबारा शासन में आते ही श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इस रिजर्वेशन को 10 साल के लिये आगे बढ़ाया । फिर भी हमारे बहुत से भाई अपने राजनीतिक स्वार्थों को सीधा करने के लिये, जब विरोधी दलों के मंचों से बोलते हैं तो कहते हैं कि कांग्रेस सरकार के हाथ में हम सुरक्षित नही हैं । उनको समाज से ज्यादा अपने हित प्यारे हो गये हैं । आज तक जितना कुछ भी उनके

लिये किया गया है, वह सारे का सारा कांग्रेस सरकार को क्रैडिट जाता है । जहां तक चौधरी बंसी लाल का. सम्बन्ध है, वे कांग्रेस सरकार की नीतियों पर चलते हैं लेकिन इन्होंने रिजर्वेशन में हमेशा एक नयी एडीशन की है । पहले जब ये यहां पर मुख्य मती थे तब इन्होंने कार्पोरेशन्ज और बोर्डज वगैरा में ही नहीं बल्कि इंजीनियरिंग कांलेजों और मैडिकल कालेजों में भी रिजर्वेशन की थी ताकि ये बच्चे भी सब जगह मान–सम्मान से नौकरी कर सकें और जीवन के हर क्षेत्र में अनुभव प्राप्त कर सकें । अब उन्होंने आते ही सबसे पहले सामूहिक विकास की ओर ध्यान देने के साथ ही विकेन्द्रीयकरण योजना की तरफ ध्यान दिया है और योजना का 20 प्रतिशत पैसा इसके लिये रखा गया है । हमने जब उनसे यह प्रार्थना की कि चौपालें बननी तो शुरु हो गयी हैं लेकिन वे पूरी नहीं हुई है तो उसके लिये 84 लाख रुपये की राशि इसी वर्ष में दिये जाने का निश्चय किया गया है । एनवायरनमैंट इम्प्रूवमैंट के लिये एक करोड़ रुपये की राशि का प्लान में प्रोविजन किया गया है । इसमें एन छ आर ० ई ० पी ० से कुछ पैसा मिलाकर दो–पौने दो करोड़ रुपये की राशि बनाकर, यह कोशिश की जायेगी कि किसी भी हरिजन बस्ती की गलियां कच्ची न हों और उनका एनवायरनमैंट ठीक हो सके । इसके अलावा उनको पैरों पर खड़ा करने के लिये 35 प्रतिशत तक की सबसिडी देते. हैं ताकि ये अपना स्वयं का रोजगार कर सकें । पानीपत में मुख्य मंत्री जी ने बैकवर्ड क्लासिज के लिये जो घोषणा की है, वह एक ऐतिहासिक कदम है । उनका पंचायत में मैम्बर, ब्लाक समिति में मैम्बर और

नम्बरदार बनाने के लिये जो कानून में आवश्यक परिवर्तन करना था, वह भी हम करने जा रहे हैं । जैसे हरिजन भाइयों को चौपाल बनाने के लिये पैसे की सुविधा मिलती है, इसी प्रकार हुस बजट में फाइनैस मिनिस्टर ने बैकवर्ड कलासिज के लिए भी चौपालें बनाने के लिए पैसे का प्रोविजन रखा है । एक दो सुझाव मेरे कुछ भाइयों ने दिये हैं जिनमें मुख्य तौर पर यह कहा गया है कि शड्यूल्ड कास्ट का सर्टीफिकेट साल में पढ़ाई के दौरान केवल एक बार लेना चाहिये । स्पीकर साहब, हमारी कुछ स्कीमें हैं जो शैक्षणिक संस्थाओं को दी जाने वाली रियायतों की हैं, इनको ऐजूकेशन वि भाग इम्पलीमैंट करता है । हमारी यह कोशिश होगी कि उनके साथ मिलकर इस समस्या का हल किया जाये । जैसे पैशन के तरीके को बदला है और प्रोसीजर को बिल्कूल सिम्पलीफाई किया है । अब डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर से आगे कहीं पर जाने की जरूरत नही पड़ेगी । इसी तरह से मैं यह इन्शोयर करूंगी कि बच्चे को एक स्कूल में दूसरी बार शड्यूल्ड कास्ट का सर्टीफिकेट न देना पड़े । इसके अलावा जो सुविधायें उनको सरकार ने दी हुई हें, वे भी ठीक टाईम पर मिलें । कालेज के बच्चों को भी हर तीसरे महीने वजीफा मिल जाये ताकि उनको अपनी पढ़ाई बीच में न छोड़नी पड़े । इससे साफ जाहिर है कि सरकार का इस बात की तरफ पूरा ध्यान है कि समाज के जो कमजोर वर्ग है, या जो हमारे पिछड़े हुए भाई हैं, उनकी तरक्की के लिये हम ज्यादा से ज्यादा सुविधायें दें । आवश्यकता इस बात की है कि हम सारी स्कीमों को समझें और आज इस बात की भी

अत्यन्त आवश्यकता है कि सरकार स्थिर हो और प्रदेश में शान्ति हो, तभी गरीबों के कामों की तरफ ध्यान दिया जा सकता है । अगर सरकार ही स्थिर न हो और शान्ति का वातावरण ही न हो तो गरीब आदमियों के भले में रुकावट आती है । मैं सभी माननीय. सदस्यों से और हरियाणा के लोगों से यह कहना चाहूंगी कि. कांग्रेस सरकार ने हमेशा सभी–वर्गो की तरफ ध्यान दिया है और कमजोर वर्ग को आगे बढ़ाने की चेष्टा की है । चौधरी बंसी लाल जी का एक निशाना है कि 21 वीं सदी में अगर कोई प्रदेश मौडल बने तो वह हरियाणा बने । इनका ध्यान जहां दूसरे वर्ग के लोगों की तरफ है, वहां कमजोर वर्ग के भाइयों को जो हमेशा पीछे रहे हैं, उनको कैसे आगे लाया जाये । इस तरफ भी है । श्रीमती इंदिरा गांधी का ध्यान जहां तक था, उससे यूक कदम आगे राजीव गांधी जी गये है । हमें यह कहते हुए गर्व– और खुशी होती है कि जींद जलसे में जब वे आये तो जलेसे से निपटते ही स्वयं कार चलाकर वे गांव भीक्खेवाला में गये । उन्होंने अपनी कार हरिजन बस्ती के आगे खड़ी कर दी । यह देखने के लिये कि वहां पर कितना काम हुआ है? इसी तरह से वे आदिवासियों के बीच में और दूसरी जगहों पर जाते हैं । हमारे सब के ऊपर उनका एक ऐसा कन्ट्रोल है कि हम खुद ही ज्यादा से ज्यादा इस बात के लिये एलर्ट रहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा काम गरीबों के लिये करें । इन शब्दों के साथ मैं यह कहूंगी कि माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं, उनका हम पूरा ध्यान. रखेंगे और देखेंगे कि प्रोसीजर्ज को सिम्पलीफाई किया जाये ।

अन्त में मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करती हूं क्योंकि आपने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया ।

**वित्त मंत्री (चौधरी कटार सिंह छोकर ) :** अध्यक्ष महोदय, बजट अनुमानों पर दो दिन तक सदन में चर्चा हुई । माननीय सदस्यों ने आम तौर पर बजट अनुमानों का समर्थन भी किया और सराहना भी की । मैं सभी साथियों का सरकार की ओर से आभारी हूं कि उन्होंने उचित बात की और बजट को एप्रीशियेट किया है । उन्होंने कुछ बातें अपने क्षेत्र के लिये मांग के रूप में इस सदन में कहीं हैं और रखी हैं । मैंने इस बात की कोशिश की है कि विभाग से ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेकर उनका जवाब देने की कोशिश करूं लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जो रह जायेगी । उनके बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि विभाग को नोट करा दिया गया है और जिन विभागों से वे सम्बन्धित हैं उनके द्वारा उचित कार्यवाही उन पर की जायेगी । मुख्य तौर पर सदन में परम्परागत तरीके से अपोजीशन के आनरेबल मैम्बर हमारे साथी लछमन सिंह जी ने डिबेट शुरु की थी । उन्होंने भी अपने क्षेत्र की बहुत सी बातें सदन के सामने रखी हैं । उसमें उन्होंने भी एक मांग की । मैं समझता हूं कि उनकी बहुत ही अच्छी मांग हए कि एस० वाई० एल० पर जो काम हो रहा है, उसकी देख रेख के लिये ताकि उसकी क्वालिटी ठीक हो, उस पर स्टैडर्ड का काम हो, उसके लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं? उसके बारे में मैं उनको यह बताना चाहूंगा कि

हरियाणा सरकार ने अगस्त, 1986 में पंजाब सरकार को इस बारे मे लिखा था और पंजाब सरकार का जवाब मिला है कि उन्होंने एक खास अधिकारी. जो चीफ इंजीनियर के रैक का है, केवल इस काम के लिये नियुक्त किया हुआ है कि वह इम प्रोजैक्ट की क्वालिटी देखे और क्वालिटी गिरने न दे । हमें उम्मीद है कि सी ० डब्ल्यू ० सी ० यानी सैट्रल वाटर कमीशन जिसकी देख रेख में यह प्रोजैक्ट चल रहा है, वह इसकी समय समय पर मौनिटरिंग करता है । यह संतोष– जनक वात है और उमकी क्वालिटी ठीक रहेगी । उन्होंने एक दूसरी बात अपने क्षेत्र के बारे में की कि कालका और ताजेवाला के बीच में अर्दन डैम्ज बनाने की कोई स्कीम है उसके लिए हरियाणा सरकार ने आने वाले साल में क्या प्रोविजन रखा है 'ई मैं उनको यह बताना चाहूंगा कि इस क्षेत्र में अर्दन डैम्ज पहले ही 200 से ज्यादा लग चुके हैं । जहां पर भी ये जगह बतायेंगे वहां विभाग देखेगा । यदि जरूरत हुई तो वहां पर और भी बनाये जा सकते है । फिलहाल ताजेवाला पर एक बहुत बड़ा हथिनीकुंड बैराज हैँ, वह बना रहे है । यह बहुत बड़ा प्रोजैक्ट है । पहरने यू ० पी ० से कुछ झगड़ा था, वह तकरीबन सौर्ट–आउट हो चुका है । यह 48 करोड़ रुपये की लागत का प्रोजैक्ट है और इस पर जल्दी ही काम शुरु होगा । स्पीकर साहब, एक साथी –ने कहा कि लाइनिंग में जो कमी रह जातीं है या लाइनिंग टूट जाती है उनकी देखरेख के लिए क्या कोई प्रबन्ध है? स्पीकर साहब, मैं सदन को बताना चाहता हू कि मैंटिनैस डिविजन हर जगह है और जहां कमी रह जाती है वह मैनटेन

करते है । पहले ऐसी व्यवस्था नही ,थी लेकिन उन्होंने कहा है कि लाइनिग को मैनटेन करने का प्राय–बान किया जाए, स्पीकर साहब वह कर दिया गया है । दूसरी बात उन्होंने यह कही कि जो दादूपुर नलवी प्रोजैक्ट है उसकी क्या स्थिति है ? अध्यक्ष महोदय, इसका ऐस्टिमेट 1985 में बनाया गया था और अब इसकी कुल लागत काफी बढ़ गई हे । करीब 28 करोड़ 88 लाख रुपए का यह प्रोजैक्ट है और जब 1985 में इसका एस्टीमेट बनाया गया था तो 15 करोड. 37 लाख रुपए का था । 'वर्ष 1986–87 में इसके लिए एक करोड रुपया रखा गया था लेकिन मदन में इरिगेशन एंड पावर मिनिस्टर ने बताया थी कि वह रुपया खर्च नही हो सका क्योंकि लैड ऐक्वीजिशन की कार्यवाही नही हो संकी । स्पीकर साहब, अगरने मील डेढ़ करोड़. रुपया प्रोवाइड किया गया है ।

**श्री अध्यक्ष :** सवाल यह है कि जो रुपया रखा गया है वह लगेगा या नहीं लगेगा या वापिसे ही 'भेज दिया जाएगा?

**चौधरी कटार सिंह छोकर :** अध्यक्ष महोदय, इसी चालू पंचवर्षीय योजना में जिसके दो साल चले गए है इसको पूरा करने का यत्न करेंगे । सरदार लछमन सिंह ने बोलते वक्त एक बहुत ही सरल बात कही कि जो कड़े पहनते हैं उन पर सेल्ज टैक्स की छूट दी जाए । सरदार जी कड़े के बारे में पर्टिकुलर थे । इनकी बात को ध्यान में रखते हुए मैं सदन को बताना चाहता हूं कि कड़ा भी चूड़ियों में शामिल है और उन पर कोई टैक्स नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय, चूड़ियों पर जो टैक्स माफ्ह किया है इसे लोगों ने और खासकर बहनों ने बड़ा हेल किया है । अब ये बहुत सस्ती हो गई हैं लेकिन सोने के कड़े इसमें शामिल नहीं हैं ।

स्पीकर साहब, ठाकुर बहादुर सिंह ने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि ट्यूबवैल्ज की मोटरों पर से टैक्स माफ किया जाए । मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि ऐग्रीकल्चर के लिए जो पम्पिंग सैट इस्तेमाल होते हैं उन पर दस हार्स पावर तक के पम्पिंग सैटों पर सेल्ज टैक्स माफ है । इसका ऐलान इसी सदन में कुछ दिन पहले किया गया था । अगर कोई दिक्कत है तो फिर बताएं ।

स्पीकर साहब, पशुओं के लिए जो खली काम आती है उस पर सेल्ज टैक्स माफ करने की मांग की गई । स्पीकर साहब, इस पर विचार किया गया लेकिन इसमें फाइनैंशियल इम्पलीकेशंज हैं इसलिए इस पर टैक्स माफ करना उचित नहीं समझा गया ।

स्पीकर साहब, सड़कों के बारे में सरदार लछमन सिंह ने मांग की है कि कालका और नारायणगढ में जो सिंगल लिंक रोड्ज हैं उनको बनाने के लिए टौप प्रायरिटी दी जाए । इनकी माग है कि पांच साल के अन्दर इनको पूरा किया जाए । स्पीकर साहब, सरकार ने इस मद में जो पैसा रखा है वह काफी है । बहुत थोड़ी सड़के है जो बननी बाकी हैं । छोटी–छोटी ढानियां

कह सकते है या गढ़ी कह सकते हैं ऐसी जगहों पर सड़क बनाने के लिए करीब पांच करोड़ रुपया रखा गया है ।

**श्री लछमन सिंह :** स्पीकर साहब, कालका हल्के में कोट फतेह सिंह कोट भोला और डकरोग जगह हैं जहां पर सड़क बनाने पर सत्तर लाख रुपया खर्च आएगा । ये काफी लम्बी लिंक रोड्ज हैं ।

**चौधरी कटार सिंह छोकर :** यह ठीक बात है । इन पर लम्बे पुल बनाने पड़ते हैं । इतना खर्चा नहीं हो सकता । स्पीकर साहब, सारी स्टेट में बहुत थोड़ी –सी जगह हैं जहां पर सड़क बननी हैं । इस वक्त सरकार की नीति. है, कि. प्लेन एरिया में हैमलैटस हैं, गांव हैं जहां की आबादी 250 है और हिली एरिया में, जहां की आबादी 150 है वहां पर सड़क दी जाए । जहां सड़क छोटी हैं और पुल बहुत – बड़े बनने हैं उन पर बहुत रुपया खर्च होगा । सरकार ने पांच करोड़ रुपया वर्ष 1987– 88 के लिए सड़कों के मद में रखा है। इसमें करीब दो सौ किलोमीटर सड़क बना पाएंगे और, दो सौ किलोमीटर के करीब ही चौंडा कर 'पाएंगे ।

स्पीकर साहब, यहां पर यह पूछा गया कि वाटर सप्लाई की मैंटिनैंस के लिए, उसको चालू रखने के लिए खर्च का प्रावधान किया गया है या नहीं । मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि काफी पैसा इसके लिए रखा जाता है । मैंटिनैसं के लिए करीब

सातू आठ करोड़ रुपया हर सात्र रखते हैं । देहात में जो वाटर सप्लाई है उसके लिए रुपया रखा जाता है । हरियाणा में 81 म्यूनिसिपल टाउंज हैं और 54 म्यूनिसिपल टाउंज में पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट वाटर सप्लाई स्कीम्ज चलाता है और दो करोड़ रुपया उसकी मैटिनैसं पर खर्च आता है ।

## बैठक का समय बढ़ाना

**श्री अध्यक्ष :** आपको कितना समय और चाहिए?

**चौधरी कटार सिंह छोकर :** स्पीकर साहब, अभी तो मैंने शुरू ही किया है । कम से कम पन्द्रह मिनट तो चाहिए ।

**श्री अध्यक्ष :** यदि हाउस सहमत हो तो बैठक का समय पन्द्रह मिनट के लिए बढा दिया जाए ।

**आवाजें :** ठीक है जी ।

**श्री अध्यक्ष :** बैठक का समय 15 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है ।

## वर्ष 1987– 88 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ )

**चौधरी कटार सिंह छोकर :** स्पीकर साहब, यहां यह भी कहा गया कि जो छोटी म्यूनिसिपल कमेटीज हैं या गांव हैं जहां पर सैपरेट वाटर सप्लाई स्कीम्ज शुरू कीं गई हैं लेकिन बिजली न आने की वजह से पानी की सुविधा नही मिलती । इसके लिए क्या

कोई जनरेटर्ज या फीडर्ज का प्रोविजन सरकार करने जा रही है? स्पीकर साहब, मैं कहना चाहता हूं कि इस सिलसिले में सरकार ने जैनरेटिंग सैट्स और इंडिपैंडेन्ट फीडर्ज का प्रोविजन किया है और इन पर इस वक्त अन्दाजा यह है कि दस–बारह करोड़ रुपए खर्च होंगे । करीब 1 करोड़ 70 लाख रुपया पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट ने बिजली बोर्ड को इंडिपैडेन्ट फीडर्ज और जैनरेटर्ज के लिए दिया है । इसमें से बीस जैनरेटर्ज खरीदे जा चुके है और चार जगह इंडिपैडैन्ट फीडर्ज के लिए इलैक्ट्रिक लाइन्ज लगाई जा चुकी हैं जिससे 125 गांवों को लाभ होना शुरू हो गया है।

स्पीकर साहब, सैनी साहब ने कुरुक्षेत्र के बारे में कहा कि औगमैन्टेशन ट्यूबवैल्ज की वजह से वहां पीने के पानी का लैवल नीचे चला जाता है जिसको पब्लिक हैल्थ विभाग सप्लाई करता है । स्पीकर साहब, इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन गांवों में वाटर टेबल नीचे चला गया है उसमें सरकार की नीति है कि वहां पर पीने का पानी उपलब्ध करायंगे । स्पीकर साहब, कुरुक्षेत्र जिले के बारे में, मैं बताना चाहता हूं । यह आपका जिला भी है । सिक्सथ फाइव ईयर प्लान में वहां केवल 52 गांवरू. प्रौब्लम विलेजिज थे 1985 में हमने वहां पर दोबारा सर्वे करवाया तो उस में 257 गांव और प्रौब्लम विलेजिज पाए गये । समस्या तो काफी गम्भीर है । 723 गांवों में से 257 गांव और प्रौब्लम विलेजिज पाए गये लेकिन अब 'इसके लिये उचित उपाय किये गये है । हमने 1986 में भी इस बात का सर्वे कर–गया ।

65 प्रौब्लम विलेजिज और बढ़ गये । इस प्रकार टोटल 374 गांव प्राब्लम विजेजिज हैं, 322 गांव नए और 52 गांव पिछले, जिन को पीने के पानी दैने की सुविधा प्रदान कर रहे हैं । इस तरह से इस वक्त 374 गांव कुरूक्षेत्र जिले के वाटर ,सप्लाई स्कीमज के तहत कवर कर लिये गये हैं । हर प्रकार से इस प्रौब्लम का समाधान किया गया है और किया जा रहा है । आशा है कि 1990 तक सारे गांव कवर कर लिये जाएंगे ।

इसी तरह से, अध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य की तरफ से सदन में एक मांग हुई है कि जो अधिकारी कोआपरेटिव विभाग का बकाया कर्जा लोगों से लेने जाते हैं वे उन लोगों को कर्जा न देने की हालत में जुडिशियल लौक अप में बन्द कर देते हैं ।

**श्री लछमन सिंह :** स्पीकर साहब, मेरा कहने का मतलब यह था कि उन लोगों को जुडिशियल लौक अप में न रख कर, ट्रायल बेसिज पर परसुएड करके बाजी वसूल किया जाए तो बेहतर होगा । यह देखा जाए कि ऐसा करने से उसका क्या रिजल्ट निकलता है ।

**चौधरी कटार सिंह छोकर :** ठीक है, स्पीकर साहब, हम इसको ऐग्कामिन करवा लेंगे और इस बारे में जो कुछ उचित हो सकता होगा, उस पर अवश्य गौर करेंगे ।

इसके साथ साथ एक और मांग की गयी कि यमुनानगर में एक थर्मल प्लांट लगाया जाए । मैं यहां हाउस में यह बताना चाहता हूं कि इस वक्त पानीपत में हमारा एक यूनिट 110 मैगावाट का आरम्भ किया गया है जिसका काम 1987–88 में पूरा होने की सम्भावना है । इसके इलावा यमुनानगर में भी एक थर्मल प्लांट लगा रहे हैं जिसमें दो यूनिट्स 210–210 मेगावाट के होंगे । इनकी क्लीयरैन्स हमें भारत सरकार से मिल चुकी है । जमीन ऐक्वायर कर ली गयी है । इस पर 1987–88 में काम आरम्भ करने का इरादा है । इसके साथ साथ– एक बात और भी यहां माननीय सदस्यों ने कही कि थर्मल प्लांट्स को जो कोल सप्लाई किया जाता है, वह घटिया क्वालिटी का होता है जिससे काफी परेशानी होती है । इसके लिए बिजली बोर्ड ने काफी उपाय किये हैं और हम कोल इंडिया से ऐग्रीमैन्ट भी कर रहे हैं ताकि ऐसी स्थिति आगे पैदा न हो । इस बात का भी प्रबन्ध किया जा रहा है कि कोयला डैस्टीनेशन तक ठीक ही पहुंचे ।

श्री साहब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र और शाहबाद में 220 के० वी ० सब–स्टेशन की बात कही है कि वहां पर बना रहे हैं कि नही? मैं यह जानकारों देना 'चाहता हूं कि यह फाईनल हो चुका है । साईट इसके लिये सिलैक्ट की जा रही है और काम उस पर तुरन्त आरम्भ कर दिया जाएगा । 1987–8 8 में यह काम शुरु होगा । आशा है यह काम 1990 तक पूरा हो जाएगा । इसी तरह की पोजीशन पिपली और शाह बाद में भी है ।

सरदार लछमन सिंह जी ने एक बड़ी हाईमोथैटिकल्न बात कह दी कि अगर चण्डीगढ हरियाणा को छोड़ना ही पड़ा तो टेम्पोरेरीली हरियाणा की कैपिटल पंचकूला में शिफ्ट कर दी जाए तो बेहतर रहेगा । मैं उनको बताना चाहता हूं कि यह बात तो अकार्ड में भी है कि जब तक हमारी कैपीटल बनकर तैयार न हो जाए तब तक हम चण्डीगढ में ही रह सकते हैं । इसलिये पंचकूला में इंटेरम और टेम्पोरेरी शिफ्ट करने की कोई सम्भावना नही है ।

इसी तरह से हमारे दूसरे साथी श्री इन्द्र सिंह नैन ने यह कह दिया कि कैपिटल के लिये हिसार बेहतर रहेगा । उन्होंने कहा कि जब तक कैपिटल का फैसला नहीं हो जाता तब तक हिसार में कैपिटल शिफ्ट कर दी जाए । यह तो इफ एण्ड बट्स वाल बात हो गयी । जब समय आएगा तो इस पर भी विचार कर लिया जाएगा । स्पीकर साहब, हमारे मुख्य मन्त्री जी कह चुके हैं और सब को पता भी है कि यह सारे प्रदेश की समस्या बनी हुई है और लोग यह चाहते हैं कि राजधानी प्रदेश के बीच में होनी चाहिये । तो स्पीकर साहब, आपका और हमारा इलाका ही बीच का पड़ता है । कुरुक्षेत्र और करनाल का इलाका ही हो सकता है ।

स्पीकर साहब, यहां कई साथियों ने बोलते हुए फोर्थ पे कमिशन की सिफारिशों पर भी अपने विचार रखे और इस बात के लिये सरकार की सराहना भी की कि सरकार ने केन्द्र सरकार की फोर्थ पे कमिशन की सारी की सारी सिफारिशों को मान लिया है

। इसके आगे इस बात– पर भी जोर दिया गया कि इन को जल्द से जल्द लागू किया जाए । इस महीने के अन्दर यह रिपोर्ट आ जाएगी और अगले महीने की पहली तारीख को हम कर्मचारियों को कैश के रूप में बढ़ी हुई दरें देना चाहते हैं और जितनी भी जल्दी हो सके, इस पर कार्यवाही की जाएगी । मैं हाउस को अश्योर करता हूं कि इस काम में ढील नहीं. की जाएगी । कोई मजबूरी हो सकती है, यह दूसरी बात है ।

स्पीकर साहब, सरदार लछमन सिंह जी ने अपने इलाके की काफी दिक्कतों को यहां पर रखा है कि लोगों को काफी परेशानियां हैं । खासतौर पर उन्होंने पंचकूला का भी जिक्र किया है कि आप पंचकुला की तरक्की के लिये क्या कर रहे हो? वहां डिऐवैल्पमैन्ट न होने की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है । स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से उनको यह बताना चाहता हूं–

**श्री अध्यक्ष :** चौधरी साहब, आप अकेले उनकी बात का जवाब नहीं दे रहे, आप सारी अपोजीशन को जवाब दे रहे हैं ।

**श्री लछमन सिंह :** धन्यवाद आपका स्पीकर साहब ।

**चौधरी कटार सिंह छोकर :** स्पीकर साहब, मैं इनको आंकड़े ही बता देता हूं । रोडज के लिये आगे वाले साल में हमने 97 लाख रुपया रखा है । वाटर सप्लाई स्कीमज के लिये 130 लाख, सीवरेज के लिये 102 लाख और पब्लिक न्हैएथ मेंटिनैमं के

लिये कुल 75 लाख रुपया रखा गया है । लगभग 4 करोड़ 3 लाख रुपया हमने इनके हल्के के लिये रिजर्व रखा है' । इससे पंचकूला के लोगों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा । लोगों को हर प्रकार की सुख सुविधा मिलेगी । सरदार लछमन सिंह जी इसका क्रैडिट ले सकते हैं ।

इसी प्रकार से महेन्द्र प्रताप सिंह जी ने कहा कि जिन लोगों की जमीनें ऐक्वायर हो जाती हैं उनको प्लाट देने की सरकार की कोई पालिसी है कि नही? अगर हुड्डा 500 सक्वेअर यार्डज तक जमीन ऐक्वायर करता है तो छोटे छोटे प्लाट्स, 100 गज से 350 गज तक के, हरिजनों और गरीब लोगों को देने का प्रोविजन है और रेट्स जगह जगह पर निर्भर करते हैं । इसके अलावा उन्होंने एक और बात कही कि झुग्गी झोपड़ियों वालों की ,तादाद बढ़ती जा रही है । हर साल लगभग 30 हजार के करीब फरीदाबाद में लोग इकट्ठे हो जाते हैं क्या ऐसे लोगों के लिये भी सरकार के पास पक्की जगह देने का कोई प्रावधान है? सरकार की यह योजना है कि उनको धीरे–धीरे शिफ्ट किया जाए । जब हुड्डा किसी किस्म की स्कीम बनाता है तो लो इन्कम ग्रुप्स वालों के लिये प्लाट्स रिजर्व रखे जाते हैं । हम कोशिश करेंगे कि सरकार की इस नीति से ऐसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो । जनाब, यहां पर सरदार लछमन सिंह जी ने मांग की कि पंचकूला में एक बड़ा हस्पताल बनाया जाए । स्पीकर साहब, वहां पर तीन डिस्पैंसरीज काम कर रही हैं जो काफी जरूरत को पूरा

कर रही हैं । इसके अलावा पंचकूला के नजदीक चण्डीगढ है जहां पर बहुत बड़े बड़े हस्पताल हैं । इसलिये अभी पंचकूला में बहुत वडा हस्पताल बनाने की योजना नहीं है । श्री. महेन्द्र प्रताप सिंह जी ने भी फरीदाबाद में 800 बैड का हस्पताल बनाने की बात कही । वहां पर 200 बैड का हस्पताल पहले से ही है और कई प्राइवेट हस्पताल भी हैं । कम्यूनिटी हैल्थ लैटर की नैन साहब ने मांग की कि बरवाला में खोला जाए । मैं उनको बताना चाहता हूं कि इसी सातवीं योजना में एक कम्यूनिटी हैल्थ सैटर बरवाला में बनाया जाएगा । श्री साहब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र की बातें कहीं । उन्होंने जय प्रकाश नारायण हस्पताले के बारे में कहा कि उसमें क्वार्टर नही कुंए । वहां पर जरूरत के मुताबिक क्वार्टर हैं । उन्होंने आयुर्वेदिक कालेज के बारे में भी कहा था । उसके लिए स्कीम बनाई जा रही है और उस पर फेज्ड मैनर में काम होगा । उसके लिए 4० एकड़ जमीन दे दी गई हए और 6 लाख 40 हजार रुपए भी मंजूर हो चुके हैं । उसका प्लान बनाया जा रहा एं । नर्मिंग कोर्स के लिए अभी कुरुक्षेत्र में कोई स्कीम विचाराधीन नहीं है क्योंकि करनाल में यह सुविधा है जोकि कुरूक्षेत्र के नजदीक ही है । महेन्द्र प्रताप सिंह जी चाहते हैं कि फरीदाबाद में गर्ल्ज कालेज के विंग को पूरा कालेज बनाया जाए । सरकार इसकी परफारमैस देख रही है, अगर यह कामयाब रहा तो इसे पूरा कालेज जरूर बनाया जाएगा । नैन साहब ने कहा कि स्कूलों में धार्मिक शिक्षा की नीति अपनानी चाहिए । मैं उनको बताना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश में स्कूलों में हफ्ते में दो पीरियड नैतिक शिक्षा के लगाये

जाते हैं । इस तरफ सरकार का पहले ही पूरा ध्यान है और मौरल ऐजूकेशन का प्रबन्ध है । एक बात नैन साहब ने स्पोर्टस को ऐजूकेशन का सब्जैक्ट बनाने के बारे में कही । ऐसी बात अभी सरकार के विचाराधीन नहीं है । वैसे स्पोर्टस की तरफ सरकार का पूरा ध्यान है, जगह जगह पर स्टेडियम बनाए जा रहे हैं । सैनी साहब ने कहा कि उनके हल्के में स्कूलों का दर्जा बढ़ाया जाए । इस बारे में सदन में बार बार बताया जाता है कि इसके लिए कुछ नौर्म्ज बने हुए हैं उसके हिसाब से आने वारने साल में स्कूलों को अपग्रेड करने का प्रोविजन किया गया है । ऐनीमल हस्बैडरीं के बारे में भी यहां पर कुछ मांगें रखी गई । महेन्द्र प्रताप सिंह, बहादुर सिंह तथा और भी कई साथियों ने इस बारे में मांगे रखीं । एक साथी ने कहा कि हसनगढ में हस्पताल बनाया जाए ।

## बैठक का समय बढ़ाना

**श्री अध्यक्ष :** आप कितनी देर और बोलना चाहते हैं?

**चौधरी कटार सिंह छोकर :** मैं कम से कम 15 मिनट और बोलूंगा ।

**श्री अध्यक्ष :** यदि हाउस सहमत हो तो बैठक का समय 15 मिनट के लिए और बड़ा दिया जाए ।

**आवाजें :** ठीक है जी ।

**श्री अध्यक्ष :** बैठक का समय 15 मिनट के लिए और बढ़ाया जाता है ।

## वाई 1987– 88 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ )

**चौधरी कटार सिंह छोकर :** स्पीकर साहब, हसनगढ में फुल फलैज्ड हस्पताल मंजूर कर दिया गया है । बाकी जो मांगे हैं उन पर भी गौर किया जा रहा है । इसी तरह से यहां पर थानेसर और बरवाला में बस स्टैड बनाने की मांग आई । इन दोनों जगहों पर अगले साल में बस स्टैड बनाने की योजना है और काम शुरु कर दिया जाएगा । एक मांग और यहां आई कि थानेसर और शाहबाद में इंडस्ट्रीज के लिए रियायत दी जाए । स्पीकर साहब, इंडस्टरी के लिए जो हमारी जनरल कंडीशज है वह इन दोनों जगहों पर भी लागू होती है । थानेसर और शाहबाद में कोई विशेष छूट देने का सरकार का इरादा नहीं है । वैसे हाउस में भी इस बारे में क्राइटेरिया बार बार बताया जा चुका है । अध्यक्ष महोदय, यहां पर डब्ल लिंकस की बहुत बातें कहीं गई । अभी डब्ल लिंकस देने का हमारा कोई इरादा नही है लेकिन जहां पर बहुत जरूरी हो वहां ऐग्जामिन भी किया जा सकता है । एक बात यहां पर यह कही गई कि लैड रैवेन्यू चूंकि खत्म हो चुका है इसलिये क्या अब नम्बरदारों को रखा जाएगा या नहीं? नम्बरदार को और भी बहुत से काम होते हैं । वह आबपाशी का पैसा कलैक्ट करता है और बहुत सी वैरिफिकेशंज भी करता है । इसलिये सरकार का इस पद को खत्म करने का इरादा नहीं है ।

इसके अलावा यहां पर और भी बहुत सी छोटी छोटी बातें कहीं गई उनके बारे में मैं संक्षेप में बताना चाहता हूं कि इन सारी बातों का ध्यान रखा जाएगा । रोडज के लिए कहा गया कि 5 करोड़ रुपया बहुत कम रखा गया है । मैं माननीय सदस्यों को– बताना चाहता हूं किं रोडज के लिए 16 करोड़ रुपया रखा गया है । पांच करोड़ रुपया तो सिर्फ नए लिंक रोडज बनाने के लिए है । हुक्म सिंह जी ने साल्हावास में वैटरिनरी हस्पताल बनाने के लिए कहा । स्पीकर साहब, वहां पर आलरेडी हस्पताल एग्जिस्ट करता है, और बनाने की जरूरत नहीं है । पिपल साहब ने आई० टी ० आईज० की मांग की है । सातवीं योजना में प्लानिंग कमिशन ने आई० टी ० आईज० बनाने की इजाजत नहीं दी है इसलिये यह काम मुश्किल होगा । आर्य साहब ने पूछा कि 198 7–8 8 में यमुना नदी पर प्रोटैक्शन बांध बनाने के लिए कोई पैसा रखा गया है या नहीं । इसके लिए हमने आने वाले साल में करीब 70 लाख रुपया रखा है । इस काम पर दिसम्बर, 1986 तक 34 लाख रुपया खर्च किया जा चुका है । अगले साल का. पैसा इससे अलग है । आर्य साहब ने यह भी कहा कि रैसलर्ज की सिलैक्शन ठीक नहीं होती । इसके लिए तो एक रैसलिंग ऐसोसिएशन बनी हुई है, सिलैक्शन का काम उसका है । आर्य साहब अपनी बात उनको कह सकते हैं । अगर वे स्टेट से कोई मदद लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं । यहां पर टूर्नामैंटस आर्गेनाइज करने की भी बात कही गई । ऐसे टूर्नामैंट तो देहात में हम पहले ही आर्गेनाइज करते हैं । हैल्थ के बारे में बोलते हुए कहा गया कि छछरौली में बच्चों का

विशेषज्ञ, डाक्टर नहीं है । छछरौली में पी० एच० सी० हे । पी० एच० सी० में हम एक मेल और एक फीमेल डाक्टर भेजते हैं । यमुनानगर में एक आर्थोपैडिक डाक्टर की मांग की गई । वहां पर हमने डा० महावीर गोयल को लगाया हुआ है । भले राम जी ने मांग की कि जो बच्चों को स्कौलरशिप देते हैं उनकी वैरिफिकेशन को सरल किया जाए । इस पर विचार किया जाएगा । हेल स्टौर्म के बारे में भी यहां जिक्र आया । इस बारे में एक कैबिनिट सब–कमेटी बनाई हुई है । इस बारे में व्यापक तरीके से सरकार का मदद करने का प्रोग्राम है ।

स्पीकर साहब, यहां पर चौधरी भले राम जी ने कहा कि मशरूम ग्रोवर्ज को अधिक से अधिक प्रोत्साहन मिलना चाहिए । मैं उनको बताना चाहूंगा कि डी ० आर० डी ० ए० सोनीपत ने इसके लिए एक स्पैशल स्कीम बनाई है जो लोगों को बैंकों से ऋण दिलवाने के लिए मदद करेगी । इसके अलावा सरकारी तौर पर ''नैफेड'' ने इस साल से खरीद भी शुरु कर दी है ।

इसी प्रकार से चौधरी हुक्म सिंह जी ने भी झांसवा माईनर के बारे में यहां पर जिक्र किया था । मैं इनको बताना चाहूंगा कि अभी तक उस की पूरी जमीन ऐक्वायर नही हुई थी । इस माईनर का काम 1983 में शुरु किया गया था लेकिन बाद में फण्डज न होने की वजह से बीच में ही इस काम को अधूरा छोड़ दिया था । अब सरकार ने इस माईनर को टेकअप किया है और इसको जल्दी ही पूरा करने की योजना है । जिन लोगों की जमीन

ली जा चुकी है या ली जायेगी उनको कम्पनसेशन भी दे देंगे । बहिन शान्ति जी ने तो करैक्टर की ही बातों पर अधिक जोर दिया है । मैं इनको बताना चाहूंगा कि स्कूलों में दो पीरियड पहले ही इस विषय के लगा दिए गए हैं । वर्ष 1987–88 के दौरान 94 विद्यालय भवन और 18 रिहायशी क्वार्टर पूरे – करने के लिए 160 लाख रुपये की व्यवस्था की है । इसके अलावा दूसरी मद से भी शिक्षा पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है । शिक्षा का हमारा कुल मिला कर बहुत ज्यादा खर्च बैठ जाता है । यह सरकार के ऊपर सबसे बड़ा बोझ है ।

अध्यक्ष महोदय, मोहन लाल जी ने कहा कि रिवाडी में ओवर ब्रिज बनाया जाना चाहिए । मैं इन्हें बताना चाहूंगा कि यह केस अगस्त, 1986 में भारत सरकार कौ भेजा जा चुका है इस पर 2 करोड़ रुपये से अधिक खर्च होने का ऐस्टिमेट है । इस ब्रिज के लिए रेलवे वालों की और हमारी अभी ज्वायंट इन्सपैक्शन होनी है । जब भारत सरकार इसकी कलियरैंस दे देगी तो उसके बाद इस पर विचार किया जायेगा और पैसा रखा जायेगा ।

**श्री मोहन लाल पीपल :** स्पीकर साहब, मैंने मेवात प्रोजैक्ट कैनाल का जिक्र किया था । उसका कोई जवाब वित्त मंत्री जीं की तरफ से नहीं आया है । वित्त मंत्री जो ने तकरीबन हर काम के लिए पैसा रखा है । यदि यह मेवात प्रोजैक्ट कैनाल बन जाती है तो इससे. तावडू और पटौदी का एरिया भी कवर हो जायेगा । गुडगावां शहर में जहां हुड्डा अपने सैक्टर्ज बसा रहा है,

वहां पर भी इस कैनाल का पानी पहुंचेगा । मैं वित्त मंत्री जी से आश्वासन चाहूंगा कि वे इस कैनाल के लिए भी कुछ करें ।

**सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी शमशीर सिंह सुरजेवाला ) :** स्पीकर साहब, वह प्रोजैक्ट तो आलरेडी है इस कैनाल को एस ० वाई ० गुल ० का पानी मिलना है । जब एस० वाई० एल ० कैनाल वन जायेगी तो इन कैनाल को भी पानी' मिलेगा ।

**चौधरी कटार सिंह छोकर :** स्पीकर साहब अन्त मे मैं अपने सभी साथियो का जिन्होंने अपने विचार रखे हैं, धन्यवाद करता हूं ।

**Mr. Speaker :** The House stands adjourned till 9.30 A. M. tomorrow, the 5th March, 1987.

**13.52 बजे**

(The Sabha then *adjourned till 9,30 A.M. on Thursday, the 5th March. 1987.)